जबलपुर बुधवार 02 सितंबर 2026 > शक संवत 1948, भाद्रपद कृष्ण पक्ष,षष्ठी
वर्ष 32 अंक 65 मूल्य ₹ 3.00 > पेज 12 > आर.एन.आई. पंजीयन नम्बर 64561/96
www.swatantramat.com

स्वतंत्र मत

अब हर
रोज दर्पण
3

मौसम
अधिकतम तापमान
29.1°C
न्यूनतम तापमान
23.5°C
सूर्योदय - 5.53 | सूर्यास्त - 6.27

स्वतंत्र मत में विज्ञापन देने के लिए 9589920250 पर कॉल करें * स्वतंत्र मत का अंक प्राप्त करने के लिए 9301359695 पर कॉल करें।

24 साल देश सेवा कर घर लौटे सेना के हवलदार... 4

रश्मिका मंदाना की ‘मैसा’ 27 नवंबर को होगी रिलीज... 7

महिलाओं को कृषि के साथ विविध आर्थिक गतिविधियों 8

नीट आंदोलन को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी राहत

पांच राज्यों में एफआईआर रद्द, 5 सितंबर का मार्च भी हुआ वापस

नई दिल्ली

नीट-यूजी पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ी राहत दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिले विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली समेत पांच राज्यों में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने का आदेश दिया। ये मामले 20 से 25 जुलाई के बीच हुए प्रदर्शनों से जुड़े थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली, असम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार में नीट प्रदर्शन से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर रद्द होंगी। दिल्ली पुलिस और संबंधित राज्य सरकारों ने भी इन मामलों को समाप्त करने के लिए अदालत से अनुच्छेद 142 के तहत हस्तक्षेप की मांग की थी। कोर्ट के फैसले से उन छात्रों और प्रदर्शनकारियों को राहत मिली है, जिन पर आंदोलन के दौरान मामले दर्ज किए गए थे।

आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मिलेगा मुआवजा

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की ओर से कहा कि प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत के दौरान दिए गए आश्वासन पर सरकार कायम है। उन्होंने बताया कि नीट प्रदर्शन के दौरान आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। केंद्र ने मुआवजे की प्रक्रिया तय करने के लिए तीन महीने का समय मांगा है। इसके लिए राज्य सरकारों और संबंधित पक्षों के साथ चर्चा की जाएगी। एफ आईआर रद्द करने के साथ ही कोर्ट ने 2873 ऐसे लोगों के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दी है, जिनके बारे में सरकार ने आपराधिक रिकॉर्ड होने की बात कही है। सुनवाई के दौरान वकील हरिहरन ने इन लोगों की सूची मांगी, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किन व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक इतिहास के आधार पर कार्रवाई प्रस्तावित है। यानी कोर्ट ने प्रदर्शन में शामिल सभी लोगों को एक समान राहत नहीं दी है।

पांच सितंबर का प्रस्तावित मार्च वापस

सुप्रीम कोर्ट के आदेश और केंद्र के सकारात्मक आश्वासन के बाद सीजेपी ने पांच सितंबर को प्रस्तावित मार्च वापस लेने का फैसला किया। संगठन के प्रवक्ता सौरव दास ने अदालत को इसकी जानकारी दी। मुख्य न्यायाधीश ने भी कहा कि दोनों पक्ष खुले मन से बातचीत करें और एक-दूसरे पर भरोसा रखें, तो कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। केंद्र ने भी बातचीत को सकारात्मक और रचनात्मक बताते हुए कहा कि सरकार और प्रदर्शनकारी एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि समाधान के लिए साथ काम करने वाले पक्ष हैं।

ममता बनर्जी की भतीजी फंदे से लटकी मिलीं

कलकत्ता । पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भतीजी ब्रिष्टी मुखर्जी मंगलवार को बीरभूम जिले के कुसुंबा गांव के घर में फंदे से लटकी मिलीं। ब्रिष्टि, ममता के चचेरे भाई और तृणमूल नेता निहार मुखर्जी की बेटी थीं। शुरुआती तौर पर माना जा रहा है कि उन्होंने सुसाइड किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ब्रिष्टि बोलपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थीं। शिक्षक भर्ती घोटाला सामने आने के बाद 2024 में उनकी जॉब चली गई थी। इसके बाद से ही वे डिप्रेशन में थीं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल, 2024 को अवैध रूप से प्राप्त सभी 25,753 नौकरियां रद्द कर दी थीं।

छिंदवाड़ा कॉलेज में दो छात्र गुट भिड़े, पुलिस से धक्का-मुक्की

छिंदवाड़ा। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफएक्सीलेंस मंगलवार को छात्र राजनीति के टकराव का केंद्र बन गया। एनएसयूआई की 17 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहे प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की हो गई। हंगामे में चार महिला पुलिसकर्मियों के घायल होने की जानकारी सामने आई। इनमें एक की तबीयत बिगड़ने पर उसे व्हीलचेयर से प्राचार्य कक्ष तक ले जाया गया। इसी दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं के कॉलेज परिसर में पहुंचने से विवाद और बढ़ गया।

सहारनपुर पंजाब नेशनल बैंक में 17 करोड़ के नकली नोट

सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पंजाब नेशनल बैंक की करेंसी चेस्ट में करीब 17 करोड़ रुपए के नकली नोट मिले हैं। बैंक ऑडिट के दौरान यह मामला सामने आया। इसके बाद मंगलवार सुबह 8 बजे आरबीआई के 6 अफसर दो गाड़ियों से पहुंचे। 4 घंटे से बैंक के अंदर हैं। सूत्रों के मुताबिक बैंक कर्मचारियों से पूछताछ कर रहे हैं। इस मामले में अब तक 3 अफसरों को सस्पेंड किया गया।

आरजीपीवी का पुनर्गठन, प्रदेश में बनेंगे 3 नए तकनीकी विश्वविद्यालय

मंत्रि-परिषद ने दी मंजूरी, जबलपुर विश्वविद्यालय के अधीन रहेंगे 4 संभागों के तकनीकी संस्थान

भोपाल (स्वतंत्र मत)

मध्यप्रदेश में तकनीकी शिक्षा के विस्तार और क्षेत्रीय संतुलन को मजबूत करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) का पुनर्गठन कर भोपाल, उज्जैन और जबलपुर में तीन नए प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने की स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही प्रदेश के सर्वांगीण विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए करीब 41 हजार करोड़ रुपये से अधिक के वित्तीय प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। नई व्यवस्था के तहत भोपाल स्थित वर्तमान विश्वविद्यालय को मध्य भारत प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालय, उज्जैन के स्वशासी इंजीनियरिंग कॉलेज को मालवा प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालय और जबलपुर के स्वशासी इंजीनियरिंग कॉलेज को महाकौशल प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया जाएगा। तीनों विश्वविद्यालयों के लिए अलग-अलग अधिनियम लागू किए जाएंगे।

जबलपुर के अधीन रीवा, सागर और शहडोल संभाग

रीवा, सागर और शहडोल संभाग के तकनीकी संस्थान जबलपुर के अधीन आएंगे। भोपाल विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में भोपाल, नर्मदापुरम, चंबल और ग्वालियर संभाग के तकनीकी संस्थान होंगे। उज्जैन विश्वविद्यालय के अंतर्गत उज्जैन और इंदौर संभाग तथा जबलपुर विश्वविद्यालय के अधीन जबलपुर, रीवा, सागर और शहडोल संभाग के तकनीकी संस्थान आएंगे। वर्तमान में आरजीपीवी के अंतर्गत 13 पाठ्यक्रमों में 585 संस्थानों के तीन लाख 83 हजार से अधिक विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। नए विश्वविद्यालय बनने से तकनीकी शिक्षा के प्रशासन, संसाधनों और संस्थानों का क्षेत्रीय स्तर पर बेहतर प्रबंधन हो सकेगा।

जबलपुर और उज्जैन में नए पदों को मंजूरी

उज्जैन और जबलपुर में स्थापित होने वाले दोनों नए विश्वविद्यालयों के प्रारंभिक प्रशासनिक संचालन के लिए कुलगुरु, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक, उप कुलसचिव और वित्त अधिकारी के पद स्वीकृत किए गए हैं। अन्य सहायक एवं तकनीकी पद नियमानुसार आउटसोर्स किए जाएंगे। दोनों विश्वविद्यालय स्व-वित्तीय आधार पर संचालित होंगे।

मूंग खरीदी की सीमा 60 प्रतिशत हुई

किसानों को राहत देते हुए पंजीकृत कृषकों से ग्रीष्मकालीन मूंग की उपज के उपार्जन की सीमा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत तक करने के निर्णय का भी अनुसमर्थन किया गया। इसके अलावा नए जिलों में सामाजिक न्याय और आयुष विभागों के कार्यालयों के संचालन के लिए नए पद सृजित करने को मंजूरी दी गई।

41 हजार करोड़ से अधिक के प्रस्ताव मंजूर

बैठक में ग्रामीण विकास के लिए वीबी जी राम जी योजना के तहत 29,619 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया गया। डेयरी विकास और सांची ब्रांड के उन्नयन के लिए 2,973 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। पश्चिम भोपाल बायपास के लिए 3,774 करोड़ रुपये तथा मेहलुआ-बीना-खिमलासा-मालथौन चार लेन मार्ग के लिए 3,272 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य संस्थानों में मशीन एवं उपकरणों के रखरखाव के लिए 488 करोड़ और विभागीय परिसंपत्तियों के संधारण के लिए करीब 916 करोड़ रुपये मंजूर हुए। इसके अलावा नवगठित जिलों में सामाजिक न्याय और आयुष विभाग के कार्यालयों के संचालन के लिए नए पदों को मंजूरी दी गई।

महाराष्ट्र में हर पांचवां वोटर ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर : राहुल

बोले- भाजपा की जीत के लिए लोकतंत्र से खिलवाड़

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन के बाद तैयार ड्राफ्ट मतदाता सूची को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को चुनाव आयोग और भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए आयोग को ‘वोट चोरी आयोग’ तक कह दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और चुनाव आयोग अपनी रणनीति बदलते रहते हैं और उनका उद्देश्य किसी भी कीमत पर भाजपा की जीत सुनिश्चित करना तथा लोकतंत्र को कमजोर करना है। एसआईआर के बाद महाराष्ट्र की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 2,06,88,487 मतदाताओं के नाम शामिल नहीं हो पाए हैं। यह संख्या राज्य के पिछले मतदाता आधार की करीब 21.14 प्रतिशत है।

अधिकारियों के अनुसार, इन मतदाताओं के एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं हो सके। इनमें ऐसे लोग शामिल हैं जो अपने पते पर नहीं मिले, घर बदल चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है या उनके नाम डुप्लीकेट पाए गए हैं। चुनाव अधिकारियों के मुताबिक, ड्राफ्ट सूची में अब 7.71 करोड़ से अधिक मतदाता हैं। इनमें करीब 3.95 करोड़ पुरुष, 3.75 करोड़ महिलाएं और 3,087 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। जिन पात्र मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं हैं, उन्हें 30 सितंबर तक दावा-आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया गया है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को जारी की जाएगी।

राहुल गांधी ने उठाए सवाल

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में महाराष्ट्र के साथ बंगाल और 2024 के चुनावों का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र में 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच 39 लाख नए मतदाता जुड़े थे। बंगाल में एसआईआर के दौरान हटाए गए नामों में से बड़ी संख्या अपील के बाद वापस जोड़े जाने का भी उन्होंने उल्लेख किया। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में हर पांचवें मतदाता के ड्राफ्ट सूची से बाहर होने का दावा करते हुए पूछा कि 2024 की लोकसभा सूची, विधानसभा सूची और 2026 की एसआईआर सूची में आखिर कौन-सी मतदाता सूची सही है?

गैर-जरूरी सोने की खरीदारी से बचे : मोदी

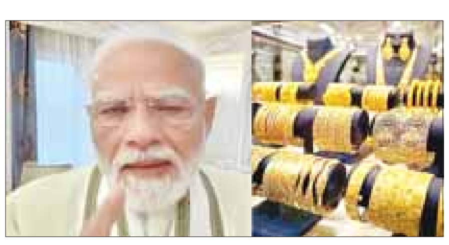

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की 7.8 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि दर को देशवासियों के लिए गौरव की उपलब्धि बताया है। मंगलवार को सोशल मीडिया पर जारी वीडियो संदेश में उन्होंने देश की आर्थिक प्रगति के लिए लोगों की इच्छाशक्ति, मेहनत और सामूहिक ताकत को श्रेय दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने मजबूत विकास दर हासिल की है और अब इसी गति को बनाए रखने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर लोगों से गैर-जरूरी सोने की खरीदारी से बचने की अपील की। उन्होंने कहा कि जरूरत न हो तो सोना नहीं खरीदना चाहिए। इससे पहले 10 मई को भी उन्होंने देशवासियों से सोने की खरीद कम करने का आग्रह किया था। भारत अपनी सोने की जरूरत का करीब 99 प्रतिशत हिस्सा आयात करता है। ऐसे में सोने का आयात कम होने से विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है और डॉलर की मांग घटने से रुपये पर दबाव भी कम हो सकता है।

नेपाल ने मांगा क्लाइमेट मुआवजा

काठमांडू। नेपाल ने 26 अगस्त को भोटेकोशी नदी बेसिन में आई विनाशकारी अचानक बाढ़ से हुए भारी नुकसान के बाद जलवायु मुआवजे की मांग तेज कर दी है। नेपाल सरकार का कहना है कि जलवायु परिवर्तन में बेहद कम योगदान देने के बावजूद देश को ग्लोबल वार्मिंग और उससे जुड़ी प्राकृतिक आपदाओं की बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। ऐसे में आपदा के बाद मिलने वाली आर्थिक सहायता को दान नहीं, बल्कि नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी के रूप में देखा जाना चाहिए। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कहा कि ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने और हिमालयी क्षेत्रों में बढ़ती विनाशकारी घटनाओं के पीछे जलवायु परिवर्तन की बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि नेपाल ऐसे वैश्विक संकट का नुकसान उठा रहा है, जिसे पैदा करने में उसका योगदान बेहद कम है। इसी आधार पर नेपाल अब अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सहायता से आगे बढ़कर न्याय और मुआवजे की मांग उठाएगा। खनाल के अनुसार, नेपाल ने बड़े ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक देशों से जलवायु मुआवजे की मांग के लिए कूटनीतिक प्रयास शुरू किए हैं। उन्होंने चीन, अमेरिका और भारत का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए कहा कि कमजोर देशों को जलवायु आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई में बड़ी जिम्मेदारी इन देशों की है। नेपाल ने पहली बार लॉस एंड डैमेज फंड से भी तत्काल आर्थिक सहायता की औपचारिक मांग की है। वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले और वन एवं कृषि मंत्री गीता चौधरी ने संयुक्त रूप से फंड के बोर्ड को पत्र भेजकर मदद मांगी है।

महिलाओं के लिए बहुत असुरक्षित बन गया है दिल्ली-एनसीआर : राहुल

नई दिल्ली (वार्ता)। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर महिलाओं के लिए इतना असुरक्षित हो चुका है कि एक नाबालिग बच्ची के साथ 45 किमी तक चलती स्लीपर बस में सामूहिक दुष्कर्म होता है लेकिन बेरोकटोक चल रही बस की कहीं कोई जांच नहीं होती। श्री गांधी ने मंगलवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि यह घटना ग्रेटर नोएडा से दिल्ली तक हुई। हैरानी की बात है कि पूरी दिल्ली या नोएडा पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। उन्होंने कहा कि यह बस नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, दिल्ली के रिंग रोड और सीमा से गुजर गयी लेकिन उसे एक भी जांच चौकी पर नहीं रोका गया। उन्होंने लिखा कि बस की सीटों पर पर्दे लगे थे, ताकि अंदर क्या हो रहा है, कोई देख न सके और अपराधियों में प्रशासन का कोई डर भी नहीं था। सवाल है कि निर्भया कांड के बाद इतने वर्षों और इतनी घटनाओं के बावजूद ऐसी बसों की जांच और निगरानी के नियमों का पालन क्यों नहीं हो रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पर्दे सिर्फ उस बस में नहीं डाले गये थे, बल्कि साल दर साल सरकार द्वारा प्रशासन की नाकामियों पर डाले गये पर्दों का नतीजा है कि देश की राजधानी में भी महिलाएं सुरक्षित सफर नहीं कर सकतीं। सवाल किया कि और कितनी महिलाओं और बच्चियों के साथ ऐसी घटनाएं होने के बाद केंद्र और राज्य सरकारें इस व्यवस्था को ठीक करेंगी। उन्होंने पूछा कि क्या गृह मंत्री अमित शाह के अधीन दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अधीन उत्तर प्रदेश पुलिस की जवाबदेही तय की जाएगी या इस अपराध पर भी पर्दा डाल दिया जाएगा।

चित्रकूट में फिर उफनी मंदाकिनी, बाढ़ का खतरा बढ़ा

लगातार बारिश से तेजी से बढ़ रहा जलस्तर, नदी किनारे और निचले इलाकों में प्रशासन करवा रहा मुनादी

चित्रकूट

सतना जिले की धार्मिक नगरी चित्रकूट में लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। देर रात से जारी बारिश के चलते मंदाकिनी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। नदी के बढ़ते पानी और रौद्र रूप को देखते हुए आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नदी किनारे रहने वाले लोगों की नजर लगातार जलस्तर पर बनी हुई है। बीते दिनों हुई भारी बारिश के बाद मंदाकिनी नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया था। बाढ़ के कारण चित्रकूट के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित हुआ था। उस आपदा के निशान अभी लोगों की यादों से पूरी तरह मिटे भी नहीं हैं कि दोबारा बढ़ता जलस्तर चिंता का कारण बन गया है। बारिश जारी रहने से नदी का पानी और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। मंदाकिनी का जलस्तर बढ़ने के साथ ही नदी के आसपास रहने वाले लोग सतर्क हो गए हैं। घाटों और निचले इलाकों में पानी भरने की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। जलस्तर बढ़ने के साथ नदी किनारे और निचले इलाकों में प्रशासनलगातार मुनादी करवाकर लोगों को सर्तक कर रहा है।

सड़कों पर नाव, घाट लबालब

बढ़ते जलस्तर का असर क्षेत्र में दिखाई देने लगा है। कई स्थानों पर पानी भरने से आवागमन प्रभावित हुआ है और सड़कों पर नाव चलती नजर आ रही हैं। नदी के घाट भी पानी से लबालब हो गए हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। नदी के आसपास और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई जा रही है। लोगों से नदी के किनारे, घाटों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूरी बनाए रखने की अपील की जा रही है। प्रशासन बारिश और जलस्तर की स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है। फिलहाल सबसे बड़ी चिंता बारिश के जारी रहने को लेकर है। यदि बारिश का दौर नहीं थमा तो मंदाकिनी का जलस्तर और बढ़ सकता है। ऐसे में नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।

प्रयागराज में भी बाढ़ का खतरा

उ.प्र के प्रयागराज में गंगा-यमुना के बढ़ते जलस्तर से मंगलवार को दोनों नदियों का पानी शहर के निचले इलाकों में पहुंच गया, जिससे कई मोहल्लों की दर्जनों गलियां जलमग्न हो गईं। नेवादा, गंगानगर, राजापुर, बेली, चिल्ला, छोटा बघाड़ा और दारागंज समेत कई इलाकों में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मंगलवार सुबह गंगा का जलस्तर 82.88 मीटर और यमुना का 82.39 मीटर दर्ज किया गया। दोनों नदियां लगातार खतरे के निशान की ओर बढ़ रही हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में जारी बारिश और बांधों-बैराजों से छोड़े जा रहे पानी के कारण जलस्तर में वृद्धि हो रही है। कई घरों में पानी घुसने के बाद सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है। प्रभावित लोगों के लिए प्रशासन ने दो राहत शिविर संचालित किए हैं।

अस्थाई रूप से बंद रहेगा शहपुरा टोल, जबलपुर दमोह मार्ग पर शीघ्र मरम्मत कराने के निर्देश

प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं की मंत्री राकेश सिंह ने ली बैठक

जबलपुर (स्वतंत्र मत)। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने मंगलवार को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रदेश में किए जा रहे निर्माण कार्यों तथा भविष्य के लिए प्रस्तावित वृहद सड़क परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में एनएचएआई के अधिकारियों ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से वर्तमान में प्रगतिरत परियोजनाओं की स्थिति तथा प्रस्तावित नई परियोजनाओं की कार्ययोजना की जानकारी दी। बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव, सड़क सुरक्षा, निर्माण गुणवत्ता तथा वर्षाकाल के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री श्री सिंह ने भोपाल इंदौर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे तथा उज्जैन झालावाड़

दिसंबर तक पूर्ण होंगे रिंग रोड़ के चार पैकेज

ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से संबंधित आवश्यक प्रक्रियाओं को शीघ्र पूर्ण कर निर्माण कार्य प्रारंभ कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण इन वृहद सड़क परियोजनाओं में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। संबंधित स्तरों पर सभी आवश्यक कार्रवाई तेजी से पूरी की जाए।

जबलपुर रिंग रोड के चार पैकेज दिसंबर 2026 तक पूर्ण करने के निर्देश

मंत्री श्री सिंह ने बैठक में जबलपुर रिंग रोड के निर्माण कार्य की प्रगति की भी समीक्षा की गई। रिंग रोड का निर्माण कुल पाँच पैकेजों में किया जा रहा है। इनमें चार पैकेजों में कार्य की प्रगति संतोषजनक पाई गईए जबकि पांचवें पैकेज में अपेक्षित गति से कार्य नहीं होने पर कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। मंत्री श्री सिंह ने चार पैकेजों का कार्य दिसंबर 2026 तक तथा पांचवें पैकेज का कार्य जून 2027 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए, जिससे संपूर्ण जबलपुर रिंग रोड का निर्माण निर्धारित समय सीमा में पूरा हो सके।

नहीं वसूला जाएगा टोल टैक्स

भोपाल जबलपुर मार्ग पर शहपुरा रेलवे ब्रिज के क्षतिग्रस्त होने के कारण यातायात को डायवर्ट किया जा रहा है। इसके चलते शहपुरा स्थित टोल पर लिए जा रहे टोल को लेकर स्थानीय समुदाय में असंतोष की स्थिति बनी हुई है। मंत्री श्री सिंह ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए शहपुरा भिटौनी टोल नाके पर अस्थायी रूप से टोल संग्रह बंद करने के निर्देश दिए। एनएचएआई के अधिकारियों ने बैठक में बताया कि प्राधिकरण के सभी राष्ट्रीय राजमार्ग किसी न किसी अनुबंध के अंतर्गत संधारित किए जा रहे हैं। जिन सड़कों की परफॉर्मेंस गारंटी अवधि समाप्त हो चुकी है अथवा जिनके पुनर्निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, उनके रखरखाव के लिए शॉर्ट टर्म मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट तथा लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से मरम्मत एवं संधारण कार्य कराया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि वर्षाकाल के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। मंत्री श्री सिंह ने निर्देश दिए कि प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणवत्ता और रखरखाव के स्तर को बेहतर बनाया जाए तथा क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत में किसी भी प्रकार की देरी नहीं हो। उन्होंने नई प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं से संबंधित प्रक्रियाओं को भी गति देने के निर्देश दिए।

गुणवत्ता संबंधी समस्याओं पर की चर्चा

मंत्री श्री सिंह ने जबलपुर-दमोह मार्ग पर आवश्यक मरम्मत कार्य शीघ्र प्रारंभ कराने के निर्देश दिए। उन्होंने उज्जैन गरोठ मार्ग के निर्माण में सामने आई गुणवत्ता संबंधी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने तथा निर्माण गुणवत्ता की जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास केवल नई सड़क परियोजनाओं तक सीमित नहीं है। निर्माण की गुणवत्ता, समयबद्धता, नियमित रखरखाव और सड़क सुरक्षा पर भी समान रूप से ध्यान दिया जाना आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को इन सभी विषयों पर सतत निगरानी रखते हुए कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

बाइक सवार दंपत्ति को क्रेन ने मारी टक्कर, एक की हालत गंभीर

बेलखाडू थाना चौकी का मामला चालक गिरफ्तार

जबलपुर (स्वतंत्र मत)। शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर ग्राम झगरा में मंगलवार सुबह रिंग रोड के काम में लगी क्रेन ने बाइक सवार दंपती और उनके दो बच्चों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार मंजू छिटककर दूर जा गिरीं और गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पति आकाश और दोनों बच्चे हादसे में सुरक्षित हैं। इस मामले में बेलखाडू चौकी प्रभारी अमित मिश्रा ने बताया कि करारी मनकवारा निवासी मंजू रक्षाबंधन पर मायके गई थीं। सोमवार शाम उनके पति आकाश उन्हें लेने पहुंचे थे। मंगलवार सुबह आकाश पत्नी और दोनों बच्चों को बाइक पर लेकर झगरा स्थित घर लौट रहे थे। इसी दौरान झगरा के पास सामने से आ रही क्रेन ने बाइक को टक्कर मार दी।

हादसे में बच्चे सुरक्षित

टक्कर लगते ही बाइक सवार चारों लोग सड़क किनारे जा गिरे। मंजू उछलकर कुछ दूरी पर जा गिरीं और उन्हें गंभीर चोट आई। आसपास मौजूद लोगों ने

तत्काल उन्हें उठाया और इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भिजवाया। सूचना पर बेलखाडू चौकी पुलिस भी मौके पर पहुंची। इस मामले में डीएसपी बीएस गठोरिया ने बताया कि आकाश और दोनों बच्चे सुरक्षित हैं, जबकि मंजू की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने हादसे में शामिल रिंग रोड निर्माण कार्य में लगी क्रेन को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

नगर निगम की जनसुनवाई में पहुंचे 63 आवेदन

जबलपुर (स्वतंत्र मत)। नगर निगम मुख्यालय और सभी संभागीय कार्यालयों में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में नागरिकों को बड़ी राहत मिली। निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार के निर्देश पर अपर आयुक्त विद्यानंद बाजपेई, सौरभ मिश्रा एवं प्रभारी जनसुनवाई वेद प्रकाश चैधरी ने नागरिकों की समस्याओं को सुना, और अधिकारियों को मौके पर बुलाकर उनका तुरंत समाधान भी कराया। अधिकारियों के इस त्वरित कार्यवाही से काम कराने आए नागरिकों के चेहरों पर खुशी साफ देखी जा सकती थी। मुख्यालय के साथ-साथ नगर निगम के सभी संभागीय कार्यालयों में भी जनसुनवाई का भी आयोजन किया गया। संभाग स्तर पर नागरिकों द्वारा कुल 30 आवेदन प्रस्तुत किए गए। संभागीय अधिकारियों ने सभी 30 आवेदनों का मौके पर ही शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित किया।

शहर को अपना समझकर करें कार्य:निगमायुक्त

जबलपुर (स्वतंत्र मत)

शहर की स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने और शहरवासियों को एक स्वच्छ परिवेश देने के लिए निगमायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की गहन समीक्षा की। समीक्षा बैठक के साथ-साथ निरीक्षण के दौरान निगमायुक्त ने शहर की सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए कड़े कदम उठाए हैं, वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों में आत्मीयता और कर्तव्यबोध जगाने के लिए सकारात्मक मार्गदर्शन भी दिया है। बैठक में निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार ने निर्देशित किया कि यदि निरीक्षण के दौरान कहीं भी सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी पाई गई तो स्वच्छता मानकों में कोताही बरतने वाले लोगों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कारवाई की जाएगी। निगमायुक्त ने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और सफाई मित्रों से भावुक अपील करते हुए कहा कि वे इस शहर को अपना घर समझकर काम करें। जब कार्य में अपनेपन का भाव होगा, तो स्वच्छता स्वत: ही नजर आने लगेगी। शहर में स्वच्छता के नए मानक स्थापित करने के लिए नगर निगम ने एक अभिनव योजना तैयार की है। इसके तहत हर जोन में एक-एक वार्ड को आदर्श वार्ड के रूप में विकसित किया जाएगा। इन वार्डों में सफाई, कचरा प्रबंधन और सौंदर्यीकरण की मिसाल पेश की जाएगी, जिससे प्रेरित होकर अन्य वार्ड भी अपने स्तर में सुधार करेंगे।

संयुक्त संचालक मत्स्योद्योग ने किया मत्स्यबीज प्रक्षेत्र गोकलपुर का निरीक्षण

जबलपुर (स्वतंत्र मत)। मत्स्य विभाग के संयुक्त संचालक मत्स्योद्योग गिरीश मेश्राम ने मत्स्यबीज प्रक्षेत्र गोकलपुर का भ्रमण एवं निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रक्षेत्र में चल रहे मत्स्यबीज उत्पादन व संवर्धन कार्यों का अवलोकन करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान संयुक्त संचालक श्री मेश्राम ने प्रजनक तालाबों का अवलोकन करते हुए मत्स्यबीज उत्पादन, नर्सरी प्रबंधन, जल गुणवत्ता और मत्स्यबीज की गुणवत्ता की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण मत्स्यबीज के उत्पादन और बेहतर प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाए। संयुक्त संचालक श्री मेश्राम ने प्रक्षेत्र की व्यवस्थाओं को सुधारने, संसाधनों का भरपूर उपयोग करने और जिले के मत्स्य पालकों को समय पर उच्च गुणवत्ता का मत्स्यबीज उपलब्ध कराने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मत्स्य विभाग के सहायक संचालक राजा राज तिलक धुर्वे, मत्स्य निरीक्षक दीक्षा बैरागी तथा प्रक्षेत्र के कर्मचारी राजेश रैकवार एवं सुनील झरिया उपस्थित रहे।

लापरवाही बरतने वाले 3 कर्मचारियों पर निगमायुक्त ने लिया एक्शन

जबलपुर (स्वतंत्र मत)

नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से निगमायुक्त ने राजस्व वसूली अभियान में तेजी लाने के संबंध में एक बैठक आयोजित की। निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार ने राजस्व संग्रह को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि प्रतिदिन टैक्स वसूली करना टैक्स कलेक्टर की प्राथमिक जिम्मेदारी है। बैठक में उन्होंने कार्य में लापरवाही बरतने वाले तीन कर्मचारियों का एक-एक वेतन वृद्धि रोकने के साथ ही उनका स्थानांतरण करने के आदेश दिए हैं।

निगमायुक्त द्वारा 100 प्रतिशत प्रतिशत वसूली के लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए संभागीय अधिकारियों, राजस्व निरीक्षकों, सहायक निरीक्षकों और कर संग्राहकों को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि अभियान को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए शहर में संचालित कार बाजारों, मैरिज गार्डन, गाड़ी धुलाई सेंटरों, कैफेटेरिया और सड़क किनारे की व्यावसायिक दुकानों का गहन निरीक्षण किया जाएगा। बिना अनुमति या बिना लाइसेंस के चल रहे प्रतिष्ठानों पर नियमानुसार त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम की इस पहल से न केवल अवैध व्यावसायिक गतिविधियों पर लगाम लगेगी, बल्कि शहर के राजस्व में भी वृद्धि होगी जिसका सीधा लाभ जनता को बेहतर नागरिक सुविधाओं के रूप में मिलेगा। राजस्व एवं बाजार विभाग के सभी अधिकारियों को मैदान में उतरकर वसूली कार्यों को गति देने के निर्देश दिए गए हैं। इस पूरे अभियान की प्रगति का आकलन करने के लिए दो दिन बाद पुन: समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में सभी विभागीय प्रमुख आदि उपस्थित रहे।

विश्व हिंदू परिषद की बैठक में नए पदाधिकारियों की घोषणा

जबलपुर (स्वतंत्र मत)। विश्व हिंदू परिषद प्रांत बैठक का आयोजन सिहोरा जिले की रमन पैलेस में संपन्न हुई। बैठक में आगामी 6 माही कार्यक्रमों हेतु योजना बनी एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर ग्राम समिति तक स्थापना दिवस के कार्यक्रम हो इस पर जोर दिया गया। नए दायित्वों की घोषणा की गई जिसमें नीरज पटेल, मानस तिवारी को जिले का सहसंयोजक, अमित बक्शी को

जिला प्रचार प्रसार प्रमुख, मनीष साहू को धर्मप्रसार प्रमुख, मझौली प्रखंड में प्रखंड सहसंयोजक समित सिंग, पटेल साहिल कुशवाहा, गौ रक्षा प्रमुख सचिन कुशवाहा सह प्रमुख अरुण मिश्रा, पंडा कुशवाहा, आकाश पुरी गोस्वामी, नादघाट समिति में, रमाकांत, अध्यक्ष मनीष पटेल, मंत्री धर्मेंद्र पटेल संयोजक ललित कुमार नीतीश कुशवाहा अंगद पटेल, सतीश साहू नीरज गोटियां, जग्गू कुशवाहा, अजीत भूमिया, अधिक संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। घोषणा के समय जिले के पालक चंद्रकांत मिश्र प्रांत सह विशेष संपर्क प्रमुख, विभाग मंत्री महेन्द्र सिंग, जिला अध्यक्ष पवन मिश्रा जिला उपाध्यक्ष विजय जनवानी जिला मंत्री अर्जुन कुशवाहा आदि उपस्थित रहे।

स्काउट एंड गाइड के सदस्यों ने सीखे आपदा में सुरक्षा के उपाय

जबलपुर (स्वतंत्र मत)। स्काउट एवं गाइड के बच्चों द्वारा एक सितंबर को एसडीआरएफ में प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया गया। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य बच्चों को आपातकालीन परिस्थितियों में स्वयं की तथा अन्य लोगों की सुरक्षा करने के लिए आवश्यक प्राथमिक सहायता एवं बचाव तकनीकों की जानकारी देना था। प्रशिक्षण के दौरान बच्चों को सीपीआर के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। बच्चों ने सीपीआर करने की सही प्रक्रिया, आपात स्थिति में व्यक्ति की स्थिति को

पहचानना तथा आवश्यकता पड़ने पर किस प्रकार सहायता प्रदान करनी चाहिए, इसका प्रायोगिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। साथ ही, बेहोश अथवा सांस न ले रहे व्यक्ति को प्राथमिक सहायता देने एवं कृत्रिम श्वसन की प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया। इसके अतिरिक्त, बच्चों को बाढ़ एवं जल-आपदा के समय बचाव के उपायों के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। डूबते हुए व्यक्ति को सुरक्षित तरीके से सहायता देने, स्वयं की सुरक्षा को प्राथमिकता देने तथा पानी में फंसे व्यक्ति के बचाव के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में समझाया गया। प्रशिक्षण के दौरान बच्चों ने प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में सभी गतिविधियों को ध्यानपूर्वक सीखा और आवश्यक प्रायोगिक अभ्यास भी किया।

पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ मनाया गया सातुड़ी तीज महोत्सव

जबलपुर (स्वतंत्र मत)। माहेश्वरी समाज की महिलाओं द्वारा पारंपरिक पर्व सातुड़ी तीज का आयोजन हर्षोल्लास एवं उत्साह के साथ किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में सहभागिता करते हुए तीज के गीत, भजन एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से भारतीय संस्कृति और परंपराओं को जीवंत किया। सातुड़ी तीज महिलाओं के लिए आस्था, सौभाग्य, प्रेम और पारिवारिक सुख-समृद्धि का महत्वपूर्ण पर्व है। इस अवसर पर महिलाओं ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-शांति एवं समृद्धि की कामना की। आयोजकों ने कहा कि ऐसे पर्व हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक मूल्यों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। सामूहिक रूप से पर्व मनाने से समाज में आपसी स्नेह, एकता और भाईचारे की भावना भी मजबूत होती है। आयुषी पाम ग्रीन में पूजा माहेश्वरी द्वारा आयोजित सातुड़ी तीज उत्सव में निर्मला जेठा, तारा जेठा, अनिता माहेश्वरी, गीता जेठा, नेहा जेठा, दीप्ति जेठा, प्रियंका माहेश्वरी, दिया माहेश्वरी,चंचल,रुचि, खुशबू ,अवनी माहेश्वरी आदि समाज की महिलाएं एकत्रित हुईं। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित महिलाओं का आभार व्यक्त करते हुए सातुड़ी तीज की शुभकामनाएं दी गईं।

25वें दिन भी जारी रहा छात्रों का प्रदर्शन

जबलपुर (स्वतंत्र मत)। एन एस ओ छात्र संगठन द्वारा नर्सिंग काउंसिल भोपाल पर 25वें दिन रात में भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। छात्रों के साथ साथ छात्राएं भी आज से रात में धरना प्रदर्शन पर बैठने पर मजबूर हो गई है। 25 दिनों के धरना प्रदर्शन के बाद भी मध्यप्रदेश सरकार और नर्सिंग काउंसिल भोपाल ना तो सभी स्टूडेंट्स के पुराने रिजल्ट घोषित कर रही है, ना ही आगामी परीक्षा करवा रही है और ना ही भ्रष्टाचार को खत्म कर रही है लेकिन संगठन का धरना प्रदर्शन सभी मांगो को पूरा करने तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा।

लंबित मांगों को लेकर शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के कर्मचारियों ने की भूख हड़ताल

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास अधिकारी-कर्मचारी संगठन ने दिया समर्थन

जबलपुर (स्वतंत्र मत)।

शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में कर्मचारियों की लंबित एवं न्यायोचित मांगों के निराकरण को लेकर मप्र लघुवेतन कर्मचारी संघ, जिला शाखा एवं विभागीय शाखा द्वारा पूर्व निर्धारित 4 चरणीय लोकतांत्रिक आंदोलन के अंतर्गत मंगलवार को एक दिवसीय भूख हड़ताल प्रारंभ की गई। भूख हड़ताल पर कर्मचारी इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रांगण में बैठे रहे। आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारियों की उपस्थिति रही तथा कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में स्थानीय प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी कर आक्रोश व्यक्त किया। इससे

कॉलेज परिसर में आंदोलन का माहौल और अधिक प्रभावशाली हो गया।

7 सितंबर से होगी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल

भूख हड़ताल के दौरान तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास अधिकारी-कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों ने आंदोलन स्थल पर पहुंचकर मध्यप्रदेश लघुवेतन कर्मचारी संघ के आंदोलन को अपना समर्थन दिया। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारिणी, संभागीय शाखा एवं प्रभावी समिति के अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कर्मचारी आंदोलन स्थल पर उपस्थित रहे। विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ने कर्मचारियों की मांगों के प्रति एकजुटता को और मजबूत किया।

मप्र लघुवेतन कर्मचारी संघ द्वारा मांगों के निराकरण के लिए चार चरणीय आंदोलन की घोषणा की गई थी। आंदोलन के प्रथम चरण में 20 अगस्त को काली पट्टी बांधकर कार्य तथा द्वितीय चरण में 24, 25 एवं 26 अगस्त को दो घंटे मौन रहकर काली पट्टी बांधकर कार्य किया गया था। इन चरणों के बावजूद मांगों का अपेक्षित निराकरण नहीं होने पर 01 सितंबर को एक दिवसीय भूख हड़ताल आयोजित की गई। संघ ने स्पष्ट किया है कि यदि कर्मचारियों की मांगों का शीघ्र एवं सकारात्मक निराकरण नहीं किया गया तो पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार 07 सितंबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल प्रारंभ की जाएगी। इसके साथ ही निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कॉलेज प्रशासन का पुतला दहन भी किया जाएगा।

संघ ने प्रशासन को दिया स्पष्ट संदेश

जिला शाखा जबलपुर ने कहा कि कर्मचारी लगातार लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को प्रशासन के समक्ष रख रहे हैं। प्रथम एवं द्वितीय चरण के बाद भी समाधान नहीं होने से कर्मचारियों में गहरा असंतोष है।

संघ ने प्रशासन से मांग की है कि आंदोलन को गंभीरता से लेते हुए कर्मचारियों की लंबित मांगों पर तत्काल सकारात्मक निर्णय लिया जाए, ताकि आंदोलन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता न पड़े। इस दौरान प्रांत महामंत्री अजय कुमार दुबे, संभागीय अध्यक्ष विपिन पीपरे, आलोक बाजपेई, वीरेश शर्मा आदि उपस्थित रहे।

संविधान ने दिया समान न्याय का अधिकार

दीनन सबको लखत है,
दीनहिं लखै न कोइ।
जो रहीम दीनहिं लखै,
दीनानाथ सम होइ।।

समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को न्याय दिलाने के लिए संविधान में निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 39(क) को वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक कमजोरी या किसी अन्य कारण से कोई नागरिक न्याय पाने के अधिकार से वंचित न रहे।

अनुच्छेद 21 से जुड़ा विधिक सहायता का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने भी निःशुल्क विधिक सहायता को नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जोड़ा है। एम.एच. होसकोट बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में न्यायालय ने माना कि निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी प्रकार हुसैनआरा खातून बनाम बिहार राज्य मामले में त्वरित सुनवाई और निःशुल्क विधिक सहायता के अधिकार को विशेष महत्व दिया गया। इन निर्णयों ने विधिक सहायता को प्रभावी कानूनी व्यवस्था का आधार प्रदान किया।

1987 में बना विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम

निःशुल्क विधिक सहायता को व्यवस्थित रूप देने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 अस्तित्व में आया। इसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर नालसा, राज्य स्तर पर सालसा, जिला स्तर पर डालसा तथा तहसील स्तर पर तालुक विधिक सेवा समितियों का गठन किया गया है। ये संस्थाएं जरूरतमंद लोगों को कानूनी सलाह और सहायता उपलब्ध कराने के साथ उन्हें न्याय तक पहुंचने में मदद करती हैं।

किन्हें मिल सकती है निःशुल्क कानूनी सहायता?

अधिनियम की धारा 12 के तहत अनुसूचित जाति-जनजाति के सदस्य, महिलाएं और बच्चे, मानसिक या शारीरिक रूप से असमर्थ व्यक्ति, मानव तस्करी या अत्याचार के पीड़ित, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोग, औद्योगिक श्रमिक तथा हिरासत में रखे गए व्यक्ति निःशुल्क विधिक सहायता के पात्र हो सकते हैं। निर्धारित आय सीमा से कम आय वाले व्यक्ति भी इसका लाभ ले सकते हैं। पात्र व्यक्ति आय प्रमाण-पत्र के स्थान पर शपथ-पत्र प्रस्तुत कर सकता है।

जरूरतमंद तक पहुंचे बेहतर कानूनी सहायता

विधिक सेवा प्राधिकरणों की व्यवस्था सराहनीय है, लेकिन अलग-अलग प्रकार के मामलों के लिए विषय-विशेषज्ञ अधिवक्ताओं की उपलब्धता और बढ़ाई जा सकती है। सिविल, आपराधिक, राजस्व, उपभोक्ता, बैंकिंग और रिट मामलों के लिए अलग-अलग अनुभवी अधिवक्ताओं के पैनल बनाए जाने से जरूरतमंदों को अधिक प्रभावी कानूनी सहायता मिल सकेगी। न्याय तभी सार्थक है, जब वह समाज के अंतिम व्यक्ति तक बिना आर्थिक बाधा के पहुंच सके।

एसएन खरे
पूर्व जिला एवं सत्र न्यायधीश
जबलपुर

छात्रों के सर्वांगीण विकास में अध्यात्म की भूमिका

आज का विद्यार्थी प्रतियोगिता, तनाव और तेजी से बदलती जीवनशैली के बीच अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे समय में अध्यात्म विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का सशक्त आधार बन सकता है। अध्यात्म केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मअनुशासन, नैतिकता, सकारात्मक सोच और मानवीय मूल्यों का विकास करता है।

मानसिक और बौद्धिक विकास

अध्यात्म मन को शांत करने में सहायक है। ध्यान, योग और प्राणायाम जैसी गतिविधियों से विद्यार्थियों में तनाव, चिंता और भय को कम करने में मदद मिलती है। इससे वे अपनी पढ़ाई और दैनिक कार्यों पर बेहतर ढंग से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। नियमित ध्यान से एकाग्रता, स्मरण शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता को भी बढ़ावा मिलता है।

नैतिक मूल्यों का विकास

विद्यार्थी जीवन चरित्र निर्माण का महत्वपूर्ण चरण होता है। अध्यात्म के माध्यम से सत्य, ईमानदारी, अनुशासन, करुणा, सहनशीलता और सेवा जैसे मूल्यों को जीवन में अपनाने की प्रेरणा मिलती है। इन मूल्यों से विद्यार्थी जिम्मेदार और आत्मविश्वासी व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं।

सामाजिक और शारीरिक विकास

अध्यात्म विद्यार्थियों में सहयोग, भाईचारे, सहिष्णुता और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करता है। वे दूसरों की भावनाओं और आवश्यकताओं को समझना सीखते हैं। वहीं योग और प्राणायाम शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर रखने के साथ कार्यक्षमता बढ़ाने में भी सहायक हैं।

शिक्षा और अध्यात्म का संतुलन

अध्यात्म का सकारात्मक प्रभाव विद्यार्थियों की शैक्षणिक गतिविधियों पर भी पड़ता है। एकाग्रता और आत्मविश्वास बढ़ने से पढ़ाई में रुचि विकसित होती है और परीक्षा के समय तनाव को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। हालांकि अध्यात्म का उद्देश्य किसी विशेष धार्मिक विचार को थोपना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में अच्छे मानवीय गुणों का विकास करना होना चाहिए।

सशक्त राष्ट्र की नींव

शिक्षा और अध्यात्म का संतुलित समन्वय विद्यार्थियों को केवल सफल नहीं, बल्कि संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बनाने में सहायक हो सकता है। विद्यालय, परिवार और समाज मिलकर यदि उनमें नैतिक एवं मानवीय मूल्यों का विकास करें, तो वे संस्कारित समाज और सशक्त राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

श्रद्धा श्रीवास
शिक्षक, के.सी. हितकारिणी चिल्ड्रल्स एकेडमी,
जोंसगंज, जबलपुर।

सूचना का अधिकार, पारदर्शिता और जवाबदेही की मजबूत कड़ी

लोकतंत्र केवल चुनाव और सरकार बनाने तक सीमित नहीं है। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि नागरिकों को यह जानने का अधिकार हो कि सरकार और सार्वजनिक संस्थाएं किस प्रकार काम कर रही हैं। सूचना का अधिकार इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने वाला महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके जरिए आम नागरिक सरकारी कामकाज से जुड़ी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू हुआ। इसका उद्देश्य सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाना, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना और प्रशासन को जनता के प्रति अधिक जवाबदेह बनाना है। इस कानून के तहत नागरिक विभिन्न सरकारी विभागों, कार्यालयों और सार्वजनिक प्राधिकरणों से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जानकारी मांग सकते हैं।

जानकारी मांगना हुआ आसान

इसके माध्यम से नागरिक सरकारी योजनाओं, विकास कार्यों, बजट, खर्च, निविदाओं, लाभार्थियों की सूची, सरकारी निर्णयों और किसी कार्य की प्रगति जैसी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी नागरिक को लगता है कि किसी सरकारी योजना का लाभ उसे नहीं मिला या किसी कार्य में अनियमितता हुई है, तो वह संबंधित विभाग से रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जानकारी मांग सकता है। इस व्यवस्था से सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है। अधिकारियों को यह एहसास रहता है कि उनके निर्णय और कार्य सार्वजनिक जांच के दायरे में आ सकते हैं।

सूचना का अधिकार नागरिकों को केवल जानकारी प्राप्त करने का साधन नहीं देता, बल्कि उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक और सक्रिय बनाता है। जानकारी के आधार पर नागरिक सवाल पूछ सकते हैं और प्रशासन से जवाब मांग सकते हैं। इससे लोकतंत्र में सरकार और जनता के बीच संवाद मजबूत होता है।

इसका उपयोग जनहित और वास्तविक जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए। नागरिकों को आवेदन करते समय स्पष्ट और तथ्यात्मक प्रश्न पूछने चाहिए तथा प्राप्त जानकारी का जिम्मेदारी से उपयोग करना चाहिए। साथ ही, कानून में कुछ ऐसी सूचनाओं को अपवाद के रूप में रखा गया है, जिनका सार्वजनिक किया जाना राष्ट्रीय हित, सुरक्षा या किसी व्यक्ति की निजता को प्रभावित कर सकता है।

सूचना का अधिकार लोकतंत्र में नागरिकों की आवाज को मजबूत करता है। जागरूक नागरिक जब सही जानकारी के आधार पर सवाल पूछते हैं, तो शासन व्यवस्था अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनोन्मुख बनती है।

वैश्विक व्यापार युद्धः भारत के लिए चुनौती और अवसर

आज के वैश्वीकरण के दौर में अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसी भी देश की आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण आधार है। जब दो या अधिक देश एक-दूसरे के उत्पादों पर अधिक शुल्क (टैरिफ) लगाते हैं या व्यापारिक प्रतिबंध लागू करते हैं, तो इसे व्यापार युद्ध कहा जाता है। इसका असर वैश्विक बाजार, उद्योगों और उपभोक्ताओं पर पड़ता है।

भारत पर संभावित प्रभाव

भारत विश्व की तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और वैश्विक व्यापार युद्ध के प्रभावों से अछूता नहीं रह सकता। व्यापारिक तनाव के बीच यदि कुछ देश चीन जैसे प्रमुख निर्यातक देशों पर निर्भरता कम करने का प्रयास करते हैं, तो भारतीय कंपनियों के लिए नए बाजार खुल सकते हैं। वस्त्र, औषधि, इंजीनियरिंग उत्पाद और कृषि जैसे क्षेत्रों में निर्यात बढ़ाने की संभावनाएं बन सकती हैं। हालांकि, इसका दूसरा पक्ष भी महत्वपूर्ण है। यदि व्यापारिक प्रतिबंधों के कारण कच्चे माल और आवश्यक वस्तुओं के आयात की लागत बढ़ती है, तो उत्पादन महंगा हो सकता है। इसका असर उद्योगों के साथ-साथ आम उपभोक्ताओं की जेब पर भी पड़ सकता है।

रोजगार और निवेश पर असर

व्यापार युद्ध का प्रभाव रोजगार और आर्थिक विकास पर भी पड़ सकता है। निर्यात आधारित उद्योगों में विदेशी मांग घटने से उत्पादन कम हो सकता है और रोजगार के अवसर प्रभावित हो सकते हैं। दूसरी ओर, वैश्विक कंपनियां यदि अपने उत्पादन केंद्रों में विविधता लाना चाहें तो भारत एक आकर्षक विकल्प बन सकता है। इससे देश में विदेशी निवेश, विनिर्माण और रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं।

भारत के लिए आगे की राह

इन परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए भारत को घरेलू विनिर्माण क्षमता मजबूत करने, उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाने और नए निर्यात बाजार विकसित करने पर ध्यान देना होगा। साथ ही, विभिन्न देशों के साथ संतुलित व्यापारिक संबंध बनाए रखना और अंतरराष्ट्रीय व्यापार सहयोग को बढ़ावा देना भी जरूरी है।

चुनौती में छिपा अवसर

वैश्विक व्यापार युद्ध भारत के लिए केवल चुनौती नहीं, बल्कि अवसर भी है। यदि देश दूरदर्शी नीतियों, मजबूत घरेलू उद्योग और प्रतिस्पर्धी उत्पादन क्षमता के साथ आगे बढ़ता है, तो वह बदलते वैश्विक व्यापार समीकरणों का लाभ उठा सकता है। इससे भारत आत्मनिर्भर, सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकता है।

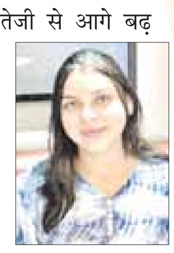

सोनल हबलानी
शिक्षक
बाबू मनमोहनदास
हितकारिणी चिल्ड्रन्स
एकेडमी, दीक्षितपुरा।

लोकतंत्र और सोशल मीडिया

आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म ने लोगों के विचारों को व्यक्त करने और एक-दूसरे तक पहुंचाने के तरीके को बदल दिया है। इसका प्रभाव लोकतंत्र पर भी दिखाई देता है। सोशल मीडिया ने नागरिकों को अपनी बात रखने, मुद्दों पर चर्चा करने और शासन-प्रशासन से संवाद करने का नया माध्यम दिया है।

लोकतंत्र में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। सोशल मीडिया के माध्यम से लोग सामाजिक, राजनीतिक और सार्वजनिक मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। किसी समस्या की जानकारी कम समय में बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच सकती है। जनहित के मुद्दों पर ऑनलाइन चर्चा और अभियान सरकार तथा प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने में भी सहायक हो सकते हैं।

सोशल मीडिया ने सरकार और नागरिकों के बीच संवाद को अधिक सीधा बनाया है। सरकारी विभाग और जनप्रतिनिधि अपनी योजनाओं, निर्णयों और सूचनाओं को सीधे जनता तक पहुंचा सकते हैं। वहीं नागरिक भी अपनी समस्याएं और सुझाव संबंधित संस्थाओं तक पहुंचा सकते हैं। इससे प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की संभावनाएं मजबूत हुई हैं।

सोशल मीडिया का दूसरा पक्ष चिंता पैदा करता है। बिना जांचे-परखे समाचार, अफवाहें और भ्रामक सूचनाएं तेजी से फैल सकती हैं। राजनीतिक मुद्दों पर गलत जानकारी लोगों की राय को प्रभावित कर सकती है और समाज में तनाव पैदा कर सकती है। इसलिए सोशल मीडिया का उपयोग करते समय किसी भी सूचना को साझा करने से पहले उसके स्रोत और सत्यता की जांच करना जरूरी है।

लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी है। किसी व्यक्ति या समुदाय के प्रति घृणा फैलाने वाली, अपमानजनक या हिंसा को बढ़ावा देने वाली सामग्री से बचना चाहिए। स्वस्थ लोकतांत्रिक संवाद के लिए असहमति का सम्मान करना भी आवश्यक है। सोशल मीडिया लोकतंत्र को अधिक सहभागी और संवादात्मक बनाने की क्षमता रखता है। जरूरत है कि नागरिक इसका उपयोग तथ्य, संयम और जिम्मेदारी के साथ करें। जब सोशल मीडिया पर जागरूक नागरिक सक्रिय होते हैं, तो यह केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रहता, बल्कि जनभागीदारी और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने का प्रभावी साधन बन जाता है।

शब्द पहेली - 8963

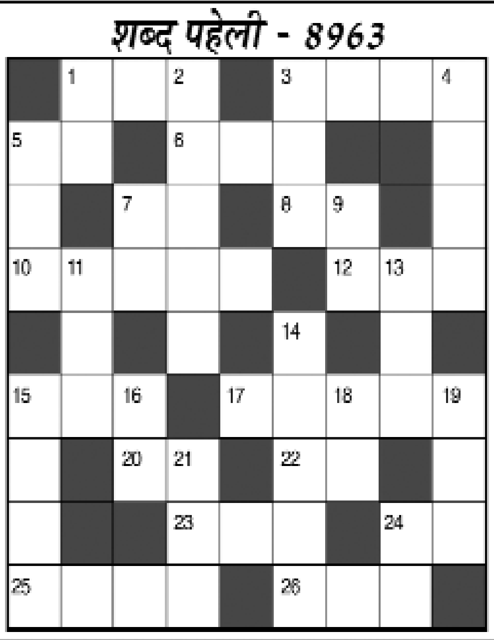

बाएँ से दाएँ

1. ईश वंदना-3
3. हाथ की तीसरी अंगुली-4
5. आगमन-2
6. स्वादिष्ट-3
7. हरसिंगार, पारिजात-2
8. क्रिकेट में बनते हैं-2
10. खौलना, उबलना-5
12. धनवान-3
15. खोदना-3
17. चुनाव, चयन-5
20. नसीब (अंग्रेजी-2)
22. कलर-2
23. रक्षक, संकटमोचक-3
24. कार्य, काज-2
25. सुंघनी, नस-4
26. पुराना जुकाम-3

ऊपर से नीचे

1. रुपए का सोलहवां भाग-2
2. कुलबुलाना, तड़पना-5
3. जो कभी बूढ़ा न हो-3
4. बंदूक की गोली-4
5. अभिलेख, लेख-3
7. रात, रात्रि (उर्दू-2)
9. मादा का विलोम-2
11. धुन, लगाव-3
13. चरित्र, नीयत-3
14. तफरीह-5
15. अनाज रखने की जगह-4
16. टोंटी, नलका-2
18. बहुमूल्य रत्न-2
19. अनाथ, बेसहारा-3
21. डोली उठाने वाले-3
24. सफेद का विलोम -2

शब्द पहेली -8962 का हल

Jagrutidaur.com, Bangalore

व्यापारी समाज देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार : नरेन्द्र सिंह तोमर

उमरिया (स्वतंत्रमत)

मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि व्यापार और व्यवसाय देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार हैं। व्यापारियों की समस्याओं का समाधान और व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना देश की आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक है। सरकार और व्यापारी संगठनों के समन्वय से व्यापार जगत को और मजबूत बनाया जा सकता है। कनफेडरेशन का ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के जिला अध्यक्ष कीर्ति कुमार सोनी ने बताया कि राष्ट्रीय महामंत्री एवं चांदनी चौक दिल्ली के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने विधानसभा परिसर स्थित मानसरोवर सभागार में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के व्यापारिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि समय के साथ व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं।इन सुधारों का उद्देश्य व्यापार को सरल बनाना और व्यापारियों के लिए बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि देश के विकास में बड़े उद्योगों के साथ-साथ छोटे व्यापारी, लघु उद्यमी, कारीगर, किसान, श्रमिक और स्वयं सहायता समूहों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने तथा लोकल फॉर वोकल की भावना को मजबूत करने से छोटे व्यापारियों और स्थानीय उत्पादकों को नए अवसर मिल सकते हैं। श्री तोमर ने कैट द्वारा व्यापारियों के हित में किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि व्यापारी संगठन सरकार और व्यापारियों के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य करते हैं। व्यापारियों की समस्याओं को संगठित रूप से शासन-प्रशासन तक पहुंचाने और उनके समाधान के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक हैं। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीबीसी भारतीय जी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में व्यापारी समाज की भूमिका महत्वपूर्ण है। छोटे से लेकर बड़े व्यापारी तक सभी के योगदान से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। इस अवसर पर उमरिया जिले से कैट के जिलाध्यक्ष कीर्ति कुमार सोनी, संगठन मंत्री राहुल अग्निहोत्री, प्रदेश मंत्री प्रभात अवधिया एवं जिला महासचिव अश्वनी वाधवा विशेष रूप से उपस्थित रहे। सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जैन, संयुक्त अध्यक्ष गोपाल असाटी ,प्रदेशमहामंत्री मनोज गुप्ता एवं विभिन्न जिलों से आए कैट के पदाधिकारी, व्यापारी प्रतिनिधि एवं संगठन के सदस्य भी शामिल हुए।

पीएम श्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमरपुर में शैक्षणिक गतिविधियों का अवलोकन

उमरिया (स्वतंत्रमत)

मंगलवार 1 सितंबर को पीएम श्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमरपुर में पीएम श्री एवं सांदीपनि विद्यालय के संभागीय ओआईसी साईचंद पांडेय द्वारा विद्यालय की शैक्षणिक एवं सह-शैक्षणिक गतिविधियों का पूरे दिन अवलोकन किया गया। अवलोकन के दौरान श्री पांडेय जी ने कक्षा 6 से 8 एवं बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों से संवाद कर उनकी शैक्षणिक प्रगति, विषय संबंधी समझ तथा अध्ययन में आने वाली कठिनाइयों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन, जिज्ञासा एवं गतिविधि आधारित सीखने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय की प्रयोगशाला, पुस्तकालय एवं कक्षा-कक्षों में विद्यार्थियों के लिए किए गए आकर्षक एवं नवाचारपूर्ण प्रयासों का भी अवलोकन किया गया। साथ ही विभिन्न कक्षाओं में जाकर शिक्षण कार्य का निरीक्षण करते हुए विद्यार्थियों की सहभागिता एवं सीखने की प्रक्रिया को देखा गया। इस अवसर पर कक्षा अवलोकन, शिक्षक डायरी, विद्यालय योजना सहित विभिन्न शैक्षणिक अभिलेखों का भी निरीक्षण किया गया। श्री पांडेय जी ने शिक्षकों से संवाद कर गुणवत्तापूर्ण एवं विद्यार्थी-केंद्रित शिक्षण को और प्रभावी बनाने के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया। पूरे दिन चली इस शैक्षणिक गतिविधि के दौरान विद्यालय की विभिन्न व्यवस्थाओं एवं शैक्षणिक कार्यों का विस्तृत अवलोकन किया गया तथा विद्यार्थियों एवं शिक्षकों से संवाद स्थापित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य श्री पवन कुमार चतुर्वेदी सहित विद्यालय के समस्त शिक्षक उपस्थित रहे।

रणविजय प्रताप सिंह महाविद्यालय में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर संपन्न

उमरिया (स्वतंत्रमत)। आयुष्मान भारत उमंग उच्च शिक्षा हेल्थ एंड वैलनेस कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री एक्सीलेंस रणविजय प्रताप सिंह महाविद्यालय कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय के निर्देशन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ व्ही एस चंदेल व महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ अमित कुमार निगम के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपस्थित 190 छात्र.छात्राओं की एनीमिया की जांच ओरल स्क्रीनिंग, आंखों की जांच, एड्स एवं जागरूकता, सामान्य जांच एवं परामर्श सुविधा उपलब्ध करवाई गई। इस दौरान आवश्यकतानुसार रेफर एवं दवाइयां वितरित की गई। इस अवसर पर डॉक्टर ए पी गुप्ता सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यासमीन राजा मंसूरी परामर्शदाता पूजा पांडे आई टेक्नीशियन अभय शर्मा, एएनएम मंजू यादव द्वारा स्वास्थ्य एवं परामर्श में उपलब्ध कराई गई। परामर्शदा द्वारा उमंग स्वास्थ्य केंद्र की सेवाएं से लाभ लेने एवं टैली मानस हेल्पलाइन नंबर 14416 का उपयोग करने हेतु छात्र.छात्राओं से अपील की गई।

जिला कांग्रेस ने राहुल गांधी के विरुद्ध एफआईआर के मुद्दे में गांधी चौक में किया प्रदर्शन

उमरिया (स्वतंत्रमत)

सोमवार 31अगस्त को शाम 6 बजे स्थानीय गांधी चौक उमरिया में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध उत्तराखंड के हल्द्वानी में अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत आफ एई आर दर्ज किए जाने के खिलाफ आज पूरे प्रदेश सहित जिला कांग्रेस कमेटी उमरिया के कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में राहुल गांधी के विरुद्ध विधि के मंशा के विरुद्ध दर्ज एफआईआर को समाप्त करने एवं राहुल गांधी जी के मांग पर हल्द्वानी के ग्राउंड में शुद्धिकरण में सम्मिलित लोगों के विरुद्ध एफआईआर किए जाने की मांग की गई है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला संगठन महामंत्री एडवोकेट पुष्पराज सिंह के नेतृत्व में कार्यक्रम संपन्न हुआ जिसमे मुख्य रूप से जिला कांग्रेस कमेटी से राहुल देव सिंह, महामंत्री वीरेंद्र सिंह सेंगर, निर्वाचन प्रभारी एडवोकेट शिशुपाल यादव, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी करकेली यशोराम राठौर एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष मोहम्मद असलम शेर युवा कांग्रेस के नेता हर्ष सिंह परिहार मंगल सिंह नगर कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष लाल भवानी सिंह, राम सिंह मंडल अध्यक्ष किशोरी सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसरी सिंह अनुज शर्मा मंगल सिंह अमित रामनारायण पांडे. उदय सिंह नानक राम राजपूत पुनीत कुमार शर्मा, कृष्ण पल राठौर, शत्रुध्न सिंह,मो.शाहिद उपस्थित रहे। अंत में जिला संगठन महासचिव एडवोकेट पुष्पराज सिंह ने कहा कि देश में भाजपा का विरोध करने वाला चाहे कोई भी हो अब सुरक्षित नहीं है यदि सामान्य आदमी है तो उसके प्रतिष्ठानों में छापे मरवा कर प्रताड़ित किया जाता है यदि राजनीतिक व्यक्ति है उनके विरुद्ध झूठ केस दर्ज कराए जाते हैं, भाजपा का कार्य निश्चित रूप से देश के निष्पक्ष लोकतंत्र की भावना के विपरीत है, कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर भाजपा की नियुक्त का विरोध करती है।

पार्षद पतियों पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के आरोप, जांच की मांग

उमरिया (स्वतंत्रमत)

चंदिया नगर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दो पार्षद पतियों को लाभ दिए जाने का मामला सामने आया है। स्थानीय स्तर पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वार्ड क्रमांक 12 एवं 13 से जुड़े पार्षद पतियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लिया है, जबकि उनकी आर्थिक स्थिति एवं संपत्ति को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप है कि वार्ड क्रमांक 13 के पार्षद पति शिवम यादव को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। इसके अलावा कटनी रोड स्थित मुख्य मार्ग पर उनके द्वारा दुकान के लिए शटरनुमा निर्माण कराए जाने की बात भी कही जा रही है। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि उनके पास कृषि भूमि, चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर सहित अन्य संपत्तियां हैं। वहीं उनकी माता के चंदिया में वरिष्ठ शिक्षक के पद पर पदस्थ होने की जानकारी भी सामने आई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर एवं पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराना है। ऐसे में यदि योजना का लाभ अपात्र व्यक्तियों को मिला है तो यह गंभीर विषय है और इसकी निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। हालांकि, लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। संबंधित अधिकारियों से योजना की पात्रता, दस्तावेजों एवं आवास स्वीकृति की प्रक्रिया की जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने की मांग की गई है। जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि योजना का लाभ नियमों के अनुरूप दिया गया है अथवा नहीं।

चंदिया नगर पंचायत में योजना के पात्रता मानदंडों को लेकर उठे सवाल

24 साल देश सेवा कर घर लौटे सेना के हवलदार

कटंगी बस स्टैंड पर ग्रामीणों ने किया भव्य स्वागत

कटंगी(स्वतंत्र मत)

भारतीय थल सेना में 24 वर्ष तक अनवरत देश की सेवा करने के बाद हवलदार के पद से सेवानिवृत्त होकर अपने गृह ग्राम सेलवा लौटे तूफान सिंह राहंगडाले का कटंगी नगर के बस स्टैंड पर ग्रामीणों और परिजनों ने जोरदार और भावुक स्वागत किया। दोपहर 1 बजे जैसे ही तूफान सिंह निजी वाहन से उतरे, पहले से उनका इंतजार कर रहे लोगों ने जय हिंद के नारों के साथ उनका अभिनंदन किया। देशभक्ति और सम्मान से भरे इस दृश्य ने वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम कर दीं। यह स्वागत केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक सैनिक के 24 साल के त्याग, तपस्या और राष्ट्र सेवा का सम्मान था। तूफान सिंह राहंगडाले भारतीय थल सेना की प्रतिष्ठित ऑल इंडिया इंजीनियरिंग वर्क ऑफ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हवलदार के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। सोमवार दोपहर 1 बजे जब वे कटंगी बस स्टैंड पहुंचे, तो वहां पहले से ही उनके पिता, भाई, ग्राम के सरपंच, उपसरपंच सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वह बस स्टैंड पहुंचे। परिजनों ने उन्हें पुष्पगुच्छ देकर और गले में फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया। ग्रामीणों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। पूरे बस स्टैंड परिसर में देशभक्ति का माहौल बन गया। कई लोगों ने उनके साथ सेल्फी ली और उनके अनुभवों को सुना। इस अवसर पर उनके पिता केशोराव राहंगडाले की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा कि उनका बेटा 24 साल तक देश की सेवा में रहा, यह पूरे परिवार और गांव के लिए गौरव की बात है। स्वागत कार्यक्रम में तूफान सिंह के भाई टेनीसिंह राहंगडाले, टीकमचंद राहंगडाले, ग्राम सेलवा के सरपंच देवेंद्र सिंह देशमुख, उपसरपंच योगेंद्र मात्रे, विष्णु देशमुख, रूपेन्द्र देशमुख, तोपसिंह देशमुख, चंदन राहंगडाले, जयसिंह राहंगडाले, चोखेन्द्र राहंगडाले सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे।

पीएमश्री शासकीय हाई स्कूल डाईट में वार्षिक शालेय पत्रिका उड़ान-मंजिल का विमोचन

बालाघाट(स्वतंत्र मत)। पीएमश्री शासकीय हाई स्कूल डाईट में विद्यालय की वार्षिक शालेय पत्रिका उड़ान-मंजिल की ओर वर्ष 2025-26 अंक का विमोचन विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्रीमती मोनिका पटेल के मुख्य आतिथ्य में किया गया। विद्यालय लगातार दूसरे सोपान में उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए अपनी शैक्षणिक एवं रचनात्मक गतिविधियों को पत्रिका के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा है। विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती गीता बंसपाल के मार्गदर्शन में प्रधान संपादक श्रीमती सुनीता कटरे एवं संतोष चौधरी द्वारा पत्रिका को आकर्षक एवं सुंदर कलेवर प्रदान किया गया है। पत्रिका में विद्यालय में वर्षभर आयोजित विभिन्न शैक्षणिक, सांस्कृतिक, खेलकूद एवं अन्य गतिविधियों को प्रमुखता से स्थान दिया गया है। पत्रिका के बाहरी आवरण पृष्ठ पर खेलो इंडिया थीम को आधार बनाते हुए वर्ष 2025 में खेल जगत की प्रमुख उपलब्धियों और आयोजनों की स्मृतियों को स्थान दिया गया है। इनमें महिला चैंपियन ट्रॉफी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, एफआईएच हॉकी महिला नेशनल कप एवं पुरुष हॉकी एशिया कप को प्रमुखता से दर्शाया गया है। पत्रिका के आंतरिक प्रथम पृष्ठ पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर विद्यालय की पूर्व छात्रा शेफाली जुम्हारे द्वारा मैथिली चित्रकला में एक्रेलिक रंगों के माध्यम से तैयार की गई कलाकृति को शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस कार्य के लिए उन्हें वर्ष 2020 में हावर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट तथा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान प्राप्त हो चुका है। शालेय पत्रिका में वर्ष 1975-76 से लेकर वर्तमान समय तक के पूर्व एवं वर्तमान विद्यार्थियों के मौलिक विचारों और लेखों को भी शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य नई पीढ़ी को पूर्व विद्यार्थियों के अनुभवों और विचारों से परिचित कराना है।

सोनेगांव में कुएं में मिला महिला का शव

कटंगी(स्वतंत्र मत)। तिरोड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम सोनेगांव में एक 32 वर्षीय महिला का शव गांव के ही एक कुएं से बरामद किया गया है। घटना से गांव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकलवाकर जांच शुरू की है। मंगलवार 01 सितंबर की दोपहर 12 बजे पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतका की पहचान गायत्री पिता मानिक लाल पारधी (32) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि 31 अगस्त की रात महिला ने अपने परिजनों के साथ सामान्य रूप से भोजन किया था। भोजन के बाद जब परिजन सोने के लिए चले गए, तब महिला घर से बाहर निकल गई। रात करीब 10 बजे उसने गांव के ही एक कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि मृतका मानसिक रूप से कमजोर थी, जिसका लंबे समय से उपचार चल रहा था। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का कारण मानसिक बीमारी ही माना जा रहा है। तिरोड़ी पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच विवेचना शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा।

6 सितम्बर को लामता बंद को विधायक मधु भगत का पूर्ण समर्थन, स्टॉपेज के लिए महाप्रबंधक को लिखा पत्र

लामता(स्वतंत्र मत)। लामता रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव सहित क्षेत्र की विभिन्न रेल सुविधाओं की मांग को लेकर लामता क्षेत्रवासियों द्वारा 6 सितम्बर 2026 को लामता बंद का आह्वान किया गया है। इस आंदोलन को परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक मधु भगत ने पूर्ण समर्थन दिया है। विधायक ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर के महाप्रबंधक को पत्र लिखकर लामता रेलवे स्टेशन पर गुजरने वाली सभी एक्सप्रेस ट्रेनों का कम से कम दो मिनट का ठहराव (स्टॉपेज) सुनिश्चित करने की मांग की है। विधायक मधु भगत ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि लगभग छह माह से उनके विधानसभा क्षेत्र के लामता रेलवे स्टेशन के आसपास के करीब 40 गांवों के ग्रामीण इस मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि लामता रेलवे स्टेशन से रेलवे को करोड़ों रुपये का राजस्व प्राप्त होता है, बावजूद इसके यहां प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों का पर्याप्त ठहराव नहीं है। पत्र में कहा गया है कि 6 सितम्बर को लामता बंद का आह्वान किया गया है और आंदोलन के माध्यम से क्षेत्र की जनता अपनी लंबे समय से लंबित मांग को रेलवे प्रशासन के समक्ष रखने जा रही है। विधायक ने स्पष्ट किया कि यदि समय रहते रेलवे प्रशासन द्वारा इस मांग पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी रेलवे प्रशासन की होगी। मधु भगत ने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि पूर्व में रेलवे विभाग द्वारा पंचवेली एक्सप्रेस को नागपुर से भोपाल के बजाय विस्तारित कर बालाघाट और गोंदिया तक चलाने संबंधी पत्र जारी किया गया था, लेकिन इस दिशा में अब तक अपेक्षित अमल नहीं हुआ है। इससे क्षेत्रवासियों में असंतोष बढ़ रहा है।विधायक ने मांग की है कि पंचवेली एक्सप्रेस को शीघ्र गोंदिया-बालाघाट से प्रारंभ किया जाए तथा लामता रेलवे स्टेशन पर इसका भी कम से कम दो मिनट का ठहराव सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अपने पत्र की प्रतिलिपि डीआरएम बिलासपुर, डीआरएम नागपुर सहित स्थानीय समाचार माध्यमों को भी भेजी है। विधायक के समर्थन के बाद 6 सितम्बर के लामता बंद को लेकर क्षेत्र में आंदोलन को और मजबूती मिलने की संभावना है।

वनांचल में थमेगी मासूमों की सांसें या बदलेगी तस्वीर!

घोषणा पर गरमाई राजनीति, 2 लाख की सहायता और 225 करोड़ भी ऊंट के मुंह में जीरा

बालाघाट(स्वतंत्र मत)

बैगा आदिवासी समाज बालाघाट की पहचान, जंगल और प्रकृति का अभिन्न हिस्सा होने के साथ इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी में से एक है। पीढ़ियों से जंगल और प्राकृतिक संसाधनों के साथ जीवन जीने वाले इस समाज के नाम पर सरकारें योजनाएं बनाती हैं, बजट जारी करती हैं और विकास के दावे करती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आज भी बैगा परिवारों का बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आवास और मूलभूत सुविधाओं के लिये संघर्ष कर रहा है। बैगा आदिवासी इस क्षेत्र के लिये बेहद आवश्यक हैं। उनकी संस्कृति, परंपराएं, जंगलों से जुड़ा पारंपरिक ज्ञान और प्रकृति के संरक्षण में उनकी भूमिका बालाघाट की पहचान है। इनके नाम पर सरकारी योजनाओं में राशि आती है, विभागों के माध्यम से योजनाएं चलती हैं, लेकिन बैगा आदिवासियों के हिस्से का कितना रुपया वास्तव में उन तक पहुंचता है और कितना सरकारी विभाग और अधिकारी डकार जाते हैं, इसकी जमीनी तस्वीर भी सामने आनी चाहिए। वर्तमान परिदृश्य यह कहता है कि जिले के दक्षिण बैहर में पिछले ढाई महीनों से मिजल्स और मलेरिया का प्रकोप जारी है। विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा और गोंड समुदाय के मासूमों की लगातार हो रही मौतों से जिले से लेकर पूरे प्रदेश तक हड़कंप मच गया है। मौतों के आंकड़ों को लेकर भी भारी घमासान छिड़ा हुआ है जहाँ सरकारी रिकॉर्ड में 10 बच्चों की मौत दर्ज है, वहीं कांग्रेस का दावा है कि 26 मासूम अपनी जान गंवा चुके हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 29 अगस्त को ग्राउंड जीरो %बोनदारी गांव% पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवारों से सीधा संवाद कर उनकी पीड़ा सुनी और प्रभावित प्रत्येक परिवार को 2-2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि देने का ऐलान किया। स्वास्थ्य संकट के साथ-साथ वनांचल की बुनियादी बदहाली को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ने एक बड़े राहत पैकेज की घोषणा की। परसवाड़ा, बैहर और लांजी विधानसभा के 100 अति-पिछड़े गांवों को चिन्हित किया गया इन गांवों में सड़क, बिजली, शुद्ध पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, कृषि और रोजगार-आजीविका के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 225 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री की इस बड़ी घोषणा के बाद बालाघाट की राजनीति उबल पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने-सामने आ गए। लांजी विधायक राजकुमार कराहे ने सरकार के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि 225 करोड़ रुपये के इस पैकेज से वनांचल के दूरस्थ गांवों में विकास की नई बयार बहेगी और स्वास्थ्य व बुनियादी सुविधाएं सुदृढ़ होंगी, तो वही बैहर विधायक व कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजय उइके ने सरकार की नीयत पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में करीब 150 बैगा बहुल गांव हैं, फिर सिर्फ 100 गांवों को ही क्यों चुना गया। सरकार ने बिना धरातलीय समीक्षा के, केवल कलेक्टर और एसपी की ओर से थमाई गई सूची पर मुहर लगा दी है। अब देखना यह होगा कि 225 करोड़ का यह पैकेज बैगा-गोंड बस्तियों की तस्वीर बदल पाता है या राजनीति की भेंट चढ़ जाता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा बैगा बहुल क्षेत्रों के लिये की गई घोषणाओं को लेकर जनपद पंचायत लांजी के उपाध्यक्ष अजय अवसरे और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बहेला के अध्यक्ष ॠषि दशरिया ने अपनी अलग-अलग प्रतिक्रिया व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने कहा कि नक्सल मुक्त बालाघाट को विकास और आत्मनिर्भरता का मॉडल बनाने की बात तभी सार्थक होगी। अवसरे ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बीमारी से मृत बच्चों के परिवारों को प्रति परिवार 2 लाख रुपये की मुआवजा राशि देने की घोषणा की है, लेकिन जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है, उनके लिये यह राशि ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। उन्होंने कहा कि सर्वांगीण विकास के लिये 225 करोड़ रुपये की घोषणा सुनने में बड़ी है, लेकिन बैगा आदिवासियों की वास्तविक जरूरतों के सामने यह भी ऊंट के मुंह में जीरा जैसी है। वर्षो से जिन गांवों में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पेयजल, रोजगार और आजीविका जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है, वहां केवल घोषणा कर देने से बैगा परिवारों का जीवन नहीं बदलने वाला।

सांदीपनि विद्यालय में रक्षाबंधन पर्व

मण्डला/निवास(स्वतंत्र मत)। सांदीपनि मॉडल विद्यालय निवास में रक्षाबंधन का पावन पर्व हर्षोल्लास एवं उत्साह के साथ मनाया गया। विद्यालय की छात्राओं ने पारंपरिक रूप से अपने भाई स्वरूप साथी छात्रों तथा विद्यालय के प्राचार्य वेद प्रकाश अवधिया को राखी बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया। इस अवसर पर छात्राओं ने अपने हाथों से राखी बांधते हुए भाई-बहन के अटूट प्रेम विश्वास एवं आपसी स्नेह का संदेश दिया। छात्राओं द्वारा प्राचार्य वेद प्रकाश अवधिया को राखी बांधने का दृश्य विशेष रूप से भावपूर्ण रहा। विद्यालय परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। छात्राओं ने राखी बांधकर भाई-बहन के रिश्ते की पवित्रता एवं भारतीय संस्कृति में निहित पारिवारिक मूल्यों को जीवंत किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय का वातावरण स्नेह, उमंग और उल्लास से भर गया।

प्रजापिता ब्रम्हाकुमारी में रक्षाबंधन पर्व

मण्डला(स्वतंत्र मत)। प्रजापिता ब्रम्हाकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्थानीय पड़ाव वार्ड सेवाकेंद्र द्वारा 148वीं बटालियन में रक्षाबंधन का पावन पर्व हर्षोल्लास एवं आध्यात्मिक वातावरण में आयोजित किया गया। देश की सुरक्षा में तत्पर सीमा सुरक्षा बल सीआरपीएफ के जवानों के त्याग और समर्पण को नमन करते हुए ब्रह्माकुमारी बहनों ने उनके उज्ज्वल भविष्य और दीर्घायु कामना की। कार्यक्रम में पड़ाव वार्ड सेंटर संचालिका ब्रम्हाकुमारी ओमलता दीदी 148वीं बटालियन के सेकंड इन कमांडेड प्रमोद कुमार यादव, डिप्टी कमांडेंट मनोरंजन कुमार, इंस्पेक्टर एम डी बंजारे, डीप्टी कमांडेंट, एसएम सूबेदार, मेजर एल बी थापाए मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इनके साथ ही बटालियन के अनेक पुलिस जवानए ब्रह्माकुमार भाई एवं बहनें बड़ी संख्या में शामिल हुए।

पति की दीर्घायु पर रखा व्रत

मण्डला(स्वतंत्र मत)। पति की दीर्घायु और खुशहाली की कामना के लिए सिंधी समाज की महिलाओं ने तीजा का व्रत रखा सुहागन महिलाएं पति की लंबी उम्र एवं कन्याएं सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए तीजा व्रत रखती हैं इसके लिए एक दिन पूर्व मेहंदी रस्म अदायगी की गई मेहंदी की आधुनिक डिजाइन को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखा गया। शाम को सामाजिक पुरोहित के घर तीजड़ी माता की कथा होती हुई जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने शामिल होकर कथा का श्रवण किया। रात्रि को चंद्र देव की पूजा की गई। इस अवसर पर पति ने पत्नियों को उपहार भेंट किया और दिन को यादगार बनाया।

त्वरित निराकरण के दिए निर्देश

मण्डला(स्वतंत्रमत)। जिला योजना भवन में कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन द्वारा आम नागरिकों की समस्याओं और शिकायतों को पूर्ण संवेदनशीलता के साथ सुना गया एवं उनका समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जनसुनवाई के दौरान जिले के दूर-दराज के क्षेत्रों से आए 80 आवेदकों ने अपनी व्यक्तिगत व सार्वजनिक समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर ने एक-एक कर सभी आवेदकों की समस्याएं गंभीरतापूर्वक सुनीं और मौके पर ही संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए। कलेक्टर ने जनसुनवाई में उपस्थित समस्त अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि आम जनता की समस्याओं का निराकरण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

बंजारा समाज का पारंपरिक तीज पर्व

मण्डला/मवई(स्वतंत्रमत)। मवई विकासखंड अंतर्गत ग्राम भीमडोंगरी में मुकेश नायक के निज निवास पर बंजारा समाज का सुप्रसिद्ध एवं पारंपरिक तीज पर्व हर्षोल्लास श्रृद्धा और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। श्रावण मास में प्रारंभ हुआ यह नौ दिवसीय पर्व प्रकृति पूजा लोक संस्कृति परंपराओं एवं लोक कलाओं का सुंदर संगम रहा पर्व के अंतिम दिन बंजारा समाज की युवतियों एवं महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा एवं आकर्षक आभूषणों से सज-संवरकर पारंपरिक तीज नृत्य प्रस्तुत किया। ढोल की थाप और लोकगीतों की मधुर धुन पर महिलाओं एवं पुरुषों ने सामूहिक रूप से नृत्य किया। बंजारा समाज में तीज पर्व की शुरुआत नौ दिन पूर्व विशेष टोकरियों में गेहूं के ज्वारे बोने के साथ हुई थी नौ दिनों तक युवतियों द्वारा ज्वारों की सेवा एवं पूजा-अर्चना की गई तथा पारंपरिक गीतों के माध्यम से प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में हनुमान जाट, भागवत प्रसाद गहलोत, तारेंद्र नायक, हजारी लाल राठौर, रूप सिंह गहलोत, टेकराम गहलोत, साहेब नायक, बिसाहू नायक, अक्षय परते सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं स्वजातीय समाजजन, महिला-पुरुष उपस्थित रहे।

कृषि विभाग की जांच सिर्फ कागजों तक,लाइसेंस किसी के नाम कृषि केंद्र चला रहा कोई,किसानों की फसल पर दांव

मण्डला(स्वतंत्रमत)

जिले भर में कृषि बीज भंडार की दुकानें लगातार खुल रही हैं। इनके संचालक के पास डिग्री डिप्लोमा है कि नही यह सवालों के घेरे में दिखाई दे रहा है गांव देहात में ही नही शहर में भी बिना लायसेंस के दुकानों का संचालन हो रहा है। अनपढ़ अशिक्षित दसवीं आठवीं फेल लोगो के द्वारा दुकानों का संचालन किया जा रहा है किसानों को न तो सलाह दी जा रही है और न ही खरीदी किए जा रही कीटनाशक बीज के बिल दिए जा रहे हैं किराये के लायसेंस पर दुकानों का संचालन हो रहा है। जिले में किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज खाद कीटनाशक और कृषि संबंधी सही सलाह उपलब्ध कराने के लिए बड़ी संख्या में कृषि बीज भंडार और कृषि केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। लेकिन इन दुकानों के संचालन को लेकर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। किसानों और सूत्रों की मानें तो जिले में कई ऐसे कृषि केंद्र हैं जिनका लाइसेंस किसी व्यक्ति के नाम पर जारी है जबकि दुकान का संचालन कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है। यानी कागजों में दुकान किसी और की और जमीन पर कारोबार किसी और के हाथ में होने की बात सामने आ रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि किसी कृषि केंद्र का लाइसेंस उस व्यक्ति के नाम पर जारी किया गया है जिसके पास कृषि संबंधी आवश्यक जानकारी और अनुभव और लायसेंस है तो उसकी अनुपस्थिति में दुकान का संचालन किसी दूसरे व्यक्ति से कराया जा रहा है तो किसानों को सही सलाह कौन देगा बीज की किस्म, उसकी गुणवत्ता, बुवाई का समय, मात्रा, रोग नियंत्रण और कीटनाशकों के इस्तेमाल की जानकारी किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में यदि दुकान पर बैठा व्यक्ति कृषि संबंधी पर्याप्त जानकारी नहीं रखता है तो इसका सीधा असर किसान की फसल और उसकी लागत पर पड़ सकता है।

कृषि निगरानी व्यवस्था पर सवाल- जिले में शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक बड़ी संख्या में कृषि केंद्र संचालित हैं। खेती-किसानी के सीजन में इन दुकानों पर किसानों की भीड़ लगी रहती है। किसान यहां से बीज खाद कीटनाशक और फसल में लगने वाले रोगों के लिए दवाएं खरीदते हैं। कई किसान दुकान संचालक की सलाह पर ही दवा और बीज का चयन करते हैं। यही वजह है कि कृषि केंद्र संचालक की जिम्मेदारी महज सामान बेचने तक सीमित नहीं रहती। किसान के लिए दुकान संचालक कई बार पहली सलाह का माध्यम होता है। यदि उसे ही फसल बीज और दवाओं के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है तो किसान गलत सलाह का शिकार हो सकता है। सूत्रों का दावा है कि कुछ स्थानों पर लाइसेंसधारी व्यक्ति स्वयं दुकान पर मौजूद नहीं रहता और उसके नाम से जारी लाइसेंस के आधार पर दूसरा व्यक्ति कारोबार संचालित करता है।

मौके पर कौन चला रहा दुकान- कृषि केंद्रों की जांच के दौरान दस्तावेजों की जांच की जाती है। लाइसेंस, बिल, स्टॉक रजिस्टर और अन्य जरूरी कागजात देखे जाते हैं। लेकिन यदि वास्तविकता यह है कि लाइसेंस किसी और के नाम पर है और दुकान का संचालन कोई अन्य व्यक्ति कर रहा है तो केवल दस्तावेज देखकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकती। ऐसे मामलों में विभाग को यह भी देखना होगा कि लाइसेंसधारी व्यक्ति वास्तव में दुकान का संचालन कर रहा है या नहीं। दुकान पर कौन बैठता है किसानों को कौन सलाह देता है बीज और कीटनाशक की बिक्री कौन करता है और स्टॉक का रखरखाव किसके द्वारा किया जा रहा है इन बिंदुओं की मौके पर जांच जरूरी है।

किसान बोले हर तरफ मची लूट - नाम नहीं छापने की शर्त पर एक किसान ने बताया कि उसने मंडला शहर के एक कृषि केंद्र से बीज खरीदा था। बुवाई के बाद खेत में अपेक्षा के अनुसार फसल नहीं उग सकी। इसके बाद फसल को बचाने के लिए अलग-अलग दवाओं का छिड़काव कराया जा रहा है। किसान के अनुसार एक समस्या खत्म नहीं होती कि दूसरी समस्या सामने आ जाती है। किसान का कहना है कि खेती पहले ही महंगी हो चुकी है। बीज खाद दवा मजदूरी और सिंचाई पर लगातार खर्च करना पड़ता है। यदि बीज के चयन या कृषि संबंधी सलाह में कहीं गलती हो जाए तो उसका नुकसान सीधे किसान को उठाना पड़ता है। ऐसे में किसान के पास दुकान संचालक की सलाह पर भरोसा करने के अलावा कई बार कोई विकल्प नहीं होता।

गलत सलाह से होता नुकसान - कृषि विशेषज्ञों के अनुसार बीज का चयन मिट्टी मौसम क्षेत्र और फसल की स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। इसी तरह किसी रोग या कीट के नियंत्रण के लिए दवा का इस्तेमाल भी विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार होना चाहिए। गलत दवा गलत मात्रा या गलत समय पर किया गया छिड़काव फसल को नुकसान पहुंचा सकता है और किसान की लागत भी बढ़ा सकता है।

विभाग की कागजी कार्यवाही - किसानों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। उनका कहना है कि जांच के दौरान कागजों को देखकर औपचारिकता पूरी कर दी जाती है जबकि वास्तविक स्थिति जानने के लिए दुकान का मौके पर निरीक्षण और संचालनकर्ता का सत्यापन जरूरी है। यदि जिले में बड़ी संख्या में ऐसे कृषि केंद्र संचालित हो रहे हैं तो कृषि विभाग को तहसील और विकासखंड स्तर पर विशेष जांच अभियान चलाकर सभी लाइसेंसधारी दुकानों का भौतिक सत्यापन करना चाहिए। जांच में यह भी देखा जाना चाहिए कि लाइसेंस किसके नाम पर है और वास्तविक रूप से दुकान कौन संचालित कर रहा है।

पटवारियों ने फार्मर आईडी कार्य का किया बहिष्कार

मण्डला

मध्यप्रदेश पटवारी संघ ने पटवारियों की विभिन्न लंबित मांगों का निराकरण नहीं होने पर 1 सितंबर से फार्मर आईडी से संबंधित कार्यों के बहिष्कार का निर्णय लिया है। इस संबंध में संघ के मंडला जिलाध्यक्ष गीतेन्द्र गीतू बैरागी ने कलेक्टर को पत्र सौंपकर मांगों के निराकरण की जानकारी दी है। पटवारी संघ द्वारा शासन के समक्ष हड़ताल अवधि के वेतन कैडर रिव्यू कमेटी के आदेश पदाधिकारियों के नीति विरुद्ध स्थानांतरण निरस्त करने फार्मर आईडी की तकनीकी समस्या तथा पटवारी स्तर पर फसल गिरदावरी से जियो टैग हटाने सहित विभिन्न मांगें रखी गई हैं। पटवारी संघ का कहना है कि पूर्व में इन समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया गया था लेकिन निर्धारित समय बीतने के बाद भी अपेक्षित निराकरण नहीं हुआ। फार्मर आईडी को लेकर प्रदेश के विभिन्न जिलों में पटवारियों पर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। पटवारी संघ का आरोप है कि फार्मर आईडी में आ रही तकनीकी एवं व्यावहारिक समस्याओं का समाधान राज्य स्तर से नहीं होने के बावजूद इसका खामियाजा पटवारियों को भुगतना पड़ रहा है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर बिना उचित कारण फसल गिरदावरी का कार्य कराया जा रहा है जबकि पटवारी स्तर पर फसल गिरदावरी से जियो टैग हटाने की मांग भी पूर्व में रखी जा चुकी है। पटवारी संघ ने चेतावनी दी है कि यदि 1 सितंबर तक समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाता है तो प्रदेश के पटवारी फार्मर आईडी के कार्य से विरत रहेंगे। इस दौरान किसी जिले में पटवारियों पर दंडात्मक कार्रवाई किए जाने पर प्रदेशभर के पटवारी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इसकी जिम्मेदारी शासन की होने की बात कही है। पत्र की प्रतिलिपि मध्यप्रदेश पटवारी संघ भोपाल के प्रांताध्यक्ष तथा संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई है। मध्यप्रदेश पटवारी संघ भोपाल के विगत आंदोलन के स्थगित किए जाने के पूर्व पीआर सी भवन भोपाल स्थित 6 अगस्त की बैठक में प्रदेश के जिलाध्यक्षो एवं प्रदेश पदाधिकारियों के समक्ष कैडर रिव्यू कमेटी गठन आदेश देने पदाधिकारियों के अनुचित स्थानांतरण निरस्त करने तथा हड़ताल अवधि को कार्य दिवस मानकर आदेश प्रसारित करने हेतु आपके द्वारा सभी के समक्ष आश्वस्त किया गया था। इसके अतिरिक्त फसल गिरदावरी तथा अन्य समस्याओं के शीघ्र निराकरण हेतु आश्वस्त किया था। जिसके पश्चात आपसे एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से चर्चा उपरांत किसान हित में जन विश्वास अभियान को देखते हुए तथा आप दोनों के आश्वासन पश्चात हड़ताल आगामी तीन माह के लिए स्थगित कर दी गई थी। किंतु आज दिनांक तक आपके द्वारा आश्वस्त उक्त किसी भी समस्या का कोई निराकरण नहीं किया गया है।

पंचायतों में उप निर्वाचन की तैयारियां

मण्डला(स्वतंत्रमत)। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में पंचायत उप निर्वाचन 2026 के लिए प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिले की संबंधित ग्राम पंचायतों में उप निर्वाचन संपन्न कराने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार मंडला, नैनपुर, बिछिया, मवई, निवास, घुघरी, नारायणगंज, मोहगांव एवं बीजाडांडी जनपद पंचायतों की संबंधित ग्राम पंचायतों में रिक्त पदों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया कराई जाएगी। अधिकारियों को निर्वाचन संबंधी आवश्यक कार्रवाई निर्धारित समय-सारणी के अनुसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में बताया गया है कि ग्राम पंचायत मंडला में पंच के 27 तथा सरपंच के 1 पद, नैनपुर में पंच के 7 व सरपंच के 1 पद, बिछिया में पंच के 7 पद, मवई में पंच एवं सरपंच के 1-1 पद, निवास में पंच के 3 पद, घुघरी में पंच के 7 पद, नारायणगंज में पंच एवं सरपंच के 1-1 पद, बीजाडांडी में पंच के 6 एवं सरपंच के 1 पद तथा मोहगांव में पंच के 4 पद रिक्त बताए गए हैं।

सरस्वती विद्यालय की बहनों ने बांधी राखी

मण्डला/बिछिया (स्वतंत्रमत)

रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सरस्वती शिशु उच्च माध्यमिक विद्यालय भुआबिछिया की छात्राओं ने बिछिया थाना में पुलिसकर्मियों की कलाई पर राखी बांधी थाना परिसर में आयोजित कार्यक्रम में बहनों ने पुलिसकर्मियों को रक्षा सूत्र बांधकर उनके स्वस्थ सुरक्षित एवं दीर्घायु जीवन की कामना की इस अवसर पर छात्राओं ने थाना प्रभारी निरीक्षक रंजीत कुमार सैयाम, उपनिरीक्षक विजयवार, सहायक उपनिरीक्षक बालमुकुंद चौरसिया सहित थाने के पुलिस स्टाफ को राखी बांधी पुलिसकर्मियों ने भी बहनों की रक्षा और सुरक्षा का संकल्प लेते हुए उन्हें उपहार प्रदान किए तथा स्नेह एवं आशीर्वाद दिया रक्षाबंधन के इस आत्मीय आयोजन से थाना परिसर में उत्साह और भाई-बहन के स्नेह का वातावरण बना रहा। कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंधन की ओर से प्रबंधक राम बहोरी पटेल, व्यवस्थापक रिखी राम परस्ते, सह व्यवस्थापक अरुण मिश्रा, जिला सचिव किशोरी लाल साहू, प्राचार्य प्रहलाद सिंह मरकाम व्यवस्था प्रमुख आकाश चौरसिया सहित विद्यालय का स्टाफ उपस्थित रहा।

नैनपुर रेलवे समपार पर ओवरब्रिज निर्माण की कवायद तेज

रेलवे और राजस्व अमले ने किया पहला स्थल परीक्षण

नैनपुर (स्वतंत्र मत)। नैनपुर-सिवनी मुख्य मार्ग स्थित रेलवे समपार पर प्रस्तावित ओवरब्रिज निर्माण की प्रक्रिया अब धरातल पर आगे बढ़ने लगी है। इसी क्रम में सोमवार को रेलवे एवं राजस्व विभाग के संयुक्त अमले द्वारा मौके पर पहुंचकर पहला स्थल परीक्षण एवं सर्वे किया गया। जिला कलेक्टर के निर्देश पर किए गए इस परीक्षण के दौरान प्रस्तावित ओवरब्रिज के निर्माण से जुड़े विभिन्न बिंदुओं का मौके पर निरीक्षण किया गया।

दरअसल, नैनपुर-सिवनी मुख्य मार्ग पर स्थित रेलवे समपार से प्रतिदिन बड़ी संख्या में वाहनों का आवागमन होता है। ट्रेनों के आवागमन के दौरान समपार के बार-बार बंद होने से सड़क यातायात प्रभावित होता है। समपार बंद रहने के दौरान दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगने से जाम की स्थिति निर्मित होती है। इसका सीधा असर नगर की यातायात व्यवस्था पर पड़ता है और वाहन चालकों के साथ आम नागरिकों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को देखते हुए क्षेत्रवासी लंबे समय से इस स्थान पर ओवरब्रिज निर्माण की मांग कर रहे थे। अब प्रस्तावित ओवरब्रिज की निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़ने से लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। जानकारी के अनुसार करीब 700 मीटर लंबा ओवरब्रिज प्रस्तावित है, जिसका निर्माण रेलवे समपार के दोनों ओर किया जाना है। ब्रिज बनने के बाद रेलवे फाटक पर निर्भरता कम होगी और वाहनों को निर्बाध आवागमन की सुविधा मिल सकेगी।

अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया प्रस्तावित- ओवरब्रिज निर्माण के लिए रेलवे विभाग द्वारा मौके पर मौजूद अतिक्रमण को हटाने के संबंध में नगर पालिका एवं राजस्व विभाग को पूर्व में ही पत्र भेजा जा चुका है। निर्माण कार्य शुरू होने से पहले प्रस्तावित स्थल को व्यवस्थित करने और आवश्यक भूमि संबंधी प्रक्रिया पूरी करने की कवायद भी की जानी है। इसी सिलसिले में राजस्व एवं रेलवे अमले द्वारा संयुक्त रूप से स्थल का परीक्षण किया गया। पहले सर्वे के दौरान प्रस्तावित ब्रिज के एलाइनमेंट, स्थल की स्थिति तथा निर्माण से जुड़े अन्य तकनीकी एवं राजस्व पहलुओं का प्रारंभिक तौर पर परीक्षण किया गया। आगामी चरणों में सर्वे और भूमि संबंधी प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य की दिशा में आगे की कार्रवाई होने की उम्मीद है।

लंबे समय से चली आ रही मांग को मिलेगा समाधान- नैनपुर का यह रेलवे समपार नगर के प्रमुख मार्ग पर स्थित होने के कारण यातायात की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। फाटक बंद होने पर लगने वाला जाम कई बार मुख्य मार्ग से नगर के भीतर तक पहुंच जाता है। ऐसे में ओवरब्रिज निर्माण को नगर की यातायात व्यवस्था सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब स्थल परीक्षण शुरू होने के बाद लंबे समय से चली आ रही ओवरब्रिज की मांग के मूर्त रूप लेने की उम्मीद जगी है।

प्रखंड अध्यक्ष बनाए गये दिनेश श्रीवास्तव

नैनपुर (स्वतंत्र मत)। मंगल भवन वार्ड क्रमांक 11 में 31 अगस्त को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रखंड नैनपुर की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला मंत्री ललित जल, उपाध्यक्ष महेंद्र ठाकुर, विभाग मंत्री अमित बैरागी, मंत्री अनिकेत चौरसिया, संगठन मंत्री सुरेंद्र धुर्वे, बजरंग दल के जिला संयोजक संकेत सोनी एवं प्रांत संगठन मंत्री जितेन्द्र कुमार की उपस्थिति रही। इस दौरान बड़ी संख्या में नेटवर्क प्रखंड के समस्त पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। प्रांत संगठन मंत्री के द्वारा प्रखंड नैनपुर के नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। प्रखंड अध्यक्ष के पद पर दिनेश श्रीवास्तव नैनपुर मनोनीत किया गया। इसके बाद प्रखंड उपाध्यक्ष के पद पर योगेश ठाकुर ग्राम ओहनी, प्रखंड उपाध्यक्ष मंगल मरावी ग्राम मालीवाड़ा, सह मंत्री अनूप बर्मन नैनपुर , सहमंत्री ध्रुव विश्वकर्मा नैनपुर , सह संयोजक अरविंद चौहान कन्हारगांव, सह संयोजक टिकेश नाग ग्राम अंडिया , सत्संग प्रमुख दीपक ठाकुर समनापुर , गोरक्षा प्रमुख गुरु नंदा नैनपुर, सेवा प्रमुख पवन ठाकुर मोहगांव , धर्म प्रसार प्रमुख राजा चक्रवर्ती नैनपुर , विद्यार्थी प्रमुख शुभम ठाकुर अलीपुर को मनोनीत किया गया। आप सभी को अपने अपने कर्तव्य निष्ठा से कार्य करते रहने की अपेक्षा जताई गई।

संपादकीय

राजनीति का अमोघ अस्त्र

भारत में आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह राजनीति और चुनाव का अमोघ अस्त्र बन चुका है। संविधान में भी अनुच्छेद 340, 341 में उल्लेख है कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक विषमताओं, विसंगतियों को खत्म करने और कुछ समुदायों को समानता की मुख्यधारा में लाने को आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है। यह व्यवस्था आजादी और संविधान लागू होने के बाद सिर्फ 10 सालों के लिए थी, लेकिन 79 साल की आजादी के बाद भी जारी है और उसे निरंतर जारी रखना सरकारों की विवशता भी है। आरक्षण संवैधानिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार भी नहीं है, सिर्फ एक व्यवस्था है, जिसे बढ़ाया जाता रहा है। अनुच्छेद 15 और 16 में आरक्षण की शक्ति राज्य को दी गई है, लेकिन सर्वोच्च अदालत यह भी स्पष्ट कर चुकी है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि एक व्यवस्था है। संविधान में आर्थिक रूप से गरीब, कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था क्यों नहीं की गई, इसका जवाब हम नहीं दे सकते। क्या ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, भूमिहार आदि सवर्ण वर्ग 'गरीब' नहीं हैं? हमारे पुरखों ने यह कल्पना क्यों नहीं की? क्या उस समय देश में कोई भी सवर्ण 'कमजोर' नहीं था? ये सवाल निरंतर अनुत्तरित रहेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए 10 फीसदी का आरक्षण संसद से पारित कराया था, जिसे सर्वोच्च अदालत ने भी न्यायिक माना, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। दरअसल छिद्र और विसंगतियां आरक्षण की व्यवस्था में हैं। उस संदर्भ में सर्वोच्च अदालत ने क्रीमी लेयर का फैसला सुनाया था। क्रीमी लेयर की आय-सीमा 8 लाख रुपए सालाना तय है। उससे अधिक आय वाले आरक्षित वर्गों के बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन यह न्यायिक व्यवस्था पूरी तरह लागू नहीं है। हम ऐसे कई परिवारों को जानते हैं, जिनमें पीढ़ी-दर-पीढ़ी आईएएस, आईपीएस अधिकारी हैं। उनके परिवारों को आरक्षण क्यों चाहिए? या क्यों दिया जाना चाहिए? लोकसभा में 131 सांसद आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति के 84 और जनजाति के 47 सांसद हैं। राज्यों की विधानसभाओं में भी सैकड़ों आरक्षित विधायक हैं। मंत्री, राज्यमंत्री और अन्य पदों पर भी आरक्षित चेहरे हैं। यदि राष्ट्रीय स्तर के चेहरों का उल्लेख करें, तो बसपा प्रमुख एवं उप्र की चार बार मुख्यमंत्री रहीं मायावती, लोकसभा सांसद एवं उप्र के ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और रामदास अठावले आदि के परिवारों और बच्चों को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? पासवान परिवार में रामविलास पासवान (अब दिवंगत) के समय से भाई, भतीजा, दामाद सभी सत्ता में रहे अथवा सांसद-विधायक रहे। आखिर सामाजिक पिछड़ेपन, विषमताओं से उबरने का मापदंड क्या है? यह सरकारों ने तय नहीं किया और सर्वोच्च अदालत ने भी कोई फैसला नहीं सुनाया। राजनीति और सरकारें तो आरक्षण के सामने नतमस्तक हैं, बंधक बनी हैं। क्रीमी लेयर की परवाह कौन करता है? आप शिक्षित हैं, आर्थिक रूप से सम्पन्न हैं, सामाजिक रुतबा भी है, विषमताओं से बाहर आने का और क्या आधार होना चाहिए? अब आरक्षण का मुद्दा उठा है, तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जैसे नेतागण इस मुद्दे पर विमर्श को ही तैयार नहीं हैं। आरक्षण को संवैधानिक अधिकार करार दे रहे हैं। विपक्ष ने एक बार फिर नेरेटिव गढ़ना शुरू कर दिया है कि भाजपा-संघ आरक्षण के साथ-साथ संविधान को भी खत्म करना चाहते हैं। यही नेरेटिव 2024 के लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल किया गया था। गृहमंत्री अमित शाह संसद में वक्तव्य दे चुके हैं कि यदि बाबा अंबेडकर भी आज आ जाएं, तो भी आरक्षण खत्म नहीं होगा। समीक्षा में क्या दिक्कत है? सवर्ण भी तो देश के नागरिक हैं।

सीमा विवाद की कठिन डगर

हालिया वार्ताएं संबंधों में एक नए चरण की शुरुआत कर सकती हैं, भारत-चीन के बीच राह लंबी

आनंद कुमार

भारत-चीन के बीच सीमा समाधान की राह लंबी और कठिन है। फिर भी, यदि वर्तमान गति बनी रहती है और 'अर्ली हार्वेस्ट', यानी कुछ क्षेत्रों में शीघ्र सीमा निर्धारण की अवधारणा को स्पष्ट उद्देश्य, समय-सीमा और ठोस विषयवस्तु मिलती है, तो हालिया वार्ताएं संबंधों में एक नए चरण की शुरुआत कर सकती हैं।

भारत और चीन के संबंध एक बार फिर ऐसे मोड़ पर हैं, जहां वर्षों की सैन्य तनातनी, कूटनीतिक अविश्वास और वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर लंबे गतिरोध के बाद दोनों देश संबंधों को स्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच विशेष प्रतिनिधि स्तर की हालिया वार्ता इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। खास बात यह है कि बातचीत अब केवल सीमा पर तनाव को नियंत्रित करने तक सीमित नहीं दिखती, बल्कि दोनों पक्षों ने सीमा निर्धारण में 'शीघ्र और ठोस प्रगति' की बात भी की है। यह सकारात्मक संकेत है, पर असली परीक्षा यह होगी कि इस अभिव्यक्ति को ठोस वार्ता प्रक्रिया और वास्तविक प्रगति में कितना बदला जा सकता है।

पिछले दो दशकों से भारत और चीन ने अपने मतभेदों को अलग-अलग रखने की कोशिश की। सीमा विवाद के बावजूद, आर्थिक संबंध तेजी से बढ़े, व्यापार बढ़ा और दोनों देश ब्रिक्स समेत अनेक बहुपक्षीय मंचों पर साथ काम करते रहे। लेकिन, परस्पर आर्थिक निर्भरता सीमा विवाद से पैदा हुए रणनीतिक अविश्वास को दूर नहीं कर सकी। वर्ष 2020 के गलवां संघर्ष और पूर्वी लद्दाख में लंबे सैन्य गतिरोध ने पुराने समीकरण बदल दिए। इससे स्पष्ट हुआ कि सीमा पर शांति केवल मौजूदा व्यवस्थाओं के सहारे अनिश्चितकाल तक कायम नहीं रखा जा सकता। इसके बाद दोनों देशों ने सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के माध्यम से तनाव कम करने का प्रयास किया। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत-चीन संबंध पुराने दौर में लौट आए हैं। दोनों देश अब एक ऐसे संबंध की तलाश कर रहे हैं, जिसमें रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के साथ स्थिरता और संवाद के लिए भी जगह हो।

विशेष प्रतिनिधियों की हालिया वार्ता का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि इसमें सीमा प्रबंधन से आगे बढ़कर सीमा निर्धारण पर ध्यान देने की इच्छा दिखाई दी है। सैन्य कमांडरों की बैठक, राजनयिक संपर्क और अन्य संवाद तंत्र ने स्थानीय घटनाओं को बड़े संघर्ष में बदलने से रोकने में भूमिका निभाई है। एलएसी के कई हिस्सों में सीमा स्पष्ट रूप से निर्धारित न होने के कारण गश्त के दौरान दोनों देशों के सैनिक आमने-सामने आ जाते हैं। बेहतर संचार गलतफहमी और आकस्मिक तनाव को रोक सकता है। लेकिन, संकट प्रबंधन सीमा विवाद का स्थायी विकल्प नहीं हो सकता। इसी कारण 'अर्ली हार्वेस्ट', यानी कुछ क्षेत्रों में शीघ्र सीमा निर्धारण की अवधारणा महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में 2005 के 'राजनीतिक मानदंडों और मार्गदर्शक सिद्धांतों' संबंधी समझौते की पुनर्पुष्टि महत्वपूर्ण है। इसमें विशेष प्रतिनिधियों को सीमा विवाद के समाधान के लिए व्यापक रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके बाद सीमा का निर्धारण व सीमांकन होना था। इसका पुनः उल्लेख बताता है कि दोनों पक्ष मौजूदा कूटनीतिक ढांचे को बनाए रखना चाहते हैं। अब असली चुनौती इन सिद्धांतों को ऐसे संवाद में बदलने की है, जिससे ठोस नतीजे हासिल हो सकें।

भारत व चीन, दोनों समझते हैं कि एलएसी पर लगातार तनाव उनके हित में नहीं है। चीन को अपनी व्यापक आर्थिक और रणनीतिक प्राथमिकताओं पर ध्यान देने के लिए स्थिर वातावरण चाहिए, जबकि भारत भी चीन के साथ सीमा तनाव को अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं पर अनिश्चितकाल तक हावी नहीं रहने देना चाहेगा। ब्रिक्स और वैश्विक दक्षिण से जुड़े मंचों पर दोनों देशों के बीच संवाद जारी है। फिर भी, इसे रणनीतिक मेल-मिलाप नहीं माना जाना चाहिए। भारत-चीन संबंधों के लिए 'प्रतिस्पर्धी सह-अस्तित्व' अधिक उपयुक्त अवधारणा है। दोनों देशों के बीच मतभेद सीमा विवाद से आगे भी हैं।

दक्षिण एशिया और हिंद महासागर में प्रतिस्पर्धा, चीन-पाकिस्तान संबंध, चीन की क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाएं, भारत की अमेरिका और अन्य हिंद-प्रशांत देशों के साथ साझेदारी तथा एशिया की भावी क्षेत्रीय व्यवस्था को लेकर दोनों के दृष्टिकोण में अंतर बना हुआ है। दोनों देशों के बीच मतभेद सीमा विवाद से आगे भी हैं। दक्षिण एशिया और हिंद महासागर में प्रतिस्पर्धा, चीन-पाकिस्तान संबंध, चीन की क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाएं, भारत की अमेरिका और अन्य हिंद-प्रशांत देशों के साथ साझेदारी तथा एशिया की भावी क्षेत्रीय व्यवस्था को लेकर दोनों के दृष्टिकोण में अंतर बना हुआ है। इसलिए, सीमा पर तनाव कम होने का अर्थ व्यापक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का अंत नहीं है।

चीन निकट भविष्य में पूरे विवाद के समाधान के बजाय क्रमिक प्रगति को प्राथमिकता दे सकता है। भारत को इस अवसर का उपयोग करना चाहिए, पर यह भी सुनिश्चित करना होगा कि क्रमिकता सीमा विवाद को अनिश्चितकाल तक टालने का माध्यम न बन जाए। सीमा पार नदियों पर सहयोग भी विश्वास निर्माण में उपयोगी हो सकता है। जल संबंधी आंकड़ों के आदान-प्रदान और विशेषज्ञ स्तर की बातचीत से गलतफहमियां कम की जा सकती हैं। इसी तरह सीमा व्यापार केंद्रों को फिर से खोलना और कैलाश मानसरोवर यात्रा को बढ़ावा देना संबंधों के सामान्यीकरण को व्यावहारिक आधार दे सकता है। फिर भी, अत्यधिक आशावादी होने का कारण नहीं है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर जारी विवाद बताता है कि क्षेत्रीय संप्रभुता का प्रश्न अब भी बेहद संवेदनशील है। भारत द्वारा अरुणाचल प्रदेश के 27 स्थानों के नाम घोषित किए जाने पर चीन की प्रतिक्रिया इसका उदाहरण है। सामान्यीकरण का अर्थ एक-दूसरे के क्षेत्रीय दावों को स्वीकार करना नहीं है। ऐसे में, छोटे प्रतीकात्मक कदम भी राजनीतिक तनाव पैदा कर सकते हैं।

अजीत डोभाल की बीजिंग यात्रा का समय भी महत्वपूर्ण है। यह नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले हुई है, जिसमें शी जिनपिंग के शामिल होने की उम्मीद है। यदि प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग की मुलाकात होती है, तो वह सीमा पर बनी सकारात्मक गति को राजनीतिक दिशा देने का अवसर हो सकती है। हालांकि, किसी बड़े समझौते की उम्मीद करना जल्दबाजी होगी। फिर भी, दोनों देश संकट प्रबंधन से आगे बढ़कर प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित करने और स्थिरता के लिए संस्थागत व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अंततः सफलता का पैमाना यही होगा कि क्या यह प्रक्रिया एलएसी पर तनाव नियंत्रित करने से आगे बढ़कर सीमा विवाद के समाधान की दिशा में जाती है। भारत को सीमा पर शांति के प्रयासों का स्वागत करना चाहिए, पर यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सीमा पर शांति और सीमा समाधान की वार्ता साथ-साथ आगे बढ़े। केवल स्थिरता हासिल करके विवाद को अनिश्चितकाल तक टालना स्थायी समाधान नहीं होगा।

भारत-चीन के बीच सीमा समाधान की राह लंबी और कठिन है। फिर भी, यदि वर्तमान गति बनी रहती है और 'अर्ली हार्वेस्ट' को स्पष्ट उद्देश्य, समय-सीमा और ठोस विषयवस्तु मिलती है, तो हालिया वार्ताएं संबंधों में एक नए चरण की शुरुआत कर सकती हैं। वास्तविक सफलता सामान्य दिखने वाले संबंध नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था होगी, जिसमें एलएसी पर शांति और एक स्वीकार्य सीमा समाधान की दिशा में प्रगति एक-दूसरे को मजबूत करें।

(लेखक सामरिक व सुरक्षा मुद्दों के विशेषज्ञ हैं।)

बिहार के 'सहयोग मॉडल' से बाकि राज्यों को भी सीखने की जरूरत

संजीव कुमार मिश्र

क्या किसी सरकारी स्कूल या हॉस्टल में गंदा पानी, खराब खाना या बिजली की किल्लत जैसी रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान 30 दिन के भीतर पाना संभव है?...जहां देश के अधिकांश राज्यों में छात्र ऐसी बुनियादी सुविधाओं के लिए महीनों प्रशासनिक चक्कर काटने या सड़कों पर उतरने को मजबूर होते हैं, वहीं बिहार सरकार ने एक पारदर्शी ऑनलाइन व्यवस्था से इस धारणा को बदलने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा शुरू की गई इस नई पहल ने छात्र शिकायतों के निपटारे का एक ऐसा मॉडल पेश किया है, जिसकी गूंज अब देश भर में सुनाई दे रही है।

छात्रों की शिकायतें अक्सर लंबे समय तक अनसुलझी रहती हैं, इसकी बड़ी वजह प्रशासनिक प्रक्रिया की जटिलता है। किसी छात्र को हॉस्टल की सफाई, भोजन की गुणवत्ता, बिजली-पानी या फीस से जुड़ी दिक्कत होने पर पहले वार्डन, फिर प्रिंसिपल और जरूरत पड़ने पर जिला शिक्षा कार्यालय तक जाना पड़ता है। इस प्रक्रिया में न तो कोई तय समयसीमा होती है और न ही स्पष्ट जवाबदेही तय होती है, जिस वजह से छोटी शिकायतें भी हफ्तों-महीनों तक लंबित रह जाती हैं। बिहार सरकार के विद्यार्थी सहयोग पोर्टल की खासियत यह है कि शिकायत दर्ज कराने के लिए दो अलग कैटेगरी बनाई गई हैं - पहली, शैक्षणिक संस्थान यानी विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से संबंधित विद्यार्थियों के लिए, और दूसरी, छात्रावास यानी हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए। पोर्टल के होमपेज पर ही यह दोनों विकल्प दिए गए हैं, जिससे छात्र सही कैटेगरी चुनकर सीधे संबंधित फॉर्म तक पहुंच जाता है। कैटेगरी चुनने के बाद छात्र के सामने एक सीधा-सादा फॉर्म खुलता है, जिसमें नाम, लिंग, पिता का नाम, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर जैसी बुनियादी जानकारी भरनी होती है। ईमेल आईडी को वैकल्पिक रखा गया है, ताकि जिन छात्रों के पास ईमेल नहीं है वे भी शिकायत दर्ज करा सकें, जबकि मोबाइल नंबर को ओटीपी से वेरिफाई करता है ताकि हर शिकायत असली छात्र की ओर से ही दर्ज हो।

पोर्टल पर छात्रों के लिए तीन सुविधाएं दी गई हैं। शिकायत दर्ज कराने का विकल्प हॉस्टल सुविधाओं, भोजन, स्वच्छता, सुरक्षा और बिजली से जुड़ी समस्याओं के लिए है। इसके अलावा छात्र व्यवस्था सुधारने से जुड़े

अपने सुझाव भी साझा कर सकते हैं, और सबसे अहम बात यह कि एक बार शिकायत दर्ज करने के बाद छात्र उसकी मौजूदा स्थिति और उस पर हुई कार्रवाई को ट्रैक भी कर सकता है। पोर्टल पर सबसे ज्यादा दर्ज होने वाली शिकायतों को भोजन, पेयजल, बिजली, शौचालय-सफाई, सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और इंटरनेट जैसी श्रेणियों में पहले से बांटा गया है, जिससे शिकायत सीधे संबंधित विभाग तक पहुंचती है और निपटारे में देरी नहीं होती। पोर्टल पर दर्ज हर शिकायत का 30 दिनों के भीतर निपटारा सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है। समाधान के बाद संबंधित छात्र को लिखित रूप से इसकी सूचना भी दी जाती है, ताकि यह साफ रहे कि उसकी शिकायत पर वाकई कार्रवाई हुई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शिकायतकर्ता छात्र-छात्राओं की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी, जिससे छात्र बिना किसी डर के अपनी बात रख सकें। जिन छात्रों के पास ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की सुविधा नहीं है, उनके लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1100 भी उपलब्ध कराया गया है। पोर्टल का मकसद छात्रों की शैक्षणिक, परीक्षा, छात्रावास, छात्रवृत्ति अन्य संस्थागत समस्याओं का पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से समाधान करना है।

सरकारी पोर्टल और हेल्पलाइन की घोषणाएं आमतौर पर होती रहती हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर व्यवहार में उतनी असरदार साबित नहीं होतीं। लेकिन बिहार सरकार की अब तक की कोशिशों को देखें तो ऐसा लगता है कि सरकार गंभीरता से छात्रों की समस्याओं को सुनने की ओर अग्रसर है। इस पोर्टल की खासियत है कि इसमें एक जवाबदेही तंत्र भी जोड़ा गया है - तय समयसीमा में शिकायत का समाधान न होने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान रखा गया है, जिससे यह सिर्फ कागजी व्यवस्था बनकर नहीं रह जाती। पोर्टल के साथ-साथ सरकार ने हर महीने सहयोग शिविर आयोजित करने की व्यवस्था भी बनाई है, जिनमें मंत्री, विधायक, सांसद और संबंधित अधिकारी सीधे स्कूल-कॉलेजों में जाकर छात्रों से बातचीत करेंगे। इन शिविरों में मिलने वाली शिकायतों और सुझावों को भी उसी पोर्टल पर दर्ज कर ट्रैक किया जाता है, जिससे पूरा सिस्टम एक जगह जुड़ा रहता है। यह व्यवस्था खासकर उन इलाकों में उपयोगी मानी जा रही है, जहां छात्र ऑनलाइन माध्यम के बजाय सीधी बातचीत में ज्यादा सहज महसूस करते हैं।

शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए बड़ी घोषणाओं के साथ-साथ जमीनी क्रियान्वयन भी उतना ही जरूरी है। बिहार का अनुभव यह दिखाता है कि अगर शिकायत निवारण तंत्र में पारदर्शिता, आसान प्रोसेस और जवाबदेही तय की जाए, तो नतीजे भी सामने आते हैं। अब देखना यह होगा कि अन्य राज्य इस मॉडल से कितना सीखते हैं और अपने यहां इसे किस रूप में लागू करते हैं।

मजबूती के संकेत: निजी निवेश और निर्यात के जरिये रफ्तार बनाए रखनी होगी; ताकि विकास पर भारी न पड़े बाहरी दबाव

ऐसे वक्त में, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के चलते मुश्किल हालात से जूझ रही है, तब भारत में जून तिमाही के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों में वृद्धि देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती का ही संकेत देती है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद दर सालाना आधार पर 7.8 प्रतिशत बढ़ी, जो देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती का संकेत है। यह तब है, जब भारतीय अर्थव्यवस्था को अमेरिका-ईरान के बीच जारी संघर्ष, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों, व्यापार को लेकर अनिश्चितता, रुपये की कमजोरी और वित्तीय बाजार में उतार-चढ़ाव जैसे मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा है।

अमेरिका और ईरान के बीच 28 फरवरी को युद्ध छिड़ने के बाद न सिर्फ कच्चे तेल की कीमत बढ़ी, बल्कि आपूर्ति पर भी खासा असर पड़ा, लेकिन सरकार के पूंजीगत खर्च जारी रखने से आर्थिक गतिविधियों को काफी समर्थन मिला। अर्थशास्त्रियों के आकलन (7.1-7.2 फीसदी) को भी पीछे छोड़ते ये आंकड़े दर्शाते हैं कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, देश की आर्थिक गतिविधियां मजबूत बनी हुई हैं। इससे साफ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किसी भी रुकावट को धता बताते हुए अपनी रफ्तार बनाए रखने की क्षमता है, जो सरकार की आर्थिक नीतियों की दिशा को सही ठहराती है।

इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 10 फीसदी विकास दर के साथ सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। इस दौरान विनिर्माण (9.2 फीसदी) और निर्माण (7.7 फीसदी) ने भी अर्थव्यवस्था को काफी सहारा दिया। तिमाही के अंत में मजबूत औद्योगिक गतिविधियों ने भी कुल विकास का समर्थन दिया। इससे भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था का महत्व भी उजागर होता है। अपेक्षाकृत बड़े घरेलू उपभोक्ता बाजार ने वैश्विक मांग और व्यापार में कुछ कमजोरी से अर्थव्यवस्था को बचाने में मदद की है।

बेशक कठिन वैश्विक हालात में 7.8 फीसदी की विकास दर हासिल करना निश्चित रूप से उत्साहजनक और बड़ी कामयाबी है, लेकिन इससे भविष्य के जोखिम कम नहीं हो जाते। तेल की कीमत अब भी एक बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि भारत अपने कच्चे तेल की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है। ऊर्जा की कीमत में लगातार बढ़ोतरी से परिवहन की लागत बढ़ जाती है और महंगाई पर दबाव बढ़ जाता है।

हाल के दिनों में विभिन्न खाद्य पदार्थों की कीमतों में उछाल देखने को मिला ही है। इसके अलावा, देश में मानसून की बारिश एक समान नहीं रही है, जिसका असर फसल उत्पादन पर पड़ेगा। विकास दर के ये आंकड़े अर्थव्यवस्था को ठोस आधार देते हैं, लेकिन आगे मजबूत निजी निवेश, उपभोग और निर्यात के जरिये इस रफ्तार को बनाए रखना होगा, ताकि बाहरी दबाव विकास पर भारी न पड़े।

भारत को खुद अपनी राह बनानी होगी: ग्लोबल फॉर्च्यून 500 में शामिल होना आसान नहीं, घरेलू क्षमता मजबूत करनी होगी

अनंत स्वरूप

15 अगस्त के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से भारतीय कॉरपोरेट जगत (यानी कि इंडिया इंक) के सामने एक साहसिक चुनौती रखी-अगले दशक तक ग्लोबल फॉर्च्यून 500 में भारत की 50 कंपनियां क्यों नहीं आ सकतीं? इस महत्वाकांक्षा को प्रधानमंत्री ने सरकार का प्रोजेक्ट न बताते हुए, विकसित भारत 2047 प्रोजेक्ट से जोड़कर केंद्र, राज्यों, और उद्योगों के बीच एक समुदाय-आधारित राष्ट्रीय परियोजना के रूप में रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने इस लक्ष्य को अलग-अलग क्षेत्रों के तय लक्ष्यों से जोड़ने की बात कही।

ग्लोबल फॉर्च्यून 500 में भारत की नौ कंपनियां हैं। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भारत को इसमें 41 और कंपनियां जोड़नी होंगी, जो मौजूदा संख्या से पांच गुना से अधिक की छलांग होगी। 2026 की ग्लोबल फॉर्च्यून 500 सूची में अमेरिका की 141 और ग्रेटर चीन (हांगकांग सहित) की 122 कंपनियां हैं। अमेरिका ने मजबूत कैपिटल मार्केट्स और अग्रणी तकनीक व बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जरिये, जबकि चीन ने सरकारी समर्थन वाली औद्योगिक नीति से कंपनियां खड़ी कर यह मुकाम हासिल किया। भारत का आंकड़ा बताता है कि अभी लंबी दूरी तय करनी है, पर संभावनाएं भी काफी हैं। भारत ने ऊंची वैल्यूएशन वाले कई यूनिकॉर्न बनाए हैं, लेकिन इन कंपनियों का रेवेन्यू अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा है, जो इस सूची में जगह बनाने के लिए जरूरी है। इसलिए, ऐसी संस्थाओं का निर्माण करना होगा, जो सालाना अरबों डॉलर्स का उत्पादन करने में सक्षम हों और तकनीक व बाजार तक पहुंच में प्रतिस्पर्धा कर सकें।

सबसे बढ़िया उदाहरण दक्षिण कोरिया का चेबोल मॉडल है। 1960 के दशक में सरकार ने निर्यात लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पारिवारिक व्यवसायों को चुना और उन्हें योजना व वित्तीय मदद दी, जबकि चेबोल ने इसे बड़े स्तर पर लागू किया। दोनों ने मिलकर निर्यात आधारित औद्योगीकरण को तेजी से बढ़ाया। वहीं युद्ध के बाद जापान ने रणनीतिक क्षेत्रों की पहचान की और सब्सिडी क्रेडिट

प्रदान किए, जबकि कीरेत्सु कंपनियों को शोध एवं विकास को साझा करने और आपसी शेयरहोल्डिंग नेटवर्क के जरिये मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। यहां तक कि चीन की फॉर्च्यून 500 में बढ़त भी इसी तरह के राज्य-उद्योग समझौते पर टिकी हुई है। बैंकिंग, ऊर्जा और निर्माण जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पूंजी वाले सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम पहले बड़े स्तर पर काम करने के लिए तैयार किए गए। फिर, सरकार के निर्देश पर इनका विस्तार और विलय हुआ, जिससे निर्यात बढ़ा तथा कंपनियां वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनीं।

भारत किसी भी एक मॉडल को नहीं अपना सकता, पर उपर्युक्त उदाहरणों में एक बात साफ है-सरकारी नीतियों ने पूंजी, बुनियादी ढांचा, सुरक्षा और निर्यात प्रोत्साहन जैसी सुविधाएं देकर अनुकूल माहौल बनाया, जबकि उद्योगों ने बेहतर प्रदर्शन, जोखिम लेने की क्षमता और वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा के साथ इसे आगे बढ़ाया। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में 2014 के बाद से किए गए मुक्त व्यापार समझौतों का जिक्र करते हुए इशारा किया कि वैश्विक बाजारों तक पहुंचने के लिए एमएसएमई और बड़ी फर्म्स, दोनों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि भारत में कारोबारी माहौल को आसान बनाया जाए, विनिर्माण की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में लगातार निवेश किया जाए, विदेशी कर्ज पर निर्भर हुए बिना बड़े पैमाने पर धन जुटाने के लिए घरेलू पूंजी का इस्तेमाल किया जाए और भारतीय ब्रांडों को दुनियाभर में पहचान दिलाने पर भी जोर दिया जाए। भारतीय कॉरपोरेट जगत को वैश्विक स्तर हासिल करना अपनी प्राथमिकता बनाना होगा। कंपनियों को मांग बढ़ने से पहले ही निवेश करना होगा। जहां बाजार का बिखराव कंपनियों के बड़े स्तर पर बढ़ने में बाधा बनता है, वहां रणनीतिक एकीकरण अपनाना होगा। साथ ही, छोटे-छोटे क्षेत्रों तक सीमित रहने के बजाय पूरी आपूर्ति श्रृंखला को एकसाथ विकसित करना होगा। निरंतर वैश्विक नेतृत्व के लिए शोध, डिजाइन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर अधिक निवेश करने की आवश्यकता होगी।

भारतीय कंपनियों को बड़े और पहचान वाले वैश्विक ब्रांड बनाने की जरूरत है, न कि केवल दूसरे ब्रांडों के लिए सेवा प्रदाता या कुशल निर्माता बने रहने की। चुनौती इस सोच को एक मजबूत व टिकाऊ व्यवस्था में बदलने की है, जिसमें भारतीय कंपनियां लंबे समय तक निवेश कर सकें, बड़े स्तर पर नवाचार कर सकें और वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा कर सकें। अन्यथा, भारत की मौजूदा नौ कंपनियों से 50 वैश्विक कंपनियों तक पहुंचने की महत्वाकांक्षा स्वतंत्रता दिवस पर कही गई महज एक पंक्ति बनकर रह जाएगी।

सेक्रेटरी जनरल, फिक्की

नेपाल की बाढ़ में बह गईं कैश से भरी बैंक की तिजोरियां सुरक्षित करने के लिए पुलिस कर रही जद्दोजहद

काठमांडू

अचानक आई बाढ़ में लापता हुए सैकड़ों लोगों की तलाश के अलावा नेपाल पुलिस के सामने एक और मुश्किल आन पड़ी है। बाढ़ में बह गए कम से कम 20 बैंकों के लापता वॉल्ट (तिजोरियों) का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित करने के लिए पुलिस जद्दोजहद कर रही है, ताकि वे गलत हाथों में न पड़ें।

अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि इनमें से कुछ वॉल्ट में भारी मात्रा में कैश और अन्य कीमती सामान हैं। डीआईजी अबी नारायण काफ्ले ने कहा कि बाढ़ के बाद की मुश्किल स्थिति में पुलिस की पहली प्राथमिकता लापता लोगों को खोजना है, लेकिन साथ ही उन्हें प्रभावित इलाकों में कानून-व्यवस्था भी बनाए रखनी है। उन्होंने कहा, रसुवा, धाडिंग, चितवन और दूसरी जगहों पर कई बैंक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए थे। उनमें से कई तिजोरियां, जिनमें कैश और सोना जैसी कीमती चीजें थीं, या तो बह गईं या भारी गाद के नीचे दब गईं। हमारे कर्मचारी अब उन तिजोरियों को खोजने और सुरक्षित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जिनमें लोगों ने बहकर आई तिजोरियों को तोड़कर कैश चुरा लिया।

यह घटनाक्रम तब सामने आया जब धाडिंग जिले की पुलिस ने अपर रसुवा इलाके से बहकर आई एक तिजोरी से कथित तौर पर 92 लाख नेपाली रुपये चुराने के आरोप में 29 लोगों को गिरफ्तार किया।

काफ्ले ने कहा, रविवार शाम को हमारे कर्मचारी त्रिशूली में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक की धुंगे शाखा की एक तिजोरी को सुरक्षित करने में कामयाब रहे। इस काम में उन्हें लगभग आठ घंटे लगे। उन्होंने बताया कि उस तिजोरी में 1.5 करोड़ नेपाली रुपये कैश और 50 करोड़ नेपाली रुपये कीमत के सोने सहित अन्य कीमती सामान था। एक अन्य मामले में, पुलिस ने नुवाकोट के कृषि विकास बैंक की एक तिजोरी को सुरक्षित किया।

रूस ने यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर हमला किया: रक्षा मंत्रालय

मॉस्को, (स्पूतनिक/वार्ता)। रूस के सशस्त्र बलों ने सोमवार रात यूक्रेन के कीव क्षेत्र में सैन्य-औद्योगिक और ईंधन एवं ऊर्जा सुविधा केन्द्रों पर हमले किये।रूसी रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

मंत्रालय ने कहा कि कल रात रूसी सशस्त्र बलों ने सटीक निशाना लगाने वाले हथियारों और लंबी दूरी तक मारक क्षमता वाले ड्रोन का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर हमला किया।

मंत्रालय ने कहा, इस हमले के परिणामस्वरूप, कीव और उसके आसपास क्षेत्र में उन सैन्य-औद्योगिक और ईंधन व ऊर्जा सुविधा केन्द्रों को निशाना बनाया गया, जो यूक्रेनी सशस्त्र बलों के लिए मिसाइलों, मानवरहित हवाई प्रणालियों, कलपुर्जों और ईंधन की आपूर्ति के उत्पादन में शामिल थीं।

थाईलैंड में बार का बिल न चुकाने पर महिला के साथ बदसलूकी, बारटेंडर ने मुंडवा दिया सिर

बैंकॉक

गलतियों या धोखाधड़ी की सजा क्या इतनी अपमानजनक होनी चाहिए कि किसी इंसान की व्यक्तिगत गरिमा ही तार-तार हो जाए? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से सामने आए एक चौंकाने वाले मामले ने इसी सवाल को लेकर इंटरनेट पर नैतिकता, मर्यादा और कानून के दायरे पर एक गंभीर बहस छेड़ दी है।

बार में हजारों रुपयों का बिल न चुका पाने पर एक युवती के सिर के बाल मुंडवाने का वीडियो सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। वायरल प्रेस के अनुसार, यह घटना 25 अगस्त को बैंकॉक के पिंकलाओ इलाके के एक लोकप्रिय बार में घटी। आरोप है कि यह युवती पहले भी इस इलाके के क्लबों और रेस्तरां में बिना बिल चुकाए भागने के लिए जानी जाती थी।

युवती कथित तौर पर एक फर्जी पहचान पत्र दिखाकर बार में दाखिल हुई। वहां उसने करीब 60,000 थाई बाथ का बिल बना लिया। इसके बाद उसने बिना भुगतान किए चुपके से वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन कर्मचारियों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और बिल चुकाने का दबाव बनाया। जब युवती के पास बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं निकले, तो उसने पुलिस में जाने से बचने के लिए एक अजीबोगरीब और अपमानजनक शर्त पर अपने सिर के बाल मुंडवाने सहमति जताई।

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में सफेद ड्रेस पहने यह युवती एक तथाकथित हेयर परचेज कॉन्ट्रैक्ट पर सहमति देती दिख रही है। कैमरे के पीछे से एक व्यक्ति यह कहता सुनाई दे रहा है कि मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठा रहा हूं। यह बाजार भाव है। मैं तुम्हारे लिए यह जोड़ रहा हूं और कुछ अतिरिक्त पैसे भी लगा रहा हूं, ठीक है?

इसके बाद वीडियो में बारटेंडर को एक इलेक्ट्रिक ट्रिमर से युवती के कंधे तक लंबे घने बालों को पूरी तरह मुंडते हुए देखा जा सकता है। दावा किया गया कि इन बालों को बाद में दान किया जाएगा।

इस घटना का वीडियो वायरल होते ही लोगों की राय बंट गई। जहां कुछ लोगों ने इसे युवती के धोखे की सजा बताया, वहीं मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों ने इसे अमानवीय और गैर-कानूनी करार दिया। बाल शोषण और मानवाधिकारों पर काम करने वाले थाईलैंड के बी वन फाउंडेशन की संस्थापक चलिदा टोन ओर फलामत ने कहा कि बार प्रबंधन ने हद पार कर दी है। चलिदा के अनुसार, मजबूरी और दबाव में कराया गया कोई भी अनुबंध कानूनन शून्य होता है।

नफरत की भाषा और आपत्तिजनक वीडियो की शुरुआत भाजपा ने की: संजय सिंह

चंदौली, (वार्ता)। आम आदमी पार्टी (आप) के उत्तर प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मंगलवार को भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो और नफरत की भाषा की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की ओर से हुई।

श्री सिंह मंगलवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां जिलाध्यक्ष अशोक सिंह के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों और गाजे-बाजे के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल-मालाएं पहनाकर अभिनंदन किया।

स्टेशन पर पत्रकारों से बातचीत में श्री सिंह ने भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो विवाद को लेकर आरोप लगाया कि भाजपा की ओर से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को थप्पड़ मारते हुए दिखाया गया एक वीडियो प्रसारित किया गया था और विवाद बढ़ने के बाद भाजपा को वह वीडियो हटाना पड़ा।

राम मंदिर निर्माण से जुड़े जमीन के मामलों पर सवाल उठाते हुए आप सांसद ने कहा कि उनके पास जमीन से संबंधित 13 दस्तावेज हैं। उन्होंने दावा किया कि अलग-अलग दस्तावेजों में चंपत राय, डॉ. अनिल मिश्रा और भाजपा के पूर्व मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के हस्ताक्षर अथवा गवाही का उल्लेख है। उन्होंने कहा कि इन दस्तावेजों के आधार पर मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यदि किसी की जिम्मेदारी सामने आती है तो उसे तय किया जाना चाहिए। संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में रोजगार और सामाजिक न्याय के मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है। उन्होंने बताया कि रोजगार के सवाल पर पांच चरणों में पदयात्राएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि तीन चरण अभी बाकी हैं। पेपर लीक के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी युवाओं की समस्याओं को लेकर लगातार आवाज उठा रही है। उन्होंने कहा कि प्रभु श्रीराम के नाम पर मिले चंदे से जुड़े कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उन्होंने वर्ष 2021 में उठाया था और आप आगे भी जनता तथा युवाओं से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाती रहेगी।

आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की भूमिका और सीटों को लेकर पूछे गए सवाल पर श्री सिंह ने कहा कि पार्टी प्रदेश में किस रूप में और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा।

पागल कुत्ते के हमले में तीन बच्चे घायल

अलवर, (वार्ता)। राजस्थान में अलवर के सदर थाना क्षेत्र में कारौली गांव में मंगलवार को एक पागल कुत्ते ने घर के बाहर खेल रहे तीन भाई-बहनों पर हमला करके उन्हें घायल कर दिया। सूत्रों ने बताया कि घटना के समय बच्चों के परिजन खेत में प्याज लगाने के काम से गए हुए थे। घर पर कोई बड़ा सदस्य मौजूद नहीं था। दोनों भाई और उनकी बहन घर के बाहर खेल रहे थे। इसी दौरान अचानक एक आवारा कुत्ता वहां पहुंचा और खेल रहे बच्चों पर झपट पड़ा। कुत्ते ने इम्तियाज, जाफर और आलिया को अपना निशाना बनाया और उनके हाथ-पैर सहित शरीर के अन्य हिस्सों पर काटकर उन्हें घायल कर दिया।

बच्चों के चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी और ग्रामीण तुरंत मौके पर दौड़े। ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए कुत्ते को बच्चों से अलग करवाया। कुत्ते के लगातार आक्रामक बने रहने से ग्रामीणों ने उसे मौके पर ही मार गिराया। इसके बाद परिजन तीनों घायल बच्चों को लेकर अलवर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्हें ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया। तीनों बच्चों का चिकित्सकों की निगरानी में उपचार जारी है।

एलडीएफ को कमजोर नहीं होने देगी भाकपा बातचीत से सुलझेगा विवाद: बिनॉय विश्वम

नयी दिल्ली/तिरुवनंतपुर

एक सितंबर केरलम विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर वाम दलों के बीच जारी विवाद के बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) की प्रदेश इकाई के सचिव बिनॉय विश्वम ने मंगलवार को कहा कि वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) भाकपा का ''बच्चा'' है और पार्टी, गठबंधन को कमजोर करने की किसी भी कोशिश की अनुमति नहीं देगी। विश्वम ने नयी दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि भाकपा ऐसा कोई रुख नहीं अपनाएगी जिससे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के साथ उसके संबंध कमजोर हों। उन्होंने कहा कि पार्टी चाहती है कि इस मुद्दे का समाधान एलडीएफ के भीतर बातचीत के जरिए निकाला जाए।

यह पूछे जाने पर कि क्या इस विवाद को लेकर भाकपा राज्य विधानसभा में अलग समूह के रूप में बैठेगी, विश्वम ने कहा कि इस बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा, ''एलडीएफ के गठन के लिए भाकपा ने कड़ी मेहनत की है। एलडीएफ भाकपा का बच्चा है।

हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यह बच्चा अपनी अलग पहचान के साथ स्वस्थ, मजबूत और अच्छे स्वभाव वाला बने। भाकपा इसके अलावा कोई और रुख नहीं अपनाएगी।'' वरिष्ठ नेता ने कहा, ''इसे नष्ट करने की किसी भी कोशिश की अनुमति नहीं दी जाएगी।'' विश्वम ने कहा कि माकपा का यह कहना केवल उसकी अपनी राय है कि परंपरा के आधार पर उप नेता प्रतिपक्ष का पद उसे मिलना चाहिए और यह एलडीएफ का फैसला नहीं है। उन्होंने उप नेता प्रतिपक्ष पद की मांग को लेकर एलडीएफ के दो प्रमुख घटक दलों के बीच सार्वजनिक रूप से जारी तकरार के बीच यह टिप्पणी की है।

एलडीएफ की दूसरी सबसे बड़ी घटक भाकपा ने हाल में उसकी मांग खारिज करने पर माकपा के वरिष्ठ नेता एवं नेता प्रतिपक्ष पिनराई विजयन की आलोचना की थी। भाकपा ने उन पर गठबंधन के नियमों का उल्लंघन करने और उसे कमजोर करने का आरोप लगाया था। विजयन ने पिछले सप्ताह भाकपा की मांग खारिज करते हुए कहा था कि उप नेता प्रतिपक्ष का पद माकपा के किसी नेता को मिलेगा।

उन्होंने कहा था कि उप नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए उन्हें केवल विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र भेजना होगा और इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह माकपा के किसी नेता के नाम की ही सिफारिश करेंगे। विश्वम ने विजयन की इस टिप्पणी की कड़ी आलोचना करते हुए कहा था कि यह उनके पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। इस बीच, भाकपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री के. राजन ने कहा कि पार्टी को भरोसा है कि केरलम विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष पद की उसकी मांग स्वीकार की जाएगी।

उन्होंने कहा, ''अगर बिनॉय विश्वम ने भरोसा जताया है कि उप नेता प्रतिपक्ष का पद भाकपा को मिलेगा तो यह पार्टी के भरोसे को दर्शाता है। भाकपा ने जायज मांग उठाई है और हम उस पर कायम हैं।'' राजन ने कहा, ''हमारा मानना है कि हमने जो मांगा है, उस पर एलडीएफ में शामिल भाकपा का अधिकार है। यह हमारा हक है, इसलिए हमें भरोसा है कि यह हमें मिलेगा।'' उन्होंने कहा कि भाकपा उन दलों में शामिल है जिन्होंने एलडीएफ के गठन के लिए त्याग किया था और फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि पार्टी गठबंधन छोड़ने के बारे में सोचे।

क्या दाम बढ़ाना सरकार की आदत बन गई है : सुप्रिया सुले

मुंबई, (वार्ता)

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा-शरद पवार) की वरिष्ठ सांसद सुप्रिया सुले ने कमरतोड़ महंगाई और कीमतों में उछाल को लेकर केन्द्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए पूछा कि क्या चुनाव समाप्त होने के बाद जरूरी चीजों के दाम बढ़ाना सरकार की आदत में शुमार हो गया है।

सुश्री सुले ने कीमतों में बढ़ोतरी के समय पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या चुनाव खत्म होने के बाद जानबूझकर चीजों के दाम बढ़ाना सत्ताधारी प्रशासन की सोची-समझी रणनीति बन गई है। गौरतलब है कि पहली सितंबर से मुंबई और उसके आस-पास के महानगरीय इलाकों में सीएनजी की कीमतों में 2 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जिससे दाम 88 रुपये प्रति किलोग्राम हो गए हैं। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर और खाना बनाने वाली गैस की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है। इस कदम से स्थानीय भोजनालयों, होटलों और टिफिन सेवाओं पर भी असर पड़ने की उम्मीद है।

सुश्री सुले ने परिवारों पर पड़ रहे भारी आर्थिक बोझ का जिक्र करते हुए कहा कि ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण ऑटो-रिक्शा, टैक्सी और सार्वजनिक परिवहन का किराया सीधे-सीधे बढ़ गया है। रोजाना इस्तेमाल होने वाले दूध, खाने के तेल, गुड़ और रसोई की अन्य जरूरी चीजें भी काफी महंगी हो गई हैं, जिससे परिवारों का बजट पूरी तरह बिगड़ गया है। राकांपा नेता ने त्योहारों के मौसम से ठीक पहले चीनी की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी पर नाराजगी जताते हुए इसे बहुत संदिग्ध बताया और कहा कि यह आम उपभोक्ताओं की खुलेआम लूट के अलावा और कुछ नहीं है।

उन्होंने इसके अलावा सरकार के चुप रहने की आलोचना करते हुए उनकी निष्क्रियता की तुलना हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से की, जबकि आम नागरिक आसमान छूती कीमतों का बोझ उठा रहे हैं।

सुश्री सुले ने कहा कि जब कोई सरकार रोजाना इस्तेमाल होने वाली जरूरी चीजों की कीमतों को नियंत्रण में रखने में पूरी तरह नाकाम रहती है, तो अच्छे दिन का नैरेटिव पूरी तरह खोखला साबित होता है। उन्होंने तुरंत दखल देने की मांग करते हुए केंद्र से कहा कि वह बिना देरी किए ईंधन पर कर-उपकर कम करे, भारी उत्पाद शुल्कों में कटौती करे और अपनी बातों के मुताबिक राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाते हुए परेशान जनता को आर्थिक राहत दे।

फिल्म/टीवी मनोरंजन

रश्मिका मंदाना की 'मैसा' 27 नवंबर को होगी रिलीज

अभिनेत्री रश्मिका मंदाना स्टारर एक्शन ड्रामा फिल्म 'मैसा' की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया गया है। रविंद्र पुल्ले के निर्देशन में बनी यह फिल्म 27 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। 'मैसा' को फीमेल-लेड पैन-इंडिया फिल्मों में शामिल किया जा रहा है। फिल्म में रश्मिका एक बेहद इंटेंस और दमदार किरदार में नजर आएंगी। फिल्म से जारी किए गए उनके अलग-अलग लुक पहले ही दर्शकों का ध्यान आकर्षित कर चुके हैं।

अनफॉर्मुला फिल्म्स के प्रोडक्शन में बनी 'मैसा' एक इमोशनल एक्शन थ्रिलर है, जिसकी कहानी आदिवासी इलाकों की पृष्ठभूमि पर आधारित है। फिल्म में रश्मिका को पहले से अलग और पावरफुल अवतार में पेश किया गया है।

रश्मिका अपनी वर्सेटिलिटी और अलग-अलग किरदारों को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए जानी जाती हैं। 'मैसा' के जरिए वह एक ऐसे किरदार में दिखाई देंगी, जिसमें एक्शन के साथ भावनात्मक पहलू भी देखने को मिलेगा। फिल्म के मेकर्स के अनुसार, 'मैसा' में दमदार कहानी, शानदार विजुअल्स और रश्मिका का इंटेंस अभिनय देखने को मिलेगा। फिल्म को बड़े पैन-इंडिया स्तर पर दर्शकों तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है।

कुब्रा सैत ने माथे पर चाबी टिकाकर खोजी 'मैग्नेटिक फोर्स', मजेदार अंदाज ने जीता प्रशंसकों का दिल

अभिनेत्री कुब्रा सैत ने सोशल मीडिया पर अपने मजेदार अंदाज से एक बार फिर प्रशंसकों का ध्यान आकर्षित किया है। कुब्रा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वह अपने माथे के बीचों-बीच चाबी रखकर 'मैग्नेटिक फोर्स' खोजती नजर आ रही हैं।

वीडियो में कुब्रा अपने माथे पर चाबी रखती हैं और उसके वहां टिक जाने पर हैरान हो जाती हैं। इसके बाद वह इस प्रयोग को बार-बार दोहराती हैं और कैमरे के सामने अपनी मजेदार प्रतिक्रियाएं देती हैं। उनका सहज और हास्यपूर्ण अंदाज वीडियो को मनोरंजक बना देता है।

वीडियो के साथ कुब्रा ने लिखा, दिमाग के बीचों-बीच चुंबकीय शक्ति रखने वाली महिलाओं से पंगा मत लेना। इसके साथ उन्होंने कुछ मजेदार इमोजी भी साझा किए हैं। उनका यह हल्का-फुल्का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रशंसकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।

कुब्रा अक्सर सोशल मीडिया पर अपने रोजमर्रा के सहज और मजेदार पल साझा करती रहती हैं, जिन्हें प्रशंसकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिलती है। कुब्रा सैत अपने हालिया प्रोजेक्ट 'संकल्प' में अपने अभिनय के लिए सराहना बटोर रही हैं। इसके अलावा वह बहुप्रतीक्षित सीरीज 'फर्जी 2' में नजर आएंगी। सीरीज में वह शाहिद कपूर और विजय सेतुपति के साथ अपने लोकप्रिय किरदार सायरा के रूप में वापसी करेंगी।

शक्तिशाली व्यवस्था के खिलाफ लड़की की आवाज की कहानी है 'हुंकार: द रोर'

जियोहॉटस्टार ने अपनी आगामी ड्रामा सीरीज 'हुंकार: द रोर' की घोषणा की है। बिड़ला स्टूडियोज और अप्लॉज एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित तथा पर्पल पेबल पिक्चर्स के सहयोग से मंगाता फिल्म्स के प्रोडक्शन में बनी यह सीरीज 25 सितंबर 2026 को जियोहॉटस्टार पर रिलीज होगी।

करण डी कपाड़िया, नित्या मेहरा और हीराज मारफतिया द्वारा निर्देशित 'हुंकार: द रोर' 17 वर्षीय मीनू रावत की कहानी है। मीनू द्वारा सम्मानित पंथ नेता सुनील चकोसी उर्फ 'बापजी' पर लगाए गए आरोप के बाद एक हाई-प्रोफाइल जांच शुरू होती है, जो धीरे-धीरे पूरे देश का ध्यान आकर्षित करती है। सीरीज में फातिमा शेख, अर्जुन माथुर, मोहम्मद जीशान अय्यूब, अनीत पड्डा, रघुबीर यादव और राम कपूर सहित कई कलाकार महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे। सीरीज की कहानी में पुलिस जांच, कानूनी लड़ाई और मीडिया ट्रायल के तीन अलग-अलग पहलुओं को सामने रखा गया है। एसीपी जसलीन सिंह सोनी, वकील भालेराव और पत्रकार अमिताभ अपने-अपने स्तर पर एक ही सच की तलाश करते नजर आएंगे। ताकत, रसूख और जनमत के बीच इन तीनों की लड़ाई कहानी को आगे बढ़ाएगी। निर्माताओं के अनुसार, 'हुंकार: द रोर' एक तनावपूर्ण और दमदार कहानी है, जो दर्शकों को घटनाओं के पीछे छिपे सच पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करेगी। सीरीज में यह भी दिखाया जाएगा कि किसी आरोप के सामने आने के बाद पुलिस, अदालत और मीडिया किस तरह अपनी-अपनी भूमिका निभाते हैं। बिड़ला स्टूडियोज और अप्लॉज एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित, पर्पल पेबल पिक्चर्स के सहयोग से मंगाता फिल्म्स प्रोडक्शन की इस सीरीज को करण डी कपाड़िया और नित्या मेहरा ने तैयार किया है।

टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने दिल्ली में शिक्षकों का जोरदार प्रदर्शन

नरसिंहपुर जिले के सैकड़ों शिक्षकों ने लिया आंदोलन में हिस्सा

गाडरवारा (स्वतंत्र मत)।

शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग को लेकर रविवार 30 अगस्त को दिल्ली के केशवपुरम स्थित जाट धर्मशाला परिसर में देशभर से आए शिक्षकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल हुए और सरकार से टीईटी की बाध्यता समाप्त करने के लिए लोकसभा में विधेयक लाकर इस संबंध में स्थायी समाधान किए जाने की मांग उठाई गई। आंदोलन में नरसिंहपुर जिले के सैकड़ों शिक्षक भी शामिल हुए। जिले से बड़ी संख्या में शिक्षकों के दिल्ली पहुंचने से आंदोलन को मजबूती मिली। शिक्षकों ने कहा कि लंबे समय से शासकीय विद्यालयों में सेवाएं दे रहे शिक्षकों के सामने टीईटी की अनिवार्यता को लेकर उत्पन्न स्थिति का समाधान सरकार को संवेदनशीलता के साथ करना चाहिए।

जेटीएएफ (शिक्षक संयुक्त मोर्चा) के राष्ट्रीय संयोजक जगदीश यादव के नेतृत्व में आयोजित इस आंदोलन में देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे हजारों शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने टीईटी की बाध्यता समाप्त करने तथा इस संबंध में स्पष्ट एवं स्थायी नीति बनाने की मांग की।

शिक्षकों का कहना था कि वे वर्षों से शिक्षा व्यवस्था में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में टीईटी की अनिवार्यता को लेकर उत्पन्न परिस्थितियों का उचित समाधान आवश्यक है। शिक्षकों ने सरकार से मांग की कि उनकी मांग पर संसद में विधेयक लाकर आवश्यक कानूनी प्रावधान किए जाएं, ताकि शिक्षकों को राहत मिल सके।

लोकसभा में विधेयक लाने की मांग

प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से मांग की कि टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने के लिए लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत कर उसे पारित कराया जाए। शिक्षकों ने कहा कि उनकी मांग केवल किसी एक राज्य या संगठन तक सीमित नहीं है, बल्कि देशभर के शिक्षकों से जुड़ा विषय है।

आंदोलन के दौरान शिक्षकों ने एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए सरकार से शीघ्र निर्णय लेने की मांग की। नरसिंहपुर जिले से संयुक्त शिक्षक मोर्चा के नेतृत्व में सैकड़ों शिक्षकों की सहभागिता को आंदोलन में जिले की महत्वपूर्ण भागीदारी के रूप में देखा गया। शिक्षकों ने कहा कि जब तक टीईटी की बाध्यता को लेकर समाधान नहीं किया जाता, तब तक अपनी मांग को लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के समक्ष उठाते रहेंगे।

नगर मे 5 करोड़ रुपयों की लागत से बनेगा वॉटर सप्लाई सिस्टम

नगर में निर्बाध जलापूर्ति किये जाने हेतु जारी है पानी टंकी निर्माण एवं पाईप लाईनों को विस्तार

गाडरवारा (स्वतंत्र मत)।

नगर में निर्बाध जलापूर्ति किये जाने एवं निकाय पर बोझ बन रहे लाखों रूपयों की राशि के बिजली बिलों को बोझ कम करने के लिये पानी की टंकी निर्माण कार्य एवं पाईप लाईनों को विस्तार किया जा रहा है। चुंकि नगर की विस्तृत पाईप लाईने एवं पानी की टंकी काफी पुरानी हो चुकी है। जिसे दृष्टिगत रखते हुये नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा नगर में जलापूर्ति सुचारू किये जाने एवं भविष्य में 2055 तक निर्बाध जलापूर्ति किये जाने के लिये अमृत 2.0 योजना के तहत पांच करोड़ रूपयों की राशि से गाडरवारा में 20 लाख लीटर की पानी की टंकी का निर्माण एवं क्लियर वॉटर डीआई 12 इंच पाईप लाईन, ड्रिस्ट्रीब्यूशन पाईप लाईन एवं नल कनेक्शन के विस्तार के लिये राशि आबंटित की जाकर कार्य किया जा रहा है।

बिजली बिलों से मिलेगी मुक्ति

आगामी समय में नगर में संचालित नलकूप जिनकी संख्या 65 हैं, को बंद किया जाना है एवं नगर में सम्पूर्ण जलापूर्ति नई पाईप लाईन एवं नई पानी की टंकियों से किया जाना है। नलकूप बंद होने से नगर पालिका परिषद को बिजली के बिलों में 80 प्रतिशत की कमी आएगी, जिससे की अनावश्यक आर्थिक भार से निकाय को मुक्ति मिल सकेगी।

एक साल का लक्ष्य

इस कार्य को पूर्ण होने में एक साल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, कार्य की गति को देखते हुये लक्ष्यानुरूप समय में कार्य पूर्ण होने का अनुमान है। नगरवासियों को पुरानी पाईप लाईन एवं पुरानी पाईप लाईन से निजात मिलेगी और पानी का दुरूपयोग भी कम हो सकेगा। क्योंकि उक्त योजना से निर्धारित समय और निर्धारित मात्रा में जलापूर्ति की जाएगी।

पुलिस अधीक्षक ने जनसुनवाई में व्यक्तिगत रूप से सुनीं आमजन की समस्याएं

सिंगरौली। आज दिनांक 01 सितम्बर 2026 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय सिंगरौली में पुलिस अधीक्षक द्वारा जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से आए आवेदकों एवं फरियादियों ने अपनी समस्याओं और शिकायतों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। पुलिस अधीक्षक ने प्रत्येक फरियादी से व्यक्तिगत रूप से संवाद कर उनकी समस्याओं को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुना। कई शिकायतों पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई कराई गई, जबकि अन्य प्रकरणों में निष्पक्ष जांच एवं त्वरित वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए संबंधित राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों एवं चौकी प्रभारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। महिला फरियादियों की शिकायतों को विशेष प्राथमिकता देते हुए महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा उनकी काउंसलिंग कराई गई तथा समस्याओं के शीघ्र एवं प्रभावी निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। जनसुनवाई के दौरान नगर पुलिस अधीक्षक विंध्यनगर हेमन्त कुमार , थाना प्रभारी नवानगर राकेश साहू,थाना प्रभारी विंध्यनगर अर्चना दिवेदी, महिला थाना प्रभारी आराधना सिंह परिहार, चौकी प्रभारी खुटार शीतला यादव सहित अन्य पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। सिंगरौली पुलिस आमजन की समस्याओं के संवेदनशील, पारदर्शी एवं त्वरित निराकरण के लिए सदैव प्रतिबद्ध है।

खाखन पुल का पुलिस अधीक्षक ने लिया जायजा

सिंगरौली। लगातार वर्षा एवं जलप्रवाह के कारण प्रभावित खाखन पुल पर आवश्यक मरम्मत कार्य के उपरांत वर्तमान में मार्ग को दो पहिया एवं छोटे चार पहिया वाहनों के आवागमन योग्य बनाया गया है। पुल की वर्तमान स्थिति एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारी एवं बड़े वाहनों का खाखन पुल से आवागमन नहीं किया जाए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक सिंगरौली षियाज के.एम. स्वयं खाखन पुल पहुंचे तथा मौके पर यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। भारी वाहनों के कारण उत्पन्न जाम की स्थिति को देखते हुए उन्होंने वाहन चालकों से संवाद कर आवश्यक समझाइश दी तथा निर्धारित वैकल्पिक मार्गों से ही आवागमन करने के लिए कहा। मौके पर उपस्थित एसडीओपी देवसर गायत्री तिवारी एवं थाना प्रभारी जियावन राजेश मिश्रा को क्षेत्र में समय-समय पर स्वयं पेट्रोलिंग कर यातायात एवं मार्ग की स्थिति पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही भारी वाहन चालकों को खाखन पुल की ओर जाने से रोकते हुए उन्हें निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने हेतु आवश्यक समझाइश एवं मार्गदर्शन देने के लिए कहा गया।

हिंडालको महान में दो वरिष्ठ अधिकारियों की भावभीनी विदाई

संजय चतुर्वेदी एवं राजेश पाल के लंबे सेवाकाल को किया गया याद

बरगँवा। हिंडालको महान में लंबे एवं समर्पित सेवाकाल के बाद सेवानिवृत्त हो रहे वरिष्ठ अधिकारियों संजय चतुर्वेदी एवं राजेश पाल के सम्मान में शीर्ष प्रबंधन द्वारा भावपूर्ण विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उनके योगदान, कार्यशैली, अनुभव और सहकर्मियों के साथ आत्मीय संबंधों को याद करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। संजय चतुर्वेदी ने वर्ष 1986 में आदित्य बिरला समूह में ट्रेनी इंजीनियर के रूप में अपनी सेवा यात्रा शुरू की और लगभग 40 वर्षों तक संगठन को सेवाएं दीं। उन्होंने ऑपरेशंस, मेंटेनेंस, प्रोजेक्ट्स एवं मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्थापना, कमीशनिंग एवं स्थिरीकरण में उनकी भूमिका उल्लेखनीय रही।

वहीं राजेश पाल ने 4 मार्च 1992 को आदित्य बिरला समूह के साथ अपनी सेवा यात्रा शुरू की और लगभग 34 वर्षों तक संगठन को अपनी सेवाएं दीं। रेनुकूट एवं महान इकाइयों में उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग, प्लानिंग एवं ऑपरेशंस के क्षेत्र में विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नॉन-मैनेजमेंट कैडर से शुरुआत कर मैनेजर, ॅ॥ स्द्गह्1द्बष्द्गह्य, स्द्वद्मद्यह्वद्गह्ल क्रथ्ह्वह्लभ्शथ्द्ब तक का उनका सफर मेहनत और समर्पण का उदाहरण रहा। इस अवसर पर इकाई प्रमुख लिनु पंचमन ने कहा कि दोनों अधिकारियों का लंबा सेवाकाल संगठन के प्रति उनकी निष्ठा और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि उनके अनुभव, नेतृत्व और कार्य के प्रति समर्पण की कमी संस्था को महसूस होगी। स्मेल्टर हेड एस. शशि कुमार ने दोनों अधिकारियों की तकनीकी दक्षता, अनुशासन और टीम भावना की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने अपने अनुभव से कार्यस्थल पर सकारात्मक कार्यसंस्कृति को मजबूत किया। पावर प्लांट हेड प्रांजल पाठक ने कहा कि दोनों अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा एवं स्वामित्व की भावना के साथ निभाया और उनका कार्यकाल नई पीढ़ी के कर्मचारियों के लिए प्रेरणादायक रहेगा। समारोह में रोहित मतेती , गौरव वर्मा, निर्दोष कुमार, रंधीर वत्स, प्रणव सोनी, संजय सिंह, प्रतीक बाजपेयी , राम जतन गुप्ता,सुनील चौबे, अनिल सिंह, सूर्यकांत नायक, पी.के. बोस, दीपक सोनी, अभिषेक उर्मलिया, प्रियंका शर्मा, दीपक तिवारी, दिग्विजय सिंह, विवेक शर्मा, अर्चना, जेनी एवं श्वेता सहित अन्य अधिकारी एवं सहकर्मी उपस्थित रहे। इस दौरान उपस्थित सभी सहयोगियों ने अपने-अपने आत्मीय एवं भावपूर्ण वक्तव्यों के माध्यम से संजय चतुर्वेदी एवं राजेश पाल के साथ कार्य करने के अनुभव साझा किए। वक्ताओं ने दोनों अधिकारियों के सरल व्यवहार, सहयोगी कार्यशैली, अनुभव और संगठन के प्रति समर्पण की सराहना करते हुए उन्हें जीवन की नई पारी के लिए बेहतर कल, स्वस्थ जीवन, सुख-समृद्धि और सफलता की शुभकामनाएं दीं। विदाई अवसर पर संजय चतुर्वेदी ने भावुक होते हुए कहा कि लगभग चार दशक का यह सफर उनके जीवन की महत्वपूर्ण यात्रा रहा है और हिंडालको परिवार से मिले स्नेह, सहयोग एवं अनुभव को वे हमेशा अपनी अमूल्य पूंजी के रूप में संजोकर रखेंगे।

राजेश पाल ने भी सभी वरिष्ठ अधिकारियों एवं सहकर्मियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 34 वर्षों के इस सफर में उन्हें संस्था से बहुत कुछ सीखने और अनेक आत्मीय रिश्ते बनाने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि हिंडालको परिवार की यादें हमेशा उनके साथ रहेंगी।समारोह का माहौल भावनात्मक होने के साथ-साथ आत्मीय और यादगार रहा। अंत में प्रबंधन एवं सहकर्मियों ने दोनों सेवानिवृत्त अधिकारियों को सम्मानपूर्वक विदाई देते हुए उनके स्वस्थ, सुखी, समृद्ध एवं बेहतर भविष्य की मंगलकामना की।

बैढ़न से सीधी जाने वाले भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग

सिंगरौली। पुलिस द्वारा भारी वाहन स्वामियों एवं चालकों से अपील की जाती है कि खाखन पुल की ओर से भारी वाहन लेकर न जाएं तथा निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का ही उपयोग करें। इससे यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के साथ-साथ संभावित दुर्घटनाओं से भी बचा जा सकेगा। लगातार बारिश के दौरान नदी-नालों, पुल-पुलियों, रपटों एवं तेज बहाव वाले क्षेत्रों के आसपास अनावश्यक रूप से न जाएं। किसी भी स्थान पर सड़क अथवा पुल के ऊपर पानी बह रहा हो तो पैदल, दोपहिया या चारपहिया वाहन से उसे पार करने का प्रयास न करें। बच्चों एवं बुजुर्गों को जलभराव एवं तेज बहाव वाले स्थानों से दूर रखें। यात्रा से पूर्व जानकारी अवश्य लें तथा मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों एवं प्रशासन द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें।

शहर में पहुंचते ही मेरा स्वागत गड्ढों से हुआ सड़कों की हालत खस्ताहाल आयुक्त

बोले सतना को आत्मनिर्भर और गड्ढा.मुक्त बनाना है प्राथमिकता

सतना स्वतंत्रमत । नगर पालिक निगम सतना के नवागत आयुक्त डॉ.नागार्जुन बी गौड़ा ने सोमवार को पदभार ग्रहण करते ही शहर की बदहाल व्यवस्थाओं पर सीधा हमला बोला। कार्यभार संभालने के कुछ घंटों के भीतर ही उन्होंने निगम के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली और दो टूक शब्दों में कहा कि काम नहीं करने वालों की अब खैर नहीं। विशेष बातचीत में नवागत आयुक्त ने कहा कि शहर में पहुंचते ही मेरा स्वागत गड्ढों से हुआ। यहां की सड़कों की हालत काफी खराब है। 15 दिन की बारिश भी ये सड़कें नहीं झेल पाई इससे साफ है कि निर्माण की गुणवत्ता में भारी लापरवाही बरती गई है। उन्होंने बताया कि शहर के कई हिस्सों में जलभराव की समस्या विकराल है। बरदाडीह पन्ना नाका और जिगनहट जैसे इलाकों का उन्होंने खुद दौरा किया। नदी.नालों के किनारे जाकर जलस्तर देखा और अधिकारियों को निर्देश दिए कि पंप सेट तैयार रखें नालों की सफाई युद्धस्तर पर करें और अतिक्रमण तत्काल हटाएं।

ठेकेदारों पर होगी सख्त कार्रवाई

आयुक्त ने सबसे बड़ा सवाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के करोड़ों रुपये के बजट पर उठाया। उन्होंने कहा कि इतना पैसा खर्च होने के बाद भी अगर सड़कों की यह हालत है तो यह गंभीर जांच का विषय है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पिछले 3 सालों में बनी सभी सड़कों के एस्टीमेट और वर्क ऑर्डर निकालकर गुणवत्ता की जांच कराई जाए। दोषी ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और उनसे वसूली भी की जाएगी।

आयुक्त डॉ. गौड़ा ने अपनी 5 प्राथमिकताएं बताईं

शहर को गड्ढा.मुक्त बनाना और सड़कों का मेंटेनेंस,जलभराव से स्थायी निजात और नालों की सफाई। नगर निगम की आय बढ़ाकर शहर को आत्मनिर्भर बनाना। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और पारदर्शी व्यवस्था। नागरिकों की समस्याओं का 48 घंटे में निराकरण। उन्होंने कहा कि शहर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नगर निगम के राजस्व स्त्रोतों को बढ़ाया जाएगा। अवैध वसूली बंद होगी और टैक्स प्रणाली को सरल किया जाएगा।

अधिकारियों में हड़कंप

पहली ही बैठक में आयुक्त के तल्ख तेवर देख निगम के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। उन्होंने साफ कहा है कि अब फाइलें टेबल पर नहीं घूमेंगी। अधिकारी फील्ड में दिखेंगे। सुबह 10 बजे से पहले सभी अधिकारी अपने वार्डों में भ्रमण करेंगे और जनता से सीधे संवाद करेंगे। नवागत आयुक्त की इस कार्यशैली की शहर में जमकर सराहना हो रही है।

एनसीएल केंद्रीय अस्पताल, मोरवा में डायलिसिस सेवा फिर से शुरू

सिंगरौली।

भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) एनसीएल के मोरवा स्थित केंद्रीय चिकित्सालय में डायलिसिस सेवा को तकनीकी मरम्मत के बाद एक बार फिर से पूर्ण रूप से सुचारू कर दिया गया है। मशीनों के पुनः चालू होने से सिंगरौली परिक्षेत्र के किडनी रोग से पीड़ित मरीज इस सेवा का लाभ ले सकेंगे।डायलिसिस मशीन यूनिट, किडनी की बीमारी से ग्रस्त मरीजों को रक्त शोधन (ब्लड प्यूरिफिकेशन) सुविधा प्रदान करने में मदद करती है। इस सुविधा के पुनः बहाल होने से स्थानीय मरीजों को इलाज में सुविधा मिलेगी। गौरतलब है कि एनसीएल अपने तीन अस्पतालों व परियोजनाओं की डिस्पेंसरी के माध्यम से कर्मियों व हितग्राहियों को बेहतर इलाज मुहैया करवाने हेतु सदैव प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में एनसीएल ने अपने मोरवा स्थित केंद्रीय अस्पताल में डायलिसिस सेंटर की शुरुआत की थी जिसमें कंपनी द्वारा 2 मशीनें स्थापित की गई थीं।

जनसुनवाई में कमिश्नर ने सुनीं लोगों की समस्याएं अधिकारियों को दिए निराकरण के निर्देश

शहडोल। संभागायुक्त ने मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में शहडोल संभाग के दूर-दराज क्षेत्रों से पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों की जांच कर नियमानुसार त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में शहडोल जिले के ग्राम बहेरहा, पंचायत ददरा टोला निवासी रामकृपाल यादव ने ग्राम पंचायत में निर्माण कार्यों में कथित वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत करते हुए जांच की मांग की। उन्होंने नवीन तालाब निर्माण सहित ग्राम ददरा टोला में पिछले वर्षों में कराए गए निर्माण कार्यों की जांच कराने का आग्रह किया। मामले में कमिश्नर ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत शहडोल को शिकायत की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार जनपद पंचायत गोहपारू के ग्राम सेमरा, लामर निवासी छोटेलाल बैगा ने प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत आवास का लाभ नहीं मिलने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि आवास के लिए आवेदन देने के बावजूद सूची में उनका नाम दर्ज नहीं हुआ है। कमिश्नर ने जिला पंचायत सीईओ को आवेदन की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील के ग्राम खिरनी निवासी भीम सिंह उइके ने अपने पुत्र के नाम पर कथित रूप से फर्जी तरीके से साइकिल एवं निःशुल्क पुस्तकों का लाभ दर्शाए जाने की शिकायत की। उन्होंने शासकीय हाईस्कूल सरफा के प्रभारी प्राचार्य पर अनियमितता के आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग की।

बाढ़ प्रभावित चित्रकूट में ग्रामोदय विश्वविद्यालय के स्वयंसेवकों ने चलाया स्वच्छता अभियान

सतना स्वतंत्रमत।

चित्रकूट क्षेत्र में मंदाकिनी नदी में आई विकराल बाढ़ के बाद जनजीवन प्रभावित है। बाढ़ का पानी उतरने के बाद मकानों एवं आसपास के क्षेत्रों में जमा मिट्टी मलबे और अन्य सामग्री को हटाने के लिए शासकीय एवं सामाजिक स्तर पर चलाए जा रहे श्रमदान अभियान में महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने भी सक्रिय सहभागिता की। विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. आलोक चौबे के निर्देश पर राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर श्रमदान किया तथा स्वच्छता अभियान में सहयोग प्रदान किया। स्वयंसेवकों ने प्रभावित क्षेत्रों में जमा मिट्टी एवं अन्य सामग्री को हटाने में स्थानीय लोगों के साथ मिलकर योगदान दिया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के शिक्षक भी स्वयंसेवकों के साथ श्रमदान अभियान में शामिल हुए। बाढ़ जैसी आपदा के बाद प्रभावित लोगों के साथ खड़े होकर स्वच्छता एवं राहत कार्यों में सहयोग की यह पहल ग्रामोदय विश्वविद्यालय की सामाजिक प्रतिबद्धता एवं सामुदायिक सहभागिता की भावना को प्रदर्शित करती है। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने कहा कि संकट की इस घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा होना और उनके आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाने में सहयोग करना सामाजिक दायित्व है।

विश्वविद्यालय की ओर से भविष्य में भी आवश्यकता के अनुरूप जनसहयोग एवं सेवा गतिविधियों में सहभागिता की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।

नाम परिवर्तन सूचना

मैं राजेश चौरे पिता श्री नारायण चौरे निवासी ग्राम बडगाँव तह. आमला जिला बैतूल मध्यप्रदेश शपथपूर्वक निम्न घोषणा करता हूँ। मुझे अपनी पुत्री का मैन्यूअल जन्म प्रमाण पत्र से डिजीटल जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है। पुत्री के मैन्यूअल जन्म प्रमाण पत्र क. 32 रजि. क. 1831 दिनांक 10/09/2012 में पुत्री का नाम तनिषि उर्फ आर्या दर्ज है जो कि तनिषि गौत्र दर्ज हो गया है पुत्री का सही नाम आर्या चौरे (AARYA CHAURE) जो कि आधार के अनुसार होना है। पुत्री का जन्म दिनांक 23/08/2012 अग्रवाल हास्पिटल नरसिंहपुर में हुआ है। शपथकर्ता की पुत्री का नाम आर्या चौरे (AARYA CHAURE) है। पिता का नाम राजेश चौरे (RAJESH CHAURE) है माता का नाम वंदना चौरे (VANDANA CHAURE) है। शपथकर्ता की पुत्री को तनिषि और आर्या दोनो नामों से जाना व पहचाना जाता । दोनो नाम एक ही महिला के है। शपथकर्ता की पुत्री का नाम आर्या चौरे होना है। आर्या चौरे जन्मरिकार्ड में पता ग्राम मेहगवां तह. तेन्दूखेड़ा दर्ज जो कि ननिहाल का पता है सही पता ग्राम बड़गांव तह.आमला जिला बैतूल पिन कोड 460554 दर्ज होना है।

शपथकर्ता

मेधावी विद्यार्थियों के सपनों को मिली नई उड़ान

मुख्यमंत्री ने कटनी के 1737 छात्रों के खातों में अंतरित किए 4.34 करोड़ रुपए

कटनी (स्वतंत्रमत)

प्रतिभा को प्रोत्साहन और विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा के संसाधनों से जोड़ने की दिशा में राज्य सरकार की प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत मंगलवार को कटनी जिले के 1737 मेधावी विद्यार्थियों के बैंक खातों में प्रति विद्यार्थी 25 हजार रुपए की राशि अंतरित की गई। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय मुख्य समारोह से विद्यार्थियों के खातों में यह राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। जिले के विद्यार्थियों को कुल 4 करोड़ 34 लाख 25 हजार रुपए की राशि का लाभ मिला। इस अवसर पर शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माधवनगर

कटनी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने भोपाल में आयोजित मुख्य समारोह का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के संबोधन सहित सीधा प्रसारण देखा और सुना। मुख्यमंत्री द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने, तकनीक का सदुपयोग करने और अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों में खासा उत्साह नजर आया। लैपटॉप के लिए मिली प्रोत्साहन राशि से विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन अध्ययन, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और तकनीकी ज्ञान अर्जित करने में सुविधा मिलेगी। यह योजना विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ तकनीक से जोड़कर उनके भविष्य को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम में सहायक संचालक शिक्षा राजेश अग्रहरि, संस्था के प्राचार्य, शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

महापौर जनसुनवाई में नागरिकों ने रखीं अपनी समस्याएं

महापौर सूरी ने अधिकारियों से ली प्रकरणों की जानकारी

कटनी (स्वतंत्रमत)

नगर निगम कार्यालय में मंगलवार 1 सितंबर को आयोजित महापौर जनसुनवाई में शहर के विभिन्न वार्डों से नागरिक अपनी समस्याओं और शिकायतों को लेकर पहुंचे। महापौर श्रीमती प्रीति संजीव सूरी ने नागरिकों से सीधे संवाद करते हुए उनकी समस्याओं को सुना तथा संबंधित अधिकारियों से प्रकरणों की जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। जनसुनवाई में नागरिकों द्वारा पेंशन, साफ-सफाई, सड़क, नाली, पेयजल सहित नगर निगम से जुड़े विभिन्न विषयों को लेकर आवेदन प्रस्तुत किए गए। महापौर ने प्राप्त आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई कर नागरिकों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। महापौर श्रीमती सूरी ने कहा कि नागरिकों की समस्याओं को सीधे सुनना और उनके समाधान की दिशा में प्रभावी कार्रवाई करना जनसुनवाई का प्रमुख उद्देश्य है। नगर निगम द्वारा नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने और शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। महापौर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों को प्राथमिकता के साथ लेते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही प्रकरणों के निराकरण की स्थिति की मॉनिटरिंग भी की जाए, ताकि नागरिकों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने बताया कि नगर निगम और नागरिकों के बीच सीधा संवाद शहर की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध एवं संतोषजनक निराकरण नगर निगम की प्राथमिकता है।

चौकी झिंझरी पुलिस के द्वारा मारपीट करने वाले आरोपियों को अभिरक्षा में लिया

कटनी (स्वतंत्रमत)

पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य, उप पुलिस अधीक्षक सुश्री शिवा पाठक एवं थाना प्रभारी माधवनगर शैलेन्द्र सिंह यादव के मार्गदर्शन में पुलिस चौकी झिंझरी द्वारा मारपीट करने बाले आरोपियों को वैधानिक कार्यवाही उपरांत अभिरक्षा में लिया गया। दिनांक 30.08.2026 को प्रार्थी विक्रम तिवारी पिता प्रहलाद तिवारी उम्र 38 साल निवासी ग्राम गनियारी थाना माधवनगर जिला कटनी के व्दारा रिपोर्ट की गई कि दिनांक 30.08.2026 को मेरा प्रेमलाल वर्मन के लडके से उधारी

सामान लेने पर विवाद हुआ था इसी बात को लेकर शाम करीब 05.30 बजे प्रेमलाल बर्मन, उसका लडका आशीष बर्मन, भाई विजय वर्मन तथा भतीजा विकास वर्मन चारों के व्दारा शासकीय स्कूल गनियारी के सामने माँ बहन की गंदी गंदी गाली देकर लाठी डंडे से मारपीट की गई तथा मोटरसायकल भी क्षतिग्रस्त कर दी गई। रिपोर्ट पर थाना माधवनगर मे अपराध क्रमांक 884/26 धारा 296 बी 115(2) 351(3) 324, 4 3 5 बीएनएस का अपराध कायम कर विवेचना मे लिया गया। दौरान विवेचना आरोपियों की पता तलाश के हर संभव प्रयास किये जाकर दिनांक 01.09.2026 को आरोपीगण प्रेमलाल वर्मन, विजय वर्मन, विकास वर्मन तथा विधि विरुद्ध बालक की तलाश की जाकर अभिरक्षा मे लेकर पूँछताछ कर घटना मे प्रयुक्त आलाजर्ब की जप्ती की गई। मामले के आरोपी प्रेमलाल वर्मन एवं फरियादी विक्रम तिवारी के पूर्व के भी आपराधिक रिकॉर्ड है जिनके विरुद्ध पूर्व में भी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा चुकी है। इस कार्यवाही में चौकी प्रभारी उनि राजेश कुमार दुबे के नेतृत्व में सउनि सतीश भगत, प्रधान आरक्षक पंकज त्रिपाठी, आर. संजय यादव, आर. अजय सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार एवं बाजरा उपार्जन के लिए किसान पंजीयन 15 सितम्बर से

कटनी (स्वतंत्रमत)

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार एवं बाजरा उपार्जन के लिए किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया 15 सितम्बर से 10 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित की गई है। उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय भोपाल के अनुसार किसान पंजीयन की कार्यवाही निर्धारित अवधि में की जाएगी। पंजीयन प्रक्रिया के तहत भूमि स्वामी, सिकमी, बटाईदार, कोटवार एवं वन पट्टाधारी किसानों के पंजीयन, डाटा संशोधन एवं पंजीयन सत्यापन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

सिकमी,बटाईदार किसानों को समर्थन मूल्य पर अपनी उपज विक्रय करने के लिए पंजीयन कराने हेतु मूल भूमिस्वामी एवं सिकमी, बटाईदार किसान के बीच मध्यप्रदेश भूमिस्वामी एवं बटाईदार के हितों का संरक्षण विधेयक, 2016 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध होना अनिवार्य है। यह अनुबंध 15 सितम्बर 2026 के पूर्व निष्पादित होना आवश्यक है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अनुबंध की अवधि अधिकतम 5 वर्ष हो सकती है। जिन किसानों ने सिकमी, बटाई पर ली गई कृषि भूमि में इस वर्ष धान, ज्वार अथवा बाजरा की फसल बोई है और वे अपनी उपज समर्थन मूल्य पर विक्रय करना चाहते हैं, वे निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए निर्धारित प्रारूप में अनुबंध तीन प्रतियों में अतिशीघ्र निष्पादित कराना सुनिश्चित करें।

15 सितम्बर के बाद का अनुबंध मान्य नहीं होगा

विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि 15 सितम्बर 2026 के बाद निष्पादित सिकमी, बटाई अनुबंध इस वर्ष समर्थन मूल्य पर किसान पंजीयन तथा धान, ज्वार एवं बाजरा के विक्रय के लिए मान्य नहीं होगा। अत: संबंधित किसान समय-सीमा का विशेष ध्यान रखते हुए आवश्यक अनुबंध की प्रक्रिया समय पर पूर्ण कराएं।

जनसुनवाई में कलेक्टर ने सुनीं 73 आवेदकों की समस्याएं

अधिकारियों को समय.सीमा में गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक निराकरण के दिए निर्देश

कटनी (स्वतंत्रमत)

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर आशीष तिवारी ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे 73 आवेदकों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने प्रत्येक आवेदक की बात को गंभीरता, संवेदनशीलता और धैर्यपूर्वक सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को प्रकरणों का तथ्यात्मक परीक्षण कर समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती हरसिमरनप्रीत कौर, अपर कलेक्टर नीलांबर मिश्रा, एसडीएम कटनी जितेन्द्र पटेल, डिप्टी कलेक्टर प्रमोद चतुर्वेदी सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे। जनसुनवाई के दौरान तहसील कटनी के ग्राम पौंसरा के ग्रामीणों ने शासकीय श्मशान भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत प्रस्तुत की। तहसील ढीमरखेड़ा निवासी गुलबहार ने खपत से अधिक बिजली बिल आने, झर्रा टिकुरिया निवासी सोनिया वंशकार ने जन्म प्रमाण-पत्र बनवाने, ग्राम डिठवारा निवासी अमित विश्वकर्मा ने रिकॉर्ड सुधार करने तथा तिगवा निवासी दिव्यांग आवेदक रामसनेह लोधी ने आर्थिक सहायता एवं शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के संबंध में आवेदन दिया। इसी प्रकार ग्राम पड़रिया निवासी नंदनी ठाकुर ने अनुकंपा नियुक्ति, ग्राम कांटी निवासी दद्दी चौधरी ने पीएम किसान योजना की राशि नहीं मिलने तथा आधारकाप कटनी निवासी जयश्री शर्मा ने कैंसर पीड़ित पति के उपचार के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। कलेक्टर श्री तिवारी ने संबंधित अधिकारियों को सभी आवेदनों का परीक्षण कर नियमानुसार निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई में प्राप्त आवेदन केवल दर्ज करने तक सीमित न रहें, बल्कि प्रत्येक प्रकरण के न्यायसंगत और स्थायी समाधान की दिशा में प्रभावी कार्रवाई की जाए। किसी भी नागरिक को अपनी समस्या के समाधान के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उन्हें समय पर राहत उपलब्ध कराई जाए।

जेपीवी डीएवी विद्यालय में संस्कृत एवं वेद प्रचार सप्ताह मनाया गया

कटनी (स्वतंत्रमत)

जेपीवी डीएवी विद्यालय में वेद प्रचार सप्ताह का भव्य शुभारंभ मध्यप्रदेश जोन के क्षेत्रीय निदेशक एवं विद्यालय प्राचार्य एस के सिन्हा के निर्देशन में दीप प्रज्ज्वलन, वेद पूजन एवं मनमोहक स्वागत गीत महामहनीय मेधाविन के द्वारा हुआ। जिसमें संस्कृत भाषा एवं वेदों के प्रचार-प्रसार हेतु विविध कार्यक्रम आयोजित किये गये, तत्पश्चात प्रतिदिन विद्यार्थियों के लिए सरल संस्कृत संभाषण हेतु विषय सामग्री प्रेषित की गई।

इसी क्रम में विद्यार्थियों द्वारा संस्कृत श्लोक गायन, गीत गायन, संभाषण, श्लोक गायन प्रतिस्पर्धा, रमणीया ही सृष्टि ही ऐष। नाटिका, दिव्या गीर वाण भारती संस्कृत परिचय माला की प्रस्तुतियाँ हुईं । शुभकामना संदेशों के साथ विश्व संस्कृत दिवस पर विद्यार्थियों ने अपने निवास स्थल पर सभी को संस्कृत संभाषण हेतु प्रेरित किया।

अंतिम दिवस पर संस्कृत भाषा एवं वेदों के प्रचार का संकल्प करते हुए संस्कृत सप्ताह का समापन हुआ तथा विद्यालय के सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं ने अन्य गतिविधियों में सहयोग करते हुए हर्ष व्यक्त किया। प्राचार्य ने संस्कृत भाषा की वैज्ञानिकता पर प्रकाश डालते हुए इस भाषा को दैनिक व्यवहार की भाषा बनाने पर बल दिया एवं संस्कृत सप्ताह की सफलता हेतु शुभकामनाएं प्रेषित कीं।

हर शिकायत पर किए जा रहे है त्वरित व उचित समाधान के हरसंभव प्रयास

कटनी (स्वतंत्रमत)। मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार आमजन की शिकायतों के त्वरित निराकरण एवं समस्याओं के प्रभावी समाधान हेतु प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाली जनसुनवाई के क्रम में एसपी अभिनय विश्वकर्मा द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में आमजन की समस्याओं को सुन त्वरित निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। जनसुनवाई में प्रमुख रूप से पति-पत्नी व बेटा-बहू संबंधी आपसी पारिवारिक विवाद, आपसी मतभेद, साइबर/फाइनेंशियल फ्रॉड, सुनवाई न होने की शिकायतें, प्लॉट, मकान, जमीन संबंधी धोखाधड़ी, महिला अपराध एवं अन्य पुलिस संबंधित प्रकरण शामिल रहे। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रत्येक आवेदक की समस्याओं एवं व्यथा को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित अधिकारियों को समक्ष में एवं फोन के द्वारा भी त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही कर शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। साथ ही आमजन को आश्वस्त किया कि कटनी पुलिस उनकी सुरक्षाए न्याय और अधिकारों के संरक्षण हेतु सदैव प्रतिबद्ध है।

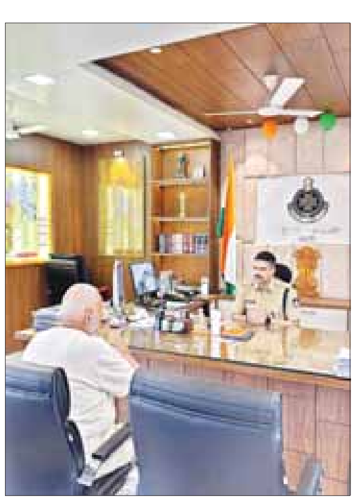

राहुल गांधी के विरुद्ध दर्ज प्रकरण वापस लेने की मांग को लेकर कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

कटनी (स्वतंत्रमत)

मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी कटनी द्वारा राहुल गांधी के विरुद्ध दर्ज प्रकरण को तत्काल वापस लेने की मांग को लेकर मंगलवार 01 सितंबर को जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट कार्यालय में विरोध प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेसजनों ने कहा कि राहुल गांधी देश के प्रमुख विपक्षी नेता हैं, जो लगातार जनता के मुद्दों, लोकतांत्रिक अधिकारों और संविधान की रक्षा के लिए अपनी आवाज मजबूती से उठाते रहे हैं। लोकतंत्र में सरकार से सवाल करना और जनहित के विषयों को प्रमुखता से उठाना विपक्ष का संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक दायित्व है।

जिला कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष एड. अमित शुक्ला ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाने के बजाय उसका सम्मान किया जाना चाहिए। राहुल गांधी सदैव आम जनता के अधिकारों और संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहे हैं। उनके विरुद्ध दर्ज प्रकरण लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति गंभीर चिंता का विषय है। जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण अध्यक्ष सौरभ सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए हमेशा संघर्ष करती रही है। जनहित के मुद्दे उठाना किसी भी विपक्षी नेता का अधिकार है और इस अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की कि राहुल गांधी के विरुद्ध दर्ज प्रकरण को तत्काल वापस लिया जाए। ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेसजनों ने राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करते हुए राहुल गांधी के विरुद्ध दर्ज प्रकरण को तत्काल वापस लिए जाने तथा लोकतंत्र, संविधान एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गरिमा बनाए रखने की मांग की। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष एड अमित शुक्ला ग्रामीण अध्यक्ष सौरभ सिंह, राजकुमार केलु उपाध्याय, राकेश जैन कक्का, करन सिंह चौहान, रजनी वर्मा, राजा जगवानी, गोल्डन पांडे, प्रेम बत्रा, जालेम यादव, आफताब अहमद, राजेश जाटव, जितेन्द्र गुप्ता, अजय जैसवानी, पंकज गौतम, कमल पांडे, आनंद पटेल, मंगल सिंह, अजय खटीक, विजय मंगल चौधरी, नारायण निषाद, सुशील जायसवाल, विकास निगम, छोटू सिंह बघेल, इस्तियाक अहमद, राहुल होतवानी, राहुल पटेरिया, संजय गुप्ता, रमेश अहिरवार, भरत विश्वकर्मा, जार्ज डेविड, रॉबिन पीटर, शशि शेखर भारद्वाज, विनीत जायसवाल, रमेश मिश्रा, रवि जायसवाल, घनश्याम रजक, रूपा तिवारी, शशि यादव, दिलदार खान, इमरान खान, विजय चांदवानी, सुनील श्रीवास, सलाहुद्दीन खान, रामचंद मूलवानीं, विकास चौधरी, राजेश निषाद, प्रिंस खटीक, शुभम सोनखरे, हर्षित मिश्रा, साहिल नामदेव एवं समस्त कांग्रेसजन उपस्थित रहे।

दलीप ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा ईस्ट जोन

डिफेंडिंग चैंपियन सेंट्रल जोन को 4 विकेट से हराया, सूर्यवंशी ने 92 और 40 रन बनाए

नई दिल्ली। दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में मंगलवार को ईस्ट जोन ने डिफेंडिंग चैंपियन सेंट्रल जोन को 4 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही टीम ने फाइनल में जगह बना ली, जहां उसका मुकाबला दूसरे सेमीफाइनल की विजेता टीम से होगा। ईस्ट जोन को जीत के लिए 159 रन का टारगेट मिला था, जिसे टीम ने टेस्ट मैच के तीसरे दिन 80.1 ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान ईशान किशन 39 और मोहम्मद शमी 8 रन बनाकर नाबाद लौटे। टीम के उपकप्तान वैभव सूर्यवंशी ने 40 रन की पारी खेली। वैभव ने पहली पारी में 7 चौके और 7 छक्कों के साथ 92 रन बनाए थे। सेंट्रल जोन की शुरुआत खराब रही और 37 रन तक टीम के तीन विकेट गिर गए। कप्तान रजत पाटीदार 5 और रिंकू सिंह 20 रन ही बना सके। 95 रन तक 7 विकेट गंवाने के बाद अरशद खान ने लोअर ऑर्डर के साथ मिलकर टीम को 150 रन के पार पहुंचाया। हालांकि टीम 158 रन पर ही सिमट गई। अमन मोखाड़े ने टीम के लिए सबसे ज्यादा 41 रन बनाए। अरशद खान ने 25 और हर्ष दुबे ने 24 रन की पारी खेली।

मुकेश कुमार को 4, शमी को 3 विकेट

ईस्ट जोन की ओर से मुकेश कुमार सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 12 ओवर में 44 रन देकर 4 विकेट लिए। मोहम्मद शमी ने 3, जबकि अभिजीत सरकार, अनुकूल रॉय और कुनैन कुरैशी ने 1-1 विकेट लिया। मोहम्मद शमी ने दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल के पहले दिन बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। ईस्ट जोन की ओर से खेल रहे शमी ने सेंट्रल जोन के खिलाफ 3 विकेट लेकर प्रोफेशनल क्रिकेट में अपने 900 विकेट पूरे किए।

ईस्ट जोन से पहली पारी में सूर्यवंशी का अर्धशतक

सेंट्रल जोन और ईस्ट जोन की पहली पारी बराबरी पर रही। दोनों टीमों ने 266 रन बनाए। ईस्ट जोन के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 92 और अभिमन्यु ईश्वर ने 69 रन बनाए। दोनों ने पहले विकेट के लिए 161 रन जोड़े। हालांकि, इसके बाद ईस्ट जोन ने अगले 104 रन में अपने सभी विकेट गंवा दिए। सेंट्रल जोन की ओर से हर्ष दुबे ने 4, जबकि आर्यन पांडे और यश ठाकुर ने 3-3 विकेट लिए।

मेसी का इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास

इंस्टाग्राम पर हाथ से लिखा नोट पोस्ट किया, लिखा- सब कुछ दे दिया, अब कुछ बाकी नहीं

नई दिल्ली। हाथ से लिखा 230 शब्दों का एक नोट... और एक ऐसा फैसला, जिसका इंतजार शायद कोई फुटबॉल फैन नहीं कर रहा था। दुनिया के सबसे सेलिब्रेटेड सॉकर प्लेयर लियोनेल मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल को अलविदा कह दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संन्यास का ऐलान किया। हाथ से लिखा यह नोट सिर्फ इंटरनेशनल फुटबॉल छोड़ने का ऐलान नहीं था, बल्कि उस सफर का आखिरी पन्ना था, जो 2005 में शुरू हुआ था। ये अर्जेंटीना की उस जर्सी को अलविदा कहने का ऐलान भी था, जिसके लिए मेसी ने कहा था- मैने इसके लिए अपना सब कुछ दे दिया। लेकिन, 39 साल के मेसी के लिए यह फैसला अचानक नहीं था। वर्ल्ड कप फाइनल के दो दिन बाद, 21 जुलाई को ही उन्होंने संन्यास का फैसला लिखकर रख लिया था। इस मुकाबले में अर्जेंटीना को स्पेन से हार मिली थी। मेसी अर्जेंटीना के लिए आखिरी बार इसी मैच में खेले थे।मेसी ने लिखा कि यह फैसला लेना तकलीफदेह था। मैदान से हटने की बाद उनके दिल के अंदर तक दुख देती है, लेकिन लगता है कि अब ऐसा करने का समय आ गया है।

'नेशनल टीम का चैप्टर खत्म अपना सब कुछ दे चुका'

मेसी ने उस जर्सी को याद किया, जिसके लिए उन्होंने हमेशा संघर्ष किया। उन्होंने लिखा कि समय कम बचा है। हर चैप्टर खत्म होता है और नेशनल टीम का चैप्टर भी अब खत्म हो रहा है। उन्होंने कहा कि अर्जेंटीना कीटीम का हिस्सा बनना उन्हें पसंद था, पसंद है और हमेशा रहेगा। फिर उन्होंने वह बात लिखी, जो शायद इस फैसले की सबसे बड़ी वजह है।

वैभव सूर्यवंशी भारत की टी-20 टीम में बरकरार

अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज के लिए टीम घोषित, अय्यर कप्तान, बुमराह की वापसी

नई दिल्ली। भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। वैभव सूर्यवंशी को एक बार फिर टीम में जगह मिली है। श्रेयस अय्यर को ही कप्तान बनाया गया है, जबकि संजू सैमसन और ईशान किशन विकेटकीपर के रूप में टीम में शामिल हैं। सीरीज का पहला मैच 13 सितंबर को खेला जाएगा। इस सीरीज के सभी मुकाबले नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होंगे।युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी लगातार चौथी सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुने गए हैं। उन्हें पहली बार आयरलैंड दौरे के लिए चुना गया था। लेकिन डेब्यू का मौका नहीं मिला। इंग्लैंड दौरे पर डेब्यू करने के बाद वैभव जिम्बाब्वे दौरे पर प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। उन्हें तीसरे मैच में प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया था। वे 6 टी-20 इंटरनेशनल मैचों में 193 रन बना चुके हैं। इनमें दो अर्धशतक शामिल हैं।

बुमराह 5 महीने बाद टी-20 इंटरनेशनल खेलेंगे

तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह सहित 7 प्लेयर्स की टीम में वापसी हुई है। इनमें नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल शामिल हैं। बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ भारत की वनडे सीरीज के दौरान घुटने में लगी चोट के कारण टीम से बाहर हो गए थे। वे श्रीलंका दौरे पर नहीं गए थे। जसप्रीत ने आखिरी टी-20 मैच 8 मार्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। जोकि टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल था।

जिम्बाब्वे दौरे पर गए 8 खिलाड़ी बाहर

जिम्बाब्वे दौरे वाली भारतीय टीम में 8 बदलाव किए गए हैं। संजू सैमसन को दोबारा चुना गया है। वे जुलाई में जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में टीम का हिस्सा नहीं थे। उनके साथ ईशान किशन को दूसरे विकेटकीपर के रूप में चुना है। रिंकू सिंह, सूर्यांश शेडगे, हर्ष दुबे, प्रभसिमरन सिंह, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, मयंक यादव और अशोक शर्मा को बाहर किया गया है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ क्लीन स्वीप किया था।

शार्दुल ठाकुर की जगह सिद्धेश लाड बने मुंबई के कप्तान

मुंबई। अनुभवी मध्यक्रम बल्लेबाज़ सिद्धेश लाड आगामी रणजी ट्रॉफ़ी सत्र में शार्दुल ठाकुर की जगह मुंबई के कप्तान होंगे, जबकि सफ़ेद गेंद के घरेलू टूर्नामेंटों में उपलब्धता के आधार पर श्रेयस अय्यर या सूर्यकुमार यादव टीम की कमान संभालेंगे। 34 वर्षीय लाड को दबाव में शांत रहने और लगातार अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता के कारण नया कप्तान चुना गया है। वह 2022-23 सीज़न में गोवा से जुड़े थे, लेकिन एक साल बाद मुंबई लौट आए। 2023-24 में अनिवार्य एक साल का कूलिंग ऑफ़ पीरियड पूरा करने के बाद उन्होंने 2024-25 में फिर से मुंबई टीम में वापसी की।लाड ने पिछले रणजी ट्रॉफ़ी सीज़न में बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया था।उन्होंने आठ मैचों में 77.40 की औसत से 774 रन बनाए, जिसमें पांच शतक और एक अर्धशतक शामिल था। 34 वर्षीय ठाकुर को उनके कार्यभार के प्रबंधन के लिए कप्तानी से हटाया गया है। मुंबई प्रबंधन उन्हें लाल गेंद की टीम के प्रमुख तेज़ गेंदबाज़ के रूप में अधिकतम उपयोग करना चाहता है।इसके अलावा वह कई अहम मौक़ों पर बल्ले से भी टीम के लिए उपयोगी योगदान देते रहे हैं।लगातार दूसरे सीजन मुंबई रणजी ट्रॉफ़ी में नए कप्तान के साथ उतरेगी। 2025-26 सत्र से पहले ठाकुर ने अजिंक्य रहाणे की जगह कप्तानी संभाली थी।

ओसाका ने सीधे सेटों में जीत के साथ शुरु किया अपना यूएस ओपन जीतने का अभियान

न्यूयॉर्क। चार बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन नाओमी ओसाका ने एनस्तासिया ज़खारोवा के खिलाफ कड़े मुकाबले में सीधे सेटों में जीत के साथ अपना तीसरा यूएस ओपन खिताब जीतने का अभियान शुरू किया।सोमवार रात आर्थर ऐश स्टेडियम में हुए मैच में ओसाका, जिन्होंने 2018 और 2020 में न्यूयॉर्क में खिताब जीता था, ने दोनों सेटों में शुरुआती बढ़त बनाई - पहले सेट में 5-2 और दूसरे में 5-3 से आगे रहीं।लेकिन दोनों ही मौकों पर, डब्ल्यूटीए टूर में 101वें नंबर की खिलाड़ी ज़खारोवा ने वापसी की और मैच को टाई-ब्रेक तक ले गईं।पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी ने पहले सेट का टाई-ब्रेक अपने तीसरे सेट पॉइंट पर 8-6 से और दूसरा सेट 7-3 से जीता, और दो घंटे से कुछ अधिक समय में जीत हासिल की।ओसाका काले रंग की पोशाक पहनकर कोर्ट पर उतरीं, जो पूर्व अमेरिकी बास्केटबॉल स्टार एलन आइवरसन को श्रद्धांजलि थी; कोर्ट पर आते समय उन्होंने पूरी तरह से सफेद गाउन पहना था। यह आइवरसन के लिए मेरा सम्मान है।

उन्नति हुड्डा पहले राउंड में बाहर

चाइना मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट

शेनझेन। भारत की उभरती हुई शटलर उन्नति हुड्डा मंगलवार को शेनझेन में महिला सिंगल्स के पहले राउंड में कोरिया गणराज्य की दुनिया की नंबर 12 किम गा-यून से हारने के बाद चाइना मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट से बाहर हो गईं। दुनिया में 25वें नंबर की 18 साल की भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के शेनझेन स्पोर्ट्स सेंटर जिम्नेजियम में 37 मिनट में 21-10, 21-18 से हार गईं।किम गा-यून ने पहले गेम में 4-0 की बढ़त बनाई और गेम के बीच में अपनी बढ़त को 11-3 कर लिया। अनुभवी कोरियाई खिलाड़ी ने ब्रेक के बाद भी कंट्रोल बनाए रखा और पहला गेम आराम से जीत लिया।उन्नति ने दूसरे गेम में ज़ोरदार वापसी की, 3-0 की बढ़त के साथ शुरुआत की। किम गा-यून 7-5 से आगे थीं, लेकिन भारतीय खिलाड़ी ने वापसी की और कुछ देर के लिए 15-14 से आगे हो गईं।गेम में बाद में 18-16 से पीछे होने पर, उन्नति ने अगले दो पॉइंट जीतकर बराबरी कर ली। हालांकि, किम गा-यून ने आखिरी तीन पॉइंट लेकर मैच अपने नाम कर लिया। उन्नति और किम गा-यून के बीच यह करियर की पहली भिड़ंत थी, जिन्होंने जून में मकाऊ ओपन का खिताब जीता था।

वाहनों की बिक्री में अगस्त में भी जारी रही जबरदस्त तेजी

नयी दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में पिछले साल सितंबर में किये गये सुधारों के बाद वाहनों की बिक्री में अगस्त में लगातार 12वें महीने मजबूत वृद्धि दर्ज की गयी।देश की सबसे बड़ी यात्री वाहन कंपनी मारुति सुजुकी की कुल घरेलू बिक्री अगस्त में 34.34 फीसदी बढ़कर 1,80,078 इकाई पर पहुंच गयी।इसमें यात्री वाहनों की बिक्री 1,76,971 इकाई और हल्के वाणिज्यिक वाहन सुपर कैरी की बिक्री 3,107 इकाई रही। इनमें क्रमशः 34.81 प्रतिशत और 12.09 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है।इसके अलावा, मारुति ने अगस्त में दूसरी कंपनी (सुजुकी) के 5,298 वाहन बेचे।निर्यात 7.37 प्रतिशत घटकर 33,844 इकाई रह गया।इस प्रकार कुल बिक्री 2,19,220 इकाई रही।यह सालाना आधार पर 21.33 प्रतिशत अधिक है।टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स की यात्री वाहनों की बिक्री अगस्त में 56 प्रतिशत बढ़कर 67,753 इकाई पर पहुंच गयी। इसमें घरेलू बिक्री 59 फीसदी की वृद्धि के साथ 65,253 इकाई और निर्यात आठ फीसदी बढ़कर 2,500 इकाई हो गया।कंपनी की इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री (निर्यात सहित) 16,549 इकाई रही जो सालाना आधार पर 94 प्रतिशत अधिक है।महिंद्रा समूह की यात्री वाहन कंपनी महिंद्रा ऑटो के उपयोगी वाहनों की बिक्री 50 फीसदी बढ़कर 59,257 इकाई हो गयी।कंपनी के वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 27,415 इकाई रही जो 22 प्रतिशत सालाना बढ़ी है।तिपहिया की बिक्री 42 प्रतिशत बढ़कर 14,922 इकाई दर्ज की गयी। कंपनी की कुल बिक्री 42 प्रतिशत बढ़कर 1,07,648 इकाई पर रही।महिंद्रा समूह के ट्रैक्टरों की कुल बिक्री (निर्यात सहित) में पांच प्रतिशत का इजाफा हुआ और यह 29,507 इकाई पर रही।

जीएसटी संग्रह अगस्त में 14.8 प्रतिशत बढ़कर 1,99,853 करोड़

नयी दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत गत अगस्त में सकल राजस्व संग्रह एक साल पहले के मुकाबले 14.8 प्रतिशत बढ़कर 1,99,853 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। अगस्त 2025 में सकल जीएसटी संग्रह 1,74,116 करोड़ रुपये रहा था।इस साल अगस्त में घरेलू जीएसटी संग्रह 9.3 प्रतिशत और आयात पर प्राप्त जीएसटी राजस्व 29 प्रतिशत बढ़ा है।घरेलू बाजार से सरकार को कुल 1,37,249 करोड़ रुपये का वस्तु एवं सेवा कर प्राप्त हुआ।वहीं निर्यात से 62,604 करोड़ रुपये की जीएसटी की प्राप्ति हुई।

मुंबई में सीएनजी दो रुपये बढ़ी

घरेलू पीएनजी एक रुपये महंगी

मुंबई। मुंबई और आसपास के शहरों में मंगलवार से सीएनजी दो रुपये प्रति किलोग्राम और घरेलू पीएनजी एक रुपये प्रति एससीएम महंगी हो गयी है। देश की वाणिज्यिक राजधानी के अलावा ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, लातूर एवं धाराशिव तथा चित्रदुर्ग और दावणगेरे में सीएनजी की आपूर्ति करने वाली कंपनी महानगर गैस लिमिटेड (एमजीएल) ने बताया कि 01 सितंबर से मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में सीएनजी की संशोधित कीमत 88 रुपये प्रति किलोग्राम होगी। पहले यह 86 रुपये प्रति किलोग्राम थी।कंपनी के बयान में कहा गया है, मध्य पूर्व में जारी संकट को देखते हुए, जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय सूचकांकों से जुड़ी इनपुट गैस की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, एमजीएल ने सीएनजी की कीमतों में संशोधन की घोषणा की है। इसके अलावा, इनपुट लागत में वृद्धि के कारण घरेलू पीएनजी की कीमत में भी एक रुपये प्रति एससीएम की वृद्धि की गयी है।एमजीएल ने बताया कि सीएजी की मांग में काफी वृद्धि हुई है और सीएनजी सेगमेंट के लिए आवश्यक इनपुट गैस का एक बड़ा हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा किया जा रहा है।इन कारणों से सीएनजी सेगमेंट के लिए इनपुट गैस की लागत में काफी वृद्धि हुई है। सीएनजी की बढ़ी हुई मांग पूरी करने के लिए एमजीएल को अब अधिक कीमत पर गैस खरीदनी पड़ रही है।बयान में कहा गया है, इनपुट गैस की बढ़ती लागत को आंशिक रूप से संतुलित करने और अपने ग्राहकों को सीएनजी की निरंतर एवं सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दाम

चीनी, चावल, गेहूं खाद्य तेलों का भाव टूट

दालों के दामों में घट-बढ़ का दौर जारी

नयी दिल्ली। घरेलू थोक जिंस बाजारों में मंगलवार को चीनी, चावल, गेहूं और खाद्य तेलों के भाव टूट गये जबकि दालों में उतार-चढ़ाव का रुख रहा।मीठे के थोक बाजार में चीनी की औसत कीमत 37 रुपये घटकर 5,803 रुपये प्रति क्विंटल रह गयी।गुड़ भी 11 रुपये फिसलकर 5,976 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा।खुदरा बाजार में चीनी की औसत कीमत 32 पैसे घटकर 62.96 रुपये प्रति किलोग्राम रह गयी।औसत दर्जे के चावल की औसत कीमत 19 रुपये घटकर 4,139 रुपये प्रति क्विंटल रह गयी।गेहूं तीन रुपये सस्ता हुआ और 2,847 रुपये प्रति क्विंटल बोला गया।आटे का भाव भी चार रुपये गिर गया।दाल-दलहनों में तुअर दाल की औसत कीमत 13 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गयी।मूंग दाल पांच रुपये और मसूर दाल चार रुपये प्रति क्विंटल महंगी हुई।वहीं, चना दाल की कीमत 10 रुपये और उड़द दाल की आठ रुपये प्रति क्विंटल गिर गयी।मलेशिया के बुरसा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज में नवंबर का पाम ऑयल वायदा 77 रिंगिट चढ़कर 4,971 रिंगिट प्रति टन पर रहा। दिसंबर का अमेरिकी सोया तेल वायदा 1.83 प्रतिशत चढ़कर 72.42 सेंट प्रति पौंड के भाव बोला गया।

शेयर बाजारों में बिकवाली

निफ्टी-50 पांच सप्ताह के निचले स्तर पर

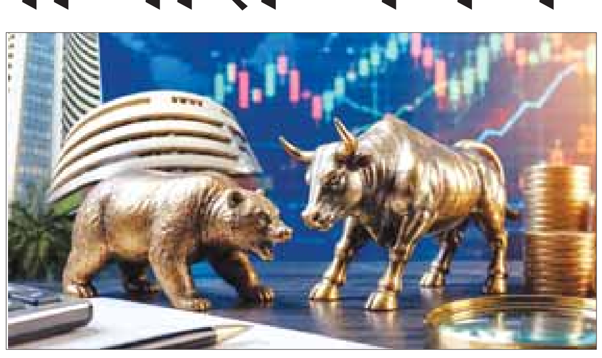

मुंबई। विदेशों से मिले नकारात्मक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में मंगलवार को बिकवाली का जोर रहा और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी-50 सूचकांक पांच सप्ताह के निचले स्तर पर बंद हुआ।प्रमुख सूचकांकों में दिन भर काफी उतार-चढ़ाव देखा गया।सेंसेक्स 37 अंक की तेजी में 76,994 अंक पर खुलने के बाद ऊपर 77,231 अंक और नीचे 76,656 अंक तक गया।अंत में 12.99 अंक (0.02 प्रतिशत) टूटकर 76,944.28 अंक पर बंद हुआ।यह 27 अगस्त के बाद का इसका निचला स्तर है।निफ्टी-50 का ग्राफ भी कमोबेश ऐसा ही रहा।कारोबार की समाप्ति पर सूचकांक 24.60 अंक यानी 0.10 प्रतिशत उतरकर 24,055.80 अंक पर रहा।यह 28 जुलाई के बाद का इसका निचला बंद स्तर है। आईटीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज और भारती एयरटेल जैसी दिग्गज कंपनियों में लिवाली के दम पर दोनों प्रमुख सूचकांक बड़ी गिरावट से बचे रहे।वहीं, वृहत बाजार में बिकवाली का दबाव ज्यादा रहा।निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 1.31 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 0.23 प्रतिशत टूट गया।वैश्विक स्तर पर लगभग सभी प्रमुख शेयर बाजार लाल निशान में रहे।जापान तथा कई अन्य देशों में बॉन्ड पर मिलने वाला रिटर्न तेजी से बढ़ने से शेयर बाजार दबाव में हैं।घरेलू स्तर पर सेक्टर आधारित सूचकांकों में आईटी, एफएमसीजी, तेल एवं गैस और मीडिया में तेजी रही।बैंकिंग, वित्त, ऑटो, फार्मा, स्वास्थ्य और टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद समूहों में बिकवाली हावी रही। एनएसई में जिन 3,649 कंपनियों के शेयरों में कारोबार हुआ उनमें 2,194 के शेयर लाल निशान में और 1,344 के हरे निशान में रहे। अन्य 111 कंपनियों के शेयर अंततः अपरिवर्तित बंद हुए।सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से 17 के शेयरों में गिरावट रही।मारुति सुजुकी का शेयर 4.16 प्रतिशत लुढ़क गया। भारतीय स्टेट बैंक का शेयर 2.51 प्रतिशत, इंडिगो का 2.48, बजाज फिनसर्व का 2.40 और महिंद्रा एंड महिंद्रा का 2.36 प्रतिशत नीचे बंद हुआ।एक्सिस बैंक में 1.80 प्रतिशत, टाइटन में 1.58, सन फार्मा में 1.31, बजाज फाइनेंस में 1.09, ट्रेंट में 1.03, एलएंडटी में 0.99 और आईसीआईसीआई बैंक में 0.91 प्रतिशत की गिरावट रही।अल्ट्राटेक सीमेंट, बीईएल और एशियन पेंट्स के शेयर भी नीचे बंद हुए। आईटीसी में सबसे अधिक 3.98 प्रतिशत की तेजी देखी गयी।एचसीएल टेक्नोलॉजीज का शेयर 3.21 प्रतिशत, इंफोसिस का 2.44 और भारती एयरटेल का 2.30 प्रतिशत चढ़ा।

रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 1.74 प्रतिशत और कोटक महिंद्रा बैंक का 1.54 प्रतिशत मजबूत हुआ।अडानी पोर्ट्स, टेक महिंद्रा और एचडीएफसी बैंक के शेयर भी ऊपर रहे।वैश्विक स्तर पर एशिया में हांगकांग का हैंग सेंग 0.93 फीसदी, चीन का शंघाई कंपोजिट 0.16 फीसदी और जापान का निक्केई 0.15 प्रतिशत टूट गया।यूरोपीय बाजारों में शुरुआती कारोबार में जर्मनी का डैक्स 0.92 फीसदी और ब्रिटेन का एफटीएसई 0.55 फीसदी फिसल गया।

अकासा एयर की पेडे सेल, किराये में 20 प्रतिशत तक की छूट

नयी दिल्ली। नवोदित विमान सेवा कंपनी अकासा एयर ने पेडे सेल की घोषणा की है जिसके तहत यात्रियों को मूल किराये में 20 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। एयरलाइंस ने मंगलवार को बताया कि ग्राहक 06 सितंबर की रात 11.59 बजे तक ऑफर के तहत बुकिंग करा सकेंगे।बुकिंग यात्रा से कम से कम सात दिन पहले करानी होगी।ऑफर के तहत ग्राहक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों नेटवर्कों पर लाभ ले सकेंगे।साथ ही, सीट चयन पर भी छूट का लाभ उठा सकते हैं। ऑफर का लाभ लेने के लिए बुकिंग अकासा एयर की वेबसाइट और उसके मोबाइल ऐप के माध्यम से ही की जा सकती है। सेवर और फ्लेक्सी दोनों किरायों पर यह छूट दी जा रही है।बुकिंग कराते समय प्रोमो कोड पेडे का इस्तेमाल करना होगा।ग्राहक इस ऑफर का लाभ वन-वे और राउंड-ट्रिप दोनों प्रकार की बुकिंग पर उठा सकते हैं।इस बीच कंपनी के बेड़े में आज एक 42वां विमान शामिल हुआ।इस साल अब तक उसके बेड़े में 11 नये विमान आ चुके हैं।पंजीकरण संख्या वीटी-वाईबीएस के साथ बोइंग 737 मैक्स 8-200 विमान नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा।एयरलाइंस ने 226 बोइंग 737 मैक्स विमानों के लिए पक्के ऑर्डर दिये हैं जिनमें 42 विमानों की आपूर्ति हो चुकी है और 184 पाइपलाइन में हैं।

सफलता में रहें विनम्र और असफलता से सीखकर आगे बढ़ें विद्यार्थीः मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने लगभग 1.22 लाख विद्यार्थियों के खातों में लैपटॉप के लिए 304.98 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सिंगल क्लिक से की अंतरित

भोपाल (स्वतंत्र मत)

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि विद्यार्थी की वास्तविक सफलता केवल अच्छे अंक अथवा प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में नहीं, बल्कि उसके संस्कार, विनम्रता, अनुशासन और व्यक्तित्व में निहित होती है। विद्यार्थी सफलता से उत्साहित हों, लेकिन अपने भीतर अहंकार नहीं आने दें। असफलता से निराश होने के बजाय उसके कारणों को समझें और उससे सीख लेकर भविष्य को बेहतर बनाएँ। मैदान में उतरने वाला खिलाड़ी ही कभी हारता और कभी जीतता है। जीतने का सपना देखने और चुनौतियों का सामना करने का साहस रखने वाला ही सच्चा खिलाड़ी कहलाता है। संघर्षों से बचने वाले जीवन में कभी सफल नहीं होते। जीवन में कठिनाइयों और चुनौतियों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। सफलता संघर्ष, धैर्य और दृढ़ संकल्प से प्राप्त होती है। परमात्मा ने प्रत्येक व्यक्ति को सीमित और मूल्यवान समय दिया है। विद्यार्थी इसका सदुपयोग करते हुए पूरी ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। आज किया गया परिश्रम ही कल की बड़ी सफलता का आधार बनेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित राज्य स्तरीय 'प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना' के राशि अंतरण कार्यक्रम को

संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश के लगभग एक लाख 22 हजार मेधावी विद्यार्थियों के बैंक खातों में लैपटॉप खरीदने के लिए 304 करोड़ 98 लाख 50 हजार रुपये से अधिक की राशि अंतरित की। प्रत्येक पात्र विद्यार्थी को 25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 12वीं की परीक्षा में प्रथम प्रयास में 75 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

लैपटॉप ज्ञान और संभावनाओं का प्रवेश-द्वार

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विद्यार्थियों से कहा कि लैपटॉप केवल एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं, बल्कि ज्ञान, अनुसंधान, नवाचार और भविष्य की नई संभावनाओं का प्रवेश-द्वार है। विद्यार्थी इसका उपयोग ऑनलाइन अध्ययन, डिजिटल पाठ्य सामग्री, ई-लाइब्रेरी, शोध तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए करें। तकनीक के माध्यम से अपने ज्ञान का विस्तार करते हुए विद्यार्थी अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी के भीतर कोई न कोई विशिष्ट प्रतिभा अवश्य होती है। जिस प्रकार मूर्तिकार पत्थर के भीतर छिपी मूर्ति को पहचानकर अनावश्यक हिस्सों को हटाता है, उसी प्रकार शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा को पहचानकर उनके व्यक्तित्व को तराशते हैं। विद्यार्थियों की सफलता में उनके माता-पिता और शिक्षकों के त्याग, परिश्रम एवं मार्गदर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों ने बढ़ाया प्रदेश का गौरव

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश के शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थी निरंतर उल्लेखनीय उपलब्धियाँ अर्जित कर रहे हैं। मेरिट सूची में शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की बढ़ती भागीदारी शिक्षकों की मेहनत और शिक्षा व्यवस्था में हो रहे सकारात्मक परिवर्तन का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों को पाठ्य-पुस्तक, गणवेश, साइकिल, स्कूटी, छात्रवृत्ति और लैपटॉप जैसी सुविधाएँ उपलब्ध करा रही है। सरकार का प्रयास है कि आर्थिक अभाव किसी भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी के सपनों की राह में बाधा न बने। प्रदेश का प्रत्येक बच्चा अपनी योग्यता के आधार पर डॉक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता, वैज्ञानिक, अधिकारी, उद्यमी अथवा अपनी पसंद के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़े।

शिक्षा के लिए बजट में व्यापक प्रावधान

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा को प्रदेश के भविष्य में निवेश मानती है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 36 हजार 730 करोड़ रुपये, उच्च शिक्षा विभाग के लिए 4 हजार 247 करोड़ रुपये तथा तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के लिए 2 हजार 932 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में स्कूल, महाविद्यालय, तकनीकी शिक्षण संस्थान और चिकित्सा महाविद्यालयों का विस्तार किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सा शिक्षा की सीटों में निरंतर वृद्धि से प्रदेश के विद्यार्थियों को अपने ही राज्य में चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने के अधिक अवसर मिल रहे हैं। युवाओं के लिए शासकीय भर्तियों की प्रक्रिया भी निरंतर और पारदर्शी रूप से संचालित की जा रही है।

शिक्षा और विद्यार्थियों को सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पूर्ववर्ती सरकारों का उल्लेख करते हुए कहा कि उस दौर में प्रदेश में शिक्षण संस्थानों और विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध अवसरों का अपेक्षित विस्तार नहीं हो सका। वर्तमान राज्य सरकार ने विद्यालयी शिक्षा से लेकर उच्च, तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा तक अधोसंरचना, बजट तथा संस्थानों का व्यापक विस्तार किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विश्व में भारत का मान-सम्मान निरंतर बढ़ रहा है। देश की युवा शक्ति, लोकतांत्रिक व्यवस्था और सशक्त नेतृत्व ने भारत के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं। मध्यप्रदेश सरकार भी शिक्षा, कौशल, तकनीक और रोजगार को युवा भविष्य के निर्माण का आधार बनाकर कार्य कर रही है।

युवा अपनी जिज्ञासा, परिश्रम और नवाचार से विकसित भारत की दिशा तय करेंगे : मंत्री परमार

आईआईआईटी भोपाल के 'दीक्षारंभ-2026' में नवप्रवेशित विद्यार्थियों को देश निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का किया आह्वान

भोपाल (स्वतंत्र मत)

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इन्दर सिंह परमार ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति और संपदा हैं। उनकी जिज्ञासा, ज्ञान, परिश्रम, अनुसंधान एवं नवाचार की क्षमता ही भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। वर्ष 2047 में जब भारत अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी पूर्ण करेगा, तब भारत कैसा होगा, यह आज की युवा पीढ़ी के ज्ञान, परिश्रम और संकल्प से तय होगा। उन्होंने विद्यार्थियों से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। मंत्री श्री परमार मंगलवार को भोपाल स्थित रविन्द्र भवन के हंसध्वनि सभागृह में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) भोपाल में नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए आयोजित अभिमुखीकरण समारोह-2026 'दीक्षारंभ' के उद्घाटन सत्र में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आईआईआईटी भोपाल में चयनित सभी नवप्रवेशित विद्यार्थियों को बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। मंत्री श्री परमार ने विद्यार्थियों से कहा कि उनके मन में निरंतर जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए। जिज्ञासा ही ज्ञान की पहली सीढ़ी है और ज्ञान को अनुसंधान एवं नवाचार से जोड़कर ही देश की समस्याओं के प्रभावी समाधान खोजे जा सकते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों का आह्वान किया कि वे केवल ज्ञान अर्जित करने तक

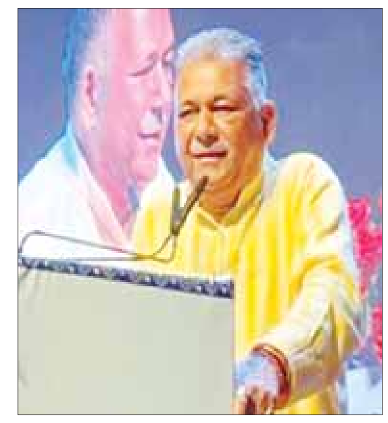

सीमित न रहें, बल्कि अपनी प्रतिभा और तकनीकी दक्षता का उपयोग समाज एवं राष्ट्र के विकास के लिए करें।

मंत्री श्री परमार ने कहा कि तकनीक तेजी से बदल रही है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आने वाले समय में शिक्षा, रोजगार, उद्योग और समाज के अनेक क्षेत्रों को प्रभावित करेगी। विद्यार्थियों को इन परिवर्तनों को समझते हुए तकनीकी ज्ञान एवं नवाचार के क्षेत्र में स्वयं को निरंतर तैयार करना होगा। आईआईआईटी भोपाल विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक, अनुसंधान और नवाचार का उत्कृष्ट अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

2047 का भारत आज की युवा पीढ़ी तय करेगी

मंत्री श्री परमार ने कहा कि स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण होने पर वर्ष 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में विश्व के सामने खड़ा हो - इसके लिए आज से ही मजबूत आधार तैयार करना होगा। आज की युवा पीढ़ी ही 2047 के भारत का निर्माण करेगी। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल प्रतिभा ही नहीं, बल्कि परिश्रम, अनुशासन, जिम्मेदारी, संस्कार और कर्तव्यबोध भी आवश्यक हैं। मंत्री श्री परमार ने विद्यार्थियों से कहा कि वे ऐसे नागरिक बनें, जिनके ज्ञान और आचरण से देश का सम्मान बढ़े। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में विश्व पटल पर भारत का सम्मान और प्रतिष्ठा और अधिक बढ़े, इसकी जिम्मेदारी युवा पीढ़ी के कंधों पर है। विद्यार्थियों का प्रत्येक सकारात्मक प्रयास राष्ट्र की प्रगति में योगदान देगा।

भाषाएं जोड़ने का माध्यम हैं, तोड़ने का नहीं

मंत्री श्री परमार ने भाषा की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भाषा लोगों को जोड़ने का माध्यम है, तोड़ने का नहीं। भारत की भाषाई विविधता हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। उन्होंने विद्यार्थियों को विभिन्न भारतीय भाषाएं सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में आने वाले समय में विभिन्न भाषाओं के अध्ययन और शिक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे विद्यार्थी देश की विविध भाषाई एवं सांस्कृतिक परंपराओं से परिचित हो सकें। इस अनुक्रम में प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में विविध भारतीय भाषाओं को क्रेडिट से जोड़कर सिखाने की कार्ययोजना पर कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप शिक्षा को ज्ञान, कौशल, अनुसंधान, नवाचार और भारतीय भाषाओं से जोड़ते हुए विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है।

तेवरईया के दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर में 32 वें वर्ष में शुरू हुआ अखंड रामचरितमानस का पाठ

भाद्रपद मास में एक माह तक गूंजेगी श्रीरामचरितमानस की चौपाइयां

हटा (स्वतंत्र मत)। समीपवर्ती ग्राम तेवरईया के श्री श्री 108 श्री दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर में भाद्रपद मास के पावन अवसर पर श्रीरामचरितमानस का एक मासीय सामूहिक अखंड पाठ का शुभारंभ किया गया। यह धार्मिक आयोजन अपनी निरंतरता के 32 में वर्ष में प्रवेश कर रहा है। मंगलवार को वैदिक विधिविधान मंत्रोचार एवं श्रद्धामय वातावरण में मंदिर के पुजारी गौरीशंकर तिवारी ने विधिवत पूजन अर्चन कर अखंड पाठ का शुभारंभ कराया। आयोजन के प्रारंभ में भगवान श्री गणेश श्रीराम दरबार एवं हनुमान जी का पूजन किया गया। वैदिक मंत्रो और मंगलाचरण के साथ मानस पोथी का पूजन कर श्रद्धालुओं ने संकल्प लिया पूरे भाद्रपद माह में श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ निरंतर चलता रहेगा। मानस मंडल के सदस्यों सहित समस्त ग्रामवासी श्रद्धापूर्वक इस आयोजन में सहभागिता कर रहे हैं । इस परंपरा का 32 वर्षो तक चलते रहना ग्रामवासियों की आस्थाए एकता और धार्मिक चेतना का प्रतीक है। बदलते समय में जहां आपाधापी बढ़ रही है। वहीं ऐसे सामूहिक धार्मिक आयोजन लोगों को अपनी संस्कृति और संस्कारों से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। विशेष रूप से नई पीढ़ी को श्रीराम के आदर्श, माता-पिता के प्रति सम्मान, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा तथा समाज के प्रति कर्तव्य पालन का संदेश मानस के माध्यम से सहज में ही मिल जाता है। रामचरितमानस का उक्त महात्म्य बताकर श्री तिवारी जी ने सभी श्रद्धालुओं, ग्रामवासियों एवं क्षेत्रीय ग्रामवासियों से समय निकालकर मानस पाठ में सहभागी बनने एक मासीय मानस पाठ को सफल बनाने का आव्हान किया।

सड़कें दुरूस्त रहे, लापरवाही बर्दास्त नहीं : कलेक्टर

दमोह (स्वतंत्र मत)। कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने समय सीमा बैठक में सड़क निर्माण के विभागीय अधिकारियों से कहा है सड़कें दुरूस्त रहे। इसमें लापरवाही कतई बर्दास्त नही की जायेगी। उन्होने कहा सड़कों का जहां भी सुधार मरम्मत आवश्यक हो कराई जायेंए अन्यथा कड़ी कार्रवाही की जायेगी। इस आशय के निर्देश कलेक्टर श्री यादव ने समय सीमा बैठक के दौरान सड़क निर्माण विभागीय अधिकारियों को दिए। उन्होंने इस दौरान सड़कों की चर्चा करते हुए अप्रसन्नता भी जाहिर की। कलेक्टर ने कहा लोकपथ एप में जानकारी आमजनो द्वारा डाली जा रही है, विभागीय सड़कें मैप आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें।

जांच रिपोर्ट के आधार पर सचिव पर निलंबन की कार्रवाई

हटा (स्वतंत्र मत)। ग्राम पंचायत रनेह में प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े मामले में जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला पंचायत दमोह ने तत्कालीन सचिव परसराम पटेल के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा 25 अगस्त को जारी आदेश में उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। आदेश के अनुसार लोकायुक्त कार्यालय से प्राप्त शिकायत की जांच के लिए गठित समिति ने 25 अगस्त को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। जांच में तत्कालीन सचिव पर आरोप है कि ग्राम पंचायत रनेह में पदस्थापना के दौरान वास्तविक आवास हितग्राहियों के स्थान पर अन्य हितग्राहियों के खातों में राशि का गबन किया गया। इसके अलावा अपात्र हितग्राहियों को आवास का लाभ देने तथा ग्राम से अन्यत्र निवासरत/पलायन कर चुके हितग्राहियों के नाम पर भी आवास का लाभ दिए जाने की बात जांच में सामने आई। जांच प्रतिवेदन के आधार पर परसराम पटेल के विरुद्ध मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए 14 लाख 90 हजार रुपये की राशि वसूली का नोटिस भी जारी किया गया है।

श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन 30 सितंबर से

दमोह (स्वतंत्र मत)। पितृपक्ष के पावन अवसर पर पितरों के निमित्त श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन श्री शिव साईं मंदिर बेलाताल टापू दमोह में किया जा रहा है। आयोजन 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक चलेगा। कथा का वाचन पं. कमलेश्वरानंद महाराज द्वारा किया जाएगा। कथा प्रतिदिन धार्मिक एवं आध्यात्मिक वातावरण में आयोजित होगी। आयोजन समिति के अनुसार पितरों की शांति एवं मोक्ष की कामना से श्रद्धालु बड़ी संख्या में कथा में शामिल होंगे।

रास्ते के लिए दो गांवों के ग्रामीण पहुंचे तहसील समाधान नहीं तो आंदोलन की चेतावनी

हटा (स्वतंत्र मत)

ग्राम बोरीखुर्द एवं बोरीकलां के ग्रामीणों ने आवागमन के लिए आम रास्ता निर्माण की मांग को लेकर तहसीलदार आलोक श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने समस्या का शीघ्र समाधान नहीं होने पर जन आंदोलन करने की चेतावनी दी है। ग्रामीणों का कहना है कि बोरीकलां एवं बोरीखुर्द की सीमा से लगे क्षेत्र में आमजन के आवागमन के लिए उचित रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं होने के कारण छात्र-छात्राओं को स्कूल आने.जाने में परेशानी होती है। वहीं बीमारी अथवा आपात स्थिति में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में भी ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि वे हटा-पटेरा मुख्य मार्ग से जमराज घाट तकए बोरीखुर्द एवं बोरीकलां की मेड़ों से होकर आम रास्ते का निर्माण कराए जाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह समस्या लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन अब तक शासन-प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया। ग्रामीणों ने तहसीलदार से आवेदन पर मौके की जांच कराकर दोनों गांवों के आमजन के लिए रास्ते की व्यवस्था कराने की मांग की। साथ ही कहा कि यदि जल्द समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे जिसकी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। ज्ञापन सौंपने वालों में बोरीकलां सरपंच रामचरण पटेल, सीताराम पटेल, गोविंद, इमरत परम, भागीरथ और हेमंत सहित दो दर्जन से अधिक ग्रामीण मौजूद रहे। मामले को गंभीरता से लेते हुए तहसीलदार आलोक श्रीवास्तव ने तत्काल आरआई और पटवारी को मौके पर भेजकर वास्तविक स्थिति की जानकारी लेने के निर्देश दिए।

नाम सुधार सूचना

मैं, चिराग पगारिया, पिता- धर्मेन्द्र पगारिया, निवासी-44, महावीर कम्पाउण्ड, केन्ट, जबलपुर (म.प्र.), ये कथन करता हूँ कि, मेरे पूर्व पासपोर्ट संख्या J3030454 भोपाल से जारी हुआ था। जिसमे मेरे तथा माता-पिता के सरनेम की स्पेलिंग PAGARIYA लिखी है, जो गलत है। मेरे सभी शासकीय दस्तावेज आधार कार्ड, पेन कार्ड मार्कशीट आदि में सरनेम PAGARIA है जो सही है। अतः अबसे मुझे इसी नाम सरनेम से जाना पहचाना जावे।

गलत नाम- चिराग पगारिया (CHIRAG PAGARIYA)
सही नाम- चिराग पगारिया (CHIRAG PAGARIA)

छात्रावासों में शीघ्र प्रारंभ होगा मेस संचालन

राज्यमंत्री कृष्णा गौर ने मंत्रालय में की विभागीय समीक्षा बैठक

भोपाल (स्वतंत्र मत)। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने मंगलवार को मंत्रालय में विभागीय योजनाओं एवं विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में विद्यार्थियों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए राज्य मंत्री श्रीमती गौर ने निर्देश दिए कि पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिये संचालित 106 छात्रावासों में आगामी 8 सितंबर से मेस का संचालन अनिवार्य रूप से प्रारंभ

किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को पौष्टिक एवं उच्च गुणवत्तायुक्त भोजन समय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, इसमें किसी भी स्तर पर शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने के इच्छुक प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए राज्य मंत्री श्रीमती गौर ने विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना के पोर्टल को पूरे वर्ष संचालित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवेदन प्रक्रिया को सुगम और निरंतर बनाए रखने के लिए पोर्टल बंद नहीं होना चाहिए। चयन प्रक्रिया को तीव्र गति देने के उद्देश्य से उन्होंने व्यवस्था बनाई कि प्रत्येक तीन माह (त्रैमासिक) में अथवा न्यूनतम 25 आवेदन प्राप्त होते ही समिति की बैठक आयोजित कर अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लिए जाएं, जिससे पात्र विद्यार्थियों को समय पर योजना का लाभ मिल सके।

समस्त विभागीय कार्य समय-सीमा में पूर्ण करने के दिये निर्देश- राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती गौर ने विभागीय अधिकारियों को कार्य-संस्कृति में गतिशीलता लाने तथा शासन की समस्त योजनाओं के क्रियान्वयन को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का वास्तविक लाभ अंतिम छोर पर खड़े हितग्राही तक पारदर्शी एवं त्वरित रूप से प्राप्त होना आवश्यक है। बैठक में सचिव अनुराग चौधरी, आयुक्त सतेन्द्र सिंह, आरके यादव सलाहकार एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल
भेड़ाघाट रोड, धनवंतरी नगर, जबलपुर म.प्र. पिन-482003

भवन नामांतरण/हस्तांतरण हेतु सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि धनवंतरी नगर जबलपुर में स्थित भवन क्रमांक Jr MIG 96 श्री सुरेन्द्र मिश्रा पिता श्री आर.जे. मिश्रा के नाम आवंटित है, जिसका विक्रय विलेख दिनांक 20.07.2010 को आवंटी के पक्ष में निष्पादित हो चुका है। उक्त भवन श्री सुरेन्द्र मिश्रा पिता श्री आर.जे मिश्रा ने पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 28.09.2021 के माध्यम से श्री शरद कुमार दुबे पिता स्व. श्री इमरत लाल दुबे एवं श्रीमती मंजू दुबे पिता श्री शरद कुमार दुबे को विक्रय किया है। अतः श्री शरद कुमार दुबे पिता स्व. श्री इमरत लाल दुबे एवं श्रीमती मंजू दुबे पिता श्री शरद कुमार दुबे द्वारा उक्त भवन उनके नाम लीज हस्तांतरण हेतु दस्तावेज/आवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किये गये हैं। यदि किसी व्यक्ति, संस्था आदि को उपरोक्त लीज हस्तांतरण (भवन/भूखण्ड) बाबत् आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने से 15 दिवस के अंदर लिखित में वैद्य आपत्ति सप्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात् हस्तांतरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। जिस पर किसी की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

संपदा अधिकारी म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, प्रक्षेत्र जबलपुर

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल
भेड़ाघाट रोड, धनवंतरी नगर, जबलपुर म.प्र. पिन-482003

भवन लीज हस्तांतरण/नामांतरण हेतु सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मदर टेरेसा कॉलोनी जबलपुर में भवन क्रमाक Jr. LIG 469 श्री रवि कुमार साहू पिता श्री धनीराम साहू के नाम आवंटित है. जिसका विक्रय विलेख दिनांक 03.11.2012 को आवंटी के पक्ष में निष्पादित हो चुका है। उक्त भवन श्री रवि कुमार साहू पिता श्री धनीराम साहू ने पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 16.01 2024 के माध्यम से सुश्री पलक साहू पिता श्री अरुण साहू को विक्रय किया है। अतः सुश्री पलक साहू पिता श्री अरुण साहू द्वारा उक्त भवन उनके नाम लीज हस्तांतरण हेतु दस्तावेज / आवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किये गये हैं। यदि किसी व्यक्ति, सस्था आदि को उपरोक्त लीज हस्तांतरण भूखण्ड बाबत् आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने से 15 दिवस के अंदर लिखित में वैद्य आपत्ति सप्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात् हस्तातरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। जिस पर किसी की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

संपदा अधिकारी म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, प्रक्षेत्र जबलपुर

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल
भेड़ाघाट रोड, धनवंतरी नगर, जबलपुर म.प्र. पिन-482003

भूखंण्ड लीज नामांतरण/हस्तांतरण हेतु सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पी.पी. कालोनी जबलपुर में स्थित भवन क्रमांक एमआईजी-24 श्री युगल चैनानी पिता/पति श्री प्रदीप चैनानी के नाम आवंटित है जिसका विक्रय विलेख दिनांक 27.03.2023 को आवंटी के पक्ष में निष्पादित हो चुका है। उक्त क्रमांक एमआईजी-24 श्री युगल चैनानी पिता/पति श्री प्रदीप चैनानी ने विक्रय विलेख दिनांक 15.06 2026 के माध्यम से श्रीमति रश्मि नागदेव पति स्व. श्री राजकुमार नागदेव एवं श्री यश नागदेव पिता स्व. श्री राजकुमार नागदेव को विक्रय किया है। श्रीमति रश्मि नागदेव पति स्व.श्री राजकुमार नागदेव एवं श्री यश नागदेव पिता स्व.श्री राजकुमार नागदेव के द्वारा उक्त भवन क्रमांक एम.आई.जी.-24 उनके नाम लीज हस्तांतरण /नामांतरण हेतु दस्तावेज/आवेदन इस कार्यालय में पस्तुत किये हैं। यदि किसी व्यक्ति /संस्था को उपरोक्त लीज हस्तांतरण/ नामांतरण बाबत् आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने से 15 दिवस के अंदर लिखित एव वैद्य आपत्ति सप्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि उपरांत हस्तांतरण / नामाकरण की कार्यवाही को जावेगी एवं भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति दावा मान्य नहीं होगा।

संपदा अधिकारी म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, प्रक्षेत्र जबलपुर

आम सूचना

यह सूचित किया जाता है कि Cobra Fitness Complex के प्रांगण में दिनांक 03 sep 2026 को सुबह 10 बजे विभिन्न ग्रान्ट्स के सामानों की नीलामी की जायेगी।

अतः इच्छुक व्यक्ति इस नीलामी हेतु अपना नाम QM OFFICE 2TTR (1 STC) में दिनांक 02 sep 2026 शाम 8.00 बजे तक दर्ज कराने का कष्ट करें।

नोट - नीलामी हुई सभी वस्तु उसी दिन अर्थात 03 sep 2026 को ही उठाना होगा और नीलामी की राशि उसी दिन जमा करना अनिवार्य है।

Quarter master 2TTR (1 STC)

जिले के 3,319 विद्यार्थियों के हाथों में होगा लैपटॉप

मेधावी छात्रों के खातों में पहुंची 25 हजार की राशि

जबलपुर (स्वतंत्र मत)। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा लैपटॉप वितरण योजना के अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में 25-25 हजार रुपये की राशि अंतरित की गई है। इस राशि का उपयोग विद्यार्थी लैपटॉप खरीदने के लिए कर सकेंगे। इस योजना के तहत जबलपुर जिले के कुल 3,319 विद्यार्थियों को लाभ मिला है। जबलपुर के 2 मेधावी विद्यार्थियों ओम चौकसे और शिवांगी नागदेव को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लैपटॉप प्रदान किए गए। कार्यक्रम में महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, विधायक अशोक रोहाणी, डॉ अभिलाष पांडे, नगर निगम अध्यक्ष रिकुंज विज, संयुक्त संचालक घनश्याम सोनी आदि उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने सुनी आमजन की समस्याएं, दिए निर्देश

कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचे 94 आवेदन

जबलपुर (स्वतंत्र मत)। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में नागरिकों की समस्याएं सुनीं और संबंधित विभागों के अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। साप्ताहिक जनसुनवाई में नागरिकों से कुल 94 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें 34 दोबारा आए आवेदन भी शामिल थे। जनसुनवाई में आए आवेदनों में अतिक्रमण, सीमांकन, राजस्व प्रकरण, टीसी नहीं मिलने, पेंशन, धान का भुगतान, नामांतरण, आयुष्मान कार्ड बनवाने, कब्जा, पानी नाली से संबंधित शिकायतें, आपसी विवाद, आर्थिक सहायता तथा भूमि डायवर्सन से संबंधित रहे।

बिजली कटौती और स्मार्ट मीटर के विरोध में कांग्रेसियों ने घेरा एसई कार्यालय

कांग्रेस पार्षदों के वार्डों में जानबूझकर ट्रांसफार्मर बंद रखने का आरोप, दी चेतावनी

जबलपुर (स्वतंत्र मत)

बिजली कटौती और स्मार्ट मीटर के विरोध में मंगलवार को कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ताओं द्वारा जिला कांग्रेस अध्यक्ष शहर सौरभ नाटी शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता अधीक्षण अभियंता (एसई) कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा ने आरोप लगाया कि मंगलवार सुबह लगभग 9 बजे से शहर के लगभग 35 ट्रांसफार्मरों की बिजली आपूर्ति बंद रही। इसके कारण कई क्षेत्रों में घंटों तक बिजली गुल रही और कुछ इलाकों में आपूर्ति सुचारु नहीं हो सकी। कांग्रेस ने दावा किया कि इस अव्यवस्था से लगभग 40 हजार बिजली उपभोक्ता भीषण गर्मी और उमस के बीच परेशान हुए। सौरभ नाटी शर्मा ने कहा कि जनता नियमित रूप से बिजली के बिलों का भुगतान करती है, इसके बावजूद उसे घंटों बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि उपभोक्ता समय पर बिल जमा नहीं करता तो विभाग कनेक्शन काट देता है, लेकिन लंबे समय तक बिजली आपूर्ति बाधित रहने पर विभाग की जवाबदेही कौन तय करेगा।

रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की माँग

इस दौरान कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। श्री शर्मा ने कहा कि उपभोक्ताओं पर स्मार्ट मीटर लगाने का दबाव बनाने और 300 यूनिट की औसत खपत के आधार पर बिल जारी किए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं, जबकि वास्तविक खपत इससे अलग होती है। इसके अलावा स्मार्ट मीटर की लाइन काटने के नाम पर बिजली बिल में 340 रुपए की राशि जोड़ने को लेकर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस ने बिजली विभाग से स्पष्ट करने की मांग की कि यह राशि किस नियम के तहत वसूली जा रही है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्षदों के वार्डों में अधिक संख्या में ट्रांसफार्मर बंद होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। उन्होंने बिजली विभाग से मांग की कि किस वार्ड में कितने ट्रांसफार्मर बंद हैं और किन क्षेत्रों में कितने समय तक बिजली बाधित रही, इसका पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक किया जाए।

व्यापक आंदोलन की चेतावनी

उन्होंने कहा कि बिजली जैसी मूलभूत सुविधा में यदि राजनीतिक भेदभाव किया जा रहा है तो यह गंभीर मामला है। ट्रांसफार्मर किसी राजनीतिक दल का नहीं होता और जनता को भी राजनीतिक दल देखकर बिजली नहीं दी जा सकती। सौरभ नाटी शर्मा ने चेतावनी दी कि यदि बिजली विभाग ने व्यवस्था में सुधार नहीं किया और उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान नहीं किया तो कांग्रेस आंदोलन को और व्यापक करेगी। प्रदर्शन के दौरान दिनेश यादव, पार्षद संतोष पंडा, सरबजीत सिंह, मनीष चंसोरिया, रितेश बंटी गुप्ता, आशु वत्स, अभिषेक चंदेल, रिंकू यादव, मेवा लाल पटेल, समर्थ अवस्थी, आसिफ इकबाल, सिद्धांत जैन, प्रमोद पटेल, सलिल चौकसे, अभिषेक पाठक, सतीश तिवारी, गुड्डू नबी, अयोध्या तिवारी आदि मौजूद रहे।

बुंदेली संस्कृति के संरक्षक थे डॉ. पूरनचंद श्रीवास्तव

स्मृति जन्मोत्सव पर हुआ बुंदेली दिवस का आयोजन

जबलपुर (स्वतंत्र मत)

बुंदेलखंड के समृद्ध लोक साहित्य, कला-संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण संवर्धन के लिए डॉ. पूरनचंद श्रीवास्तव को याद किया जाता है। जब देश में हिंदी और अंग्रेजी के बोलबाले से क्षेत्रीय भाषाएं और बोलियां विलुप्त होने लगीं तब भाषाविज्ञानी, शिक्षाविद् डॉ. श्रीवास्तव ने इनके संरक्षण का बीड़ा उठाकर इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया । उपरोक्त आशय के विचार गुंजन कला सदन और नगर की संस्थाओं द्वारा मंगलवार को शहीद स्मारक भवन में आयोजित डॉ. पूरनचंद श्रीवास्तव की 110वीं जयंती बुंदेली दिवस पर अतिथि वक्ताओं ने व्यक्त किए । सभी ने डॉ. श्रीवास्तव के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की । कार्यक्रम का संचालन राजेश पाठक प्रवीण एवं आभार प्रदर्शन विक्रम परवार ने किया ।

सम्मानित हुई विभूतियां

आयोजन में जयेश सिंह राठौर (अधिवक्ता एवं समाजसेवी) को सम्मानित किया गया। श्री राठौर अर्थशास्त्र व विधि में स्नातक, इतिहास में स्नातकोत्तर होने के साथ ही आपने मानवाधिकार, ग्राम विकास एवं उपभोक्ताओं संबंधी अध्ययन भी किया है। हार नहीं मानूँगा, रार नहीं ठानूँगा को नीति बनाकर आप पीड़ितों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से सफलतापूर्वक वकालत कर रहे हैं। हितकारिणी विधि महाविद्यालय में छात्रसंघ अध्यक्ष रहे। आप अच्छे एथलीट, तीरंदाज, हॉकी व क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं। हितकारिणी सभा सहित अनेक संस्थाओं में विभिन्न पदों पर रहते हुए जनहित में कार्य करते रहे हैं। इस अवसर पर विधायक अजय विश्नोई, पूर्व विधायक पं. नित्यनिरंजन खम्परिया आदि उपस्थित रहे।

गांवों को विवाद विहीन बनाने मीडिएशन प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत

जबलपुर (स्वतंत्र मत)

गांवों को विवाद विहिन बनाने की ओर एक सार्थक कदम उठाते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति, मप्र उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक, मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायामूर्ति विवेक रूसिया के संरक्षण एवं प्रधान जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के मार्गदर्शन में सुदूर ग्रामीण अंचलों से चयनित समाजसेवियों एवं ऊर्जावान व्यक्तियों का चयन कर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 01 सितम्बर से 03 सितम्बर तक 20 घंटे का सामुदायिक मीडिएशन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम जबलपुर शहर के स्पोर्ट्स क्लब में प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर की सदस्य सचिव सुमन श्रीवास्तव ने अपने उद्बोधन में कहा जहां एक से अधिक व्यक्ति हैं, विवादों का होना स्वाभाविक हैं। साथ ही ऐसे विवादों का समाप्त होना भी उतना ही स्वाभाविक हैं, जिसके लिए सामूदायिक मध्यस्थता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा हैं। इन प्रशिक्षणों का मूल उद्देश्य सुदूर ग्रामीण अंचलों में छोटे मोटे विवादों का सहज व व्यवहारिक तरीके से निपटान कर न्याय की पहुंच स्थापित करना है। शुभारंभ कार्यक्रम में एमसीपीसी सीनियर ट्रेनर रीमा भण्डारी, एसोसिएट ट्रेनर व सेवानिवृत्त प्रधान जिला न्यायाधीश भावना साधौ, अतिरिक्त सचिव सालसा अरविंद श्रीवास्तव, उप सचिव सालसा अनिरूद्ध जैन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की सचिव शक्ति वर्मा आदि कर्मचारी उपस्थित रहें।

7 से 12 सितंबर तक आयोजित होंगी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा

जबलपुर (स्वतंत्र मत)। मप्र लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2026 का आयोजन 7 से 12 सितंबर तक किया जाएगा। परीक्षा के लिए जिले में शासकीय मानकुंवर बाई कला एवं वाणिज्य महिला महाविद्यालय, नेपियर टाउन को केंद्र बनाया गया है। 6 दिनों तक चलने वाली यह परीक्षा ऑफलाइन माध्यम से सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होगी। इसमें 11 सितंबर को परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक एवं 12 सितंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा के निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संचालन के लिए संभाग के उप आयुक्त राजस्वह ने आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा व्यवस्था और संचालन के लिए महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ सुनीता मिश्रा को केन्द्राध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गोपनीय सामग्री को कोषालय से लाने, ले जाने तथा परीक्षा केंद्र पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए तिथिवार अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिसमें 7 एवं 8 सितंबर के लिए एकीकृत बालविकास सेवा के परियोजना अधिकारी वीकेस राय, 9 एवं 10 सितंबर के लिए सहायक क्रीडा अधिकारी भगवान सिंह दांगी और 11 एवं 12 सितंबर के लिए हिरन जल संसाधन संभाग की सहायक यंत्री अस्मिता सराफ को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा जल संसाधन मंडल के सहायक यंत्री अभिमन्यु पाण्डे तथा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के प्रबंधक बृजेश मिश्रा को रिजर्व प्राधिकृत अधिकारी बनाया गया है।

जिनसार के विद्यार्थियों ने चलाया जन जागरूकता अभियान

जबलपुर (स्वतंत्र मत)

हितकारिणी सभा द्वारा संचालित जबलपुर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेज एंड रिसर्च (जिनसार) द्वारा विक्टोरिया अस्पताल में सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विषय टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विद साइंस रहा। इस कार्यक्रम में बीएससी नर्सिंग चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया तथा समुदाय के लोगों को व्यक्तिगत स्वच्छता, संतुलित पोषण, शारीरिक गतिविधि, रोगों की रोकथाम एवं नियमित स्वास्थ्य जांच के महत्व के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की। कार्यक्रम का आयोजन संस्थान की प्राचार्य प्रो. डॉ. प्रिंसी शाजी के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम का समन्वय भानुप्रिया रजक एवं स्वप्निल मसीह द्वारा किया गया। इस जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से समुदाय में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया। साथ ही, विद्यार्थियों को स्वास्थ्य शिक्षा एवं प्रभावी संचार कौशल का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हुआ। समुदाय की सक्रिय सहभागिता के साथ कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

थर्ड लाइन कमीशनिंग कार्य के चलते जबलपुर पुणे एक्सप्रेस सहित 6 ट्रेनें रहेंगी प्रभावित

जबलपुर (स्वतंत्र मत)

मध्य रेल, पुणे मंडल के हड़पसर-पुणे रेलखंड में थर्ड लाइन कमीशनिंग कार्य के लिए पुणे एवं हड़पसर यार्ड में नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा। इस कार्य के चलते पश्चिम मध्य रेल से संबंधित कुछ रेलगाड़ियों के परिचालन में परिवर्तन किया गया है। इसके अंतर्गत 4 रेलगाड़ियां शॉर्ट टर्मिनेट/शॉर्ट ओरिजिनेट, 1 रेलगाड़ी मार्ग परिवर्तित तथा 1 रेलगाड़ी रि-शिड्यूल रहेगी। गाड़ी संख्या 20162 जबलपुर-पुणे एक्सप्रेस दिनांक 20 सितंबर को जबलपुर से प्रस्थान करने वाली यह ट्रेन अगले दिन पुणे के स्थान पर दौंड जंक्शन स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी। अर्थात दौंड जंक्शन से पुणे के मध्य यह ट्रेन आंशिक रूप से निरस्त रहेगी। गाड़ी संख्या 22172 रानी कमलापति-पुणे एक्सप्रेस दिनांक 03 अक्टूबर 2026 को रानी कमलापति से प्रस्थान करने वाली यह ट्रेन अगले दिन पुणे के स्थान पर दौंड जंक्शन स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी। अर्थात दौंड जंक्शन से पुणे के मध्य यह ट्रेन आंशिक रूप से निरस्त रहेगी।

दौंड जंक्शन से शॉर्ट ओरिजिनेट होने वाली ट्रेनें- गाड़ी संख्या 20161 पुणे-जबलपुर एक्सप्रेस दिनांक 21 सितंबर को पुणे के स्थान पर दौंड जंक्शन से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी। अर्थात पुणे से दौंड जंक्शन के मध्य यह ट्रेन आंशिक रूप से निरस्त रहेगी। गाड़ी संख्या 22171 पुणे-रानी कमलापति एक्सप्रेस दिनांक 04 अक्टूबर को पुणे के स्थान पर दौंड जंक्शन से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी। अर्थात पुणे से दौंड जंक्शन के मध्य यह ट्रेन आंशिक रूप से निरस्त रहेगी। गाड़ी संख्या 22171 पुणे-रानी कमलापति एक्सप्रेस दिनांक 20 सितंबर को पुणे से प्रारंभ होकर यह ट्रेन परिवर्तित मार्ग लोनावला-कर्जत जंक्शन-पनवेल-कल्याण-इगतपुरी-मनमाड़ होकर संचालित होगी। हड़पसर-रीवा एक्सप्रेस का हड़पसर स्टेशन पर प्रस्थान समय रि-शिड्यूल रहेगा। गाड़ी संख्या 20151 हड़पसर-रीवा एक्सप्रेस दिनांक 24 सितंबर को हड़पसर स्टेशन से अपने निर्धारित समय दोपहर 03.15 बजे के स्थान पर शाम 04 बजे, अर्थात 45 मिनट रि-शिड्यूल होकर प्रस्थान करेगी। इसी प्रकार, दिनांक 01 अक्टूबर को यह ट्रेन हड़पसर स्टेशन से अपने निर्धारित समय दोपहर 03.15 बजे के स्थान पर शाम 05 बजे, अर्थात 1 घंटे 45 मिनट रि-शिड्यूल होकर प्रस्थान करेगी।

अचानक चल पड़ा सड़क किनारे खड़ा ट्रक नीचे सो रहे चालक की दबने से हुई मौत

मदनमहल थाना क्षेत्र का मामला

ब्रेक फेल होने की आशंका

जबलपुर (स्वतंत्र मत)

फ्लाईओवर ब्रिज के पास मंगलवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एफसीआई का चावल से भरा ट्रक अचानक चल पड़ा। ट्रक के सामने बैठकर आराम कर रहा चालक और मालिक शेख इसराइल उसकी चपेट में आ गया। ट्रक से कुचलने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद ट्रक आगे जाकर दीवार से टकराकर रुका। जानकारी के मुताबिक यह घटना सुबह करीब 10 बजे की है। शेख इसराइल हनुमानताल क्षेत्र का रहने वाला था। वह ट्रक में लगभग 22 टन चावल लोड कर कहीं बाहर ले जाने की तैयारी में था। ट्रक खड़ा करने के बाद वह उसके सामने बैठकर आराम कर रहा था। इसी दौरान अचानक ट्रक चल पड़ा और वह संभल पाता, इससे पहले ही उसकी चपेट में आ गया। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने मदनमहल थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और ट्रक के नीचे फंसे शेख इसराइल के शव को बाहर निकलवाया।

दीवार से टकराने के बाद रूका ट्रक

इस मामले को लेकर एएसपी आयुष जाखड़ ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आशंका है कि ट्रक का अचानक ब्रेक फेल होने के कारण वह अपने आप चल पड़ा। हालांकि हादसे की वास्तविक वजह की जांच की जा रही है। ट्रक आगे जाकर दीवार से टकराया, जिसके बाद वह रुक गया। पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। पीएम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। एएसपी ने बताया कि ट्रक में शासकीय अनाज लोड है, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से उसे मदनमहल थाने में खड़ा कराया जा रहा है। साथ ही सड़क पर ट्रैफिक प्रभावित न हो, इसका भी ध्यान रखा गया है। कर दिया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

डिवाइडर से टकराई बाइक, युवक की मौत

सिहोरा। मझगवां थाना क्षेत्र के सिहोरा-सिलोड़ी रोड पर मंगलवार शाम कन्हाई देवरी गांव के पास मोटरसाइकिल डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में दुर्गेश दहिया की मौत हो गई, जबकि 35 सोनू बर्मन और सूरज 18 वर्षीय बर्मन गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों इमलई सिलोड़ी के निवासी बताए गए हैं। पुलिस के अनुसार तीनों युवक मोटरसाइकिल से किसी काम से मझगवां आए थे। काम पूरा करने के बाद घर लौटते समय कन्हाई देवरी के पास मोड़ पर बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दुर्गेश के सिर में गंभीर चोट आई और कुछ देर बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और सोनू व सूरज को निजी एंबुलेंस से सिहोरा अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज जबलपुर रेफर किया।

पैक्ड दूध में मिलवाट की आशंका, लिया गया सैम्पल

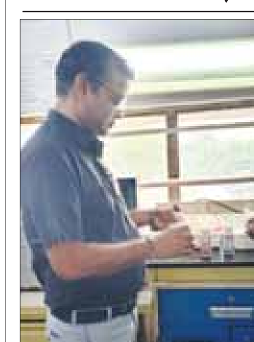

जबलपुर (स्वतंत्र मत)। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा आज सोमवार को दूध एवं दुग्ध उत्पाद की जांच हेतु विशेष अभियान चलाया गया जिसमें मिल्क टेस्टिंग किट के माध्यम से बाजार में बिक रहे खुला दूध एवं पैक्ड दूध के सैंपल लेकर जांच की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमित गुप्ता के अनुसार जांच के दौरान खुले दूध के किसी भी सैंपल में मिलावट नहीं पाई गई, किंतु पैक्ड मिल्क में आंशिक मिलावट पाये जाने पर करमेता स्थित जैन डेरी से सैंपल लेकर विस्तृत परीक्षण के लिए भोपाल भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

हितकारिणी प्रकाशन प्रायवेट लिमिटेड के लिए **प्रकाशक एवं मुद्रक- राम असरानी** द्वारा प्रेस काम्पलेक्स सिविक सेंटर जबलपुर से प्रकाशित एवं हितकारिणी प्रिंटिंग प्रेस, सिविक सेंटर जबलपुर से मुद्रित. **प्रबंध सम्पादक- सुबोध दुबे, सम्पादक- राजेन्द्र मिश्रा,** *पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयनार्थ उत्तरदायी।
ई-मेल-**smatjbp1@ gmail.com,** फोन- 0761-2411414, 4032436 समस्त विवाद जबलपुर न्यायालयाधीन. पोस्टल रजि. नं. एसएसपी जबलपुर/13/2026-28, **RNI No. 64561/96.**